चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

05 अगस्त-11 अगस्त 2013

अन्ना का राजनीतिक क़दम

सभी फोटो-प्रभात पाण्डेय

संतोष भारतीय

अन्ना हजारे देश में राजनीतिक विकल्प की बात करने लगे हैं, अन्ना हजारे ने अब यह तय कर लिया है कि वो राजनीतिक दलों के ख़िलाफ़ न केवल जन जागृति करेंगे, बल्कि लोकसभा के चुनाव के लिए ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन भी करेंगे, जिनका रिश्ता राजनीतिक दलों से नहीं है. तकनीकी तौर पर यह उम्मीदवार निर्दलीय होंगे, लेकिन अन्ना का कहना है कि इनमें से जिसे जनता खड़ा करेगी, उसे वो जनतंत्र के लिए लड़ने वाला उम्मीदवार मानेंगे. पर इसके लिए उनकी कुछ और शर्तें भी हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देखें कि अन्ना के रूख़ में परिवर्तन आया कैसे.

दरअसल अन्ना हजारे ने 2011 में जब भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ रामलीला मैदान में अनशन किया था, तब उन्हें भरोसा नहीं था कि देश की जनता भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ उनके साथ इस क़दर खड़ी हो जाएगी. अगर उन्हें भरोसा होता तो वे देश के लोगों से साथ देने की अपील करते. अन्ना ने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया और सरकार से जन-लोकपाल क़ानून बनाने की मांग की. इसके पहले अन्ना कई बार सरकार से बात-चीत कर चुके थे. मंत्रियों से उनकी बातें हो चुकी थीं. मंत्रियों ने उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में अन्ना को हर जगह से धोखा मिला और सरकार के मंत्रियों और राजनीतिक दलों ने अचानक पलटी खाई और उन्होंने अन्ना को जनलोकपाल बिल के मसले पर अकेला छोड़ दिया. अन्ना ने थक हार कर निर्णय किया कि वो आमरण अनशन करेंगे. जिस अनशन पर बैठने के लिए वो लोकनायक जयप्रकाश पार्क में जा रहे थे, वहां जाने से पहले पुलिस ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस उन्हें जज के पास ले गई, जहां उन्हें लगभग सात दिन की सजा सुनाई गई. मुश्किल से उन्हें जेल में दो घंटे ही बीते होंगे कि जेल के अधिकारी आए और उनसे कहा कि अन्ना आप बाहर जा सकते हैं, आप की सज़ा माफ़ हो गई. अन्ना ने कहा कि अरे! ऐसे कैसे सज़ा माफ़ हो गई है? अभी तो मुझे सज़ा सुनाई गई है और अभी जेल में आए मुझे तीन घंटे भी नहीं बीते हैं. अधिकारियों ने कहा कि नहीं आपकी सज़ा माफ़ हो गई है. अन्ना ने कहा कि नहीं मैं अभी जेल से बाहर नहीं जाऊंगा और मैं पूरी सज़ा काट कर ही यहां से निकलूंगा. उन्होंने कहा कि अदालत को मैं बनिया की दुकान नहीं समझता कि जहां, जब जैसी मर्जी हो ग्राहक के हिसाब से अपनी क़ीमतों को ऊपर नीचे कर लो. जेल के अधिकारी चले गए और कुछ देर बाद लौट कर बोले की जेल के आईजी ने उन्हें बुलाया है. अन्ना जब आईजी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अब आप जेल नहीं जा सकते, क्योंकि अब आप जेल से बाहर आ गए हैं. अन्ना ने कहा कि अगर आप भी वही व्यवहार करेंगे, जैसा कुछ देर पहले आपके मातहत कर रहे थे, तो मैं आपके दफ्तर से नहीं उठूंगा और अन्ना तीन दिन तक आईजी के दफ्तर में बैठे रहे.

और यहीं से शुरू हुआ, देश के लोगों को गुस्सा. ठीक वैसा ही गुस्सा, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सर पर पटना की सड़कों पर लाठी का प्रहार का फोटोग्राफ देखते हुए जनता के मन में उठा था. देश लोकनायक के साथ खड़ा हो गया. उन्हीं लम्हों की पुनरावृत्ति हुई और एक बार देश को फिर से लगा कि 75 वर्ष के सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ सरकार ने अन्याय किया है, जिसके ख़िलाफ़ क्रोधित होकर बहुत बड़ी संख्या में लोग तिहाड़ जेल के सामने बैठ गए. जैसे-जैसे घंटे बीते वैसे-वैसे लोगों की भीड़ तिहाड़ जेल के सामने बढ़ने लगी. सारे देश में प्रदर्शन होने लगे और देश के लोगों को लगा कि एक गांधीवादी और जनता के हित की बात करने वाले व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है. जब अन्ना तीन दिन के बाद जेल से निकले, तो लगभग चार किलोमीटर लंबा जुलूस उनके साथ रामलीला मैदान की तरफ चला. पहले तो सरकार अन्ना हजारे को रामलीला मैदान अनशन के लिए देना ही नहीं चाहती थी, लेकिन इन्हीं तीन दिनों के भीतर रामलीला मैदान को अनशन के लायक बनाया गया और अन्ना सीधे रामलीला मैदान पहुंचे और अपना अनशन जारी रखा. टेलीविजन के सामने इस गुस्से को दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं था, न ही प्रिंट मीडिया के पास इसके पक्ष में जाने के अलावा कोई विकल्प. टेलीविजन ने इस घटना को घर-घर पहुंचा दिया और सारे देश में गुस्से की एक लहर फैल गई. रामलीला मैदान में भाषण हो रहे थे, लेकिन यह गुस्सा केवल दिल्ली भर में ही केंद्रित हो, ऐसा नहीं था. देश के अलग-अलग हिस्सों में सभाएं हो रही थीं. जो महिलाएं सभाओं में नहीं जा पा रही थीं, वो अपने गली-मुहल्लों में प्रभात फेरी निकाल रही थीं. बच्चे अन्ना-टोपी लगाकर मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना. सारा देश है अन्ना, के नारे लगाने लगे. नतीजा यह हुआ कि रामलीला मैदान से जो गुस्से का उफान निकला, उसने समूचे देश को अपने दायरे में ले लिया.

अन्ना ने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया और सरकार से जन-लोकपाल क़ानून बनाने की मांग की. इसके पहले अन्ना कई बार सरकार से बात-चीत कर चुके थे. मंत्रियों से उनकी बातें हो चुकी थीं. मंत्रियों ने उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में अन्ना को हर जगह से धोखा

अन्ना के गुस्से से शायद कम, लेकिन देश की जनता के गुस्से से डरकर संसद बैठी और एक प्रस्ताव पारित किया गया. हालांकि इस बैठक में पिछली बैठकों की तरह ही अन्ना पर कई सांसदों ने कटाक्ष किया. सबसे कड़ा कटाक्ष लालू प्रसाद यादव की ओर से था. बाद में सर्वसम्मत राय बनी और जनलोकपाल बिल लोकसभा में पास करने का निर्णय हुआ, जिसे सेंस ऑफ हाउस कहा गया.

अन्ना के गुस्से से शायद कम, लेकिन देश की जनता के गुस्से से डरकर संसद बैठी और एक प्रस्ताव पारित किया गया. हालांकि इस बैठक में पिछली बैठकों की तरह ही अन्ना पर कई सांसदों ने कटाक्ष किया. सबसे कड़ा कटाक्ष लालू प्रसाद यादव की ओर से था. शरद यादव ने भी शिष्ट भाषा का प्रयोग लोकसभा में नहीं किया, लेकिन एक सर्वसम्मत राय बनी और जनलोकपाल बिल लोकसभा में पास करने का निर्णय हुआ, जिसे सेंस ऑफ हाउस कहा गया और जिसे लोकसभा की सामूहिक राय बताई गई. अगले दिन उस प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री के पत्र के साथ स्वर्गीय बिलास राव देशमुख अपने कुछ साथी सांसदों के साथ अन्ना से मिलने पहुंचे, उन्होंने अन्ना हजारे को प्रधानमंत्री का एक पत्र और लोकसभा की सेंस ऑफ हाउस की प्रति सौंपी. अन्ना हजारे ने विलास राव देशमुख के कहने पर अपना अनशन तोड़ना स्वीकार कर लिया. इसके पहले, देश के कई जाने-माने लोगों ने अन्ना का अनशन समाप्त करवाने की कोशिशें की, जिनमें श्री श्री रविशंकर और भय्यू जी महाराज प्रमुख थे. ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद भी अन्ना का अनशन तुड़वाने गंगाजल लेकर पहुंचे थे, लेकिन अन्ना ने विनम्रता से सबकी अपीलों को नज़रअंदाज़ कर दिया. संसद के सेंस ऑफ हाउस की भाषा देख अन्ना ने अपना अनशन समाप्त कर दिया.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

यूएनआई बंदी की क़गार पर! 04

विकास का नारा जातिवाद का सहारा 05

इफ़्तार पार्टी 07

साई की महिमा 12

अन्ना का राजनीतिक क़दम

पृष्ठ एक का शेष

अनशन के बाद अन्ना कुछ दिनों के लिए गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए, क्योंकि डॉ. नरेश त्रेहन अनशन के दौरान भी उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे थे. कुछ दिन हॉस्पिटल मे रहने के बाद अन्ना अपने मूल स्थान रालेगण सिद्धि चले गए.

इसके बाद, एक तरफ़ सरकार ने अन्ना को अनदेखा करना शुरू किया, तो दूसरी तरफ अन्ना के साथियों ने अन्ना के समर्थन में उठे जनसैलाब को अपने लिए जनता का अंधा समर्थन मान लिया. फिर उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर आपस में बातचीत शुरू की, लेकिन इनमें से किसी ने भी यह समझने की कोशिश नहीं की, कि अन्ना हजारे के दिमाग़ में समाजिक परिवर्तन का नक्शा क्या है. अन्ना हजारे ने जब अनशन किया, उस अनशन से पहले अन्ना ने अपने गांव को बदलने की एक जीती-जागती कोशिश की थी. अन्ना का गांव सही मायने में देश का आदर्श गांव है. इस गांव में पान-बीड़ी-सिगरेट नहीं बिकते. 16 साल पहले जिस गांव में शराब की 40 भट्ठियां थीं, आज उस गांव में कोई शराब नहीं पीता और जिस गांव में लोगों के खाने के भी लाले पड़े हुए थे, आज उस गांव से रोज 500 लीटर दूध का निर्यात हो रहा है. अकाल पीड़ित गांव में अन्ना ने खाने का संचयन किया. गांव के लोगों को तैयार किया और मॉनसून न आने से जो गांव कभी अकाल पीड़ित क्षेत्र में आता था, आज वहां तीन फसलों के लिए पानी का इंतजाम अन्ना ने करके दिखाया. अन्ना के गांव में उगी हुई सब्जियां विदेशों तक गई हैं.

अन्ना ने 16-18 साल की मेहनत के बाद जो उपलब्धि हासिल की दरअसल, अन्ना उसे बढ़ाकर समूचे देश में लागू करना चाहते थे और उनके दिमाग़ में यह सपना हमेशा घूमता रहता था कि देश के लोग, हिंदुस्तान के गांवों को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाएं. अन्ना को गांधी जी के इस सिद्धांत में पूरा भरोसा था.

पर अन्ना के साथियों अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और किरण बेदी समेत सारे कोर-कमेटी के सदस्यों में से किसी ने भी अन्ना से यह जानने की कोशिश नहीं कि अन्ना के दिमाग़ में समाज परिवर्तन का जो ताना-बाना है, वह कैसा है? लेकिन अन्ना शायद यह समझ चुके थे कि उनके साथियों के दिमाग़ में महज एक क़ानून है और उस क़ानून को ही उनके साथी अपनी अंतिम उपलब्धि मान रहे हैं. अन्ना ने कई बार कोशिश भी की ताकी वे अपना मूल मंतव्य अपने साथियों को समझा सकें, पर अन्ना के साथियों ने न उनकी बात सुनी न ही उनके संकेतों को समझा. उसके बाद अन्ना ज़्यादातर समय रालेगण सिद्धि में ही रहे.

इसी बीच जंतर-मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने अपने साथियों मनीष सिसौदिया और गोपाल राय के साथ अनशन करने का फ़ैसला किया. अन्ना इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन करना शुरू कर दिया तो अन्ना रालेगण से दिल्ली आए और उनके समर्थन में अनशन शुरू किया.

हमारी जानकारी बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने चुनाव लड़ने या राजनीतिक दल बनाने के बारे में अन्ना से कभी बातचीत नहीं की. अगर बातचीत की भी होगी तो ऐसी भाषा में, जिस भाषा को अन्ना समझ नहीं पाए. जनरल वीके सिंह ने लगभग 10 दिनों के बाद सबका अनशन तुड़वाया, लेकिन जिस दिन अनशन टूटा, अन्ना ने अपनी बात पर क़ायम रहते हुए कहा कि जनता को कोई विकल्प देना चाहिए. लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस अनशन तोड़ने वाली मीटिंग में ही एक नई पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी. यहां से अन्ना और उनकी पुरानी टीम में दरार दिखने लगी. अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी मीटिंग रखी, जिसमें ज़्यादातर अन्ना के साथ काम करने वाले और उन्हें समर्थन देने वाले लोग शामिल थे. इनमें कई चैनलों के संपादक भी थे. दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब में दिन भर मीटिंग चली और सबने अलग-अलग राय रखी. अरविंद केजरीवाल का कहना था कि अन्ना ने उनसे कहा है कि- मैं आपका विरोध नहीं करूंगा, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं. लेकिन अन्ना ने जो भी वहां कहा हो, इसकी सच्चाई तभी पता चल सकती है, जब वह रिकॉर्डिंग सामने आए. हालांकि अन्ना ने तभी यह साफ़ कर दिया था कि उनका नई बनने वाली पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है और वे लोग उनकी तस्वीर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते. उसी दिन शाम साढ़े सात बजे अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और जनरल वीके सिंह की एक बैठक हुई. उस बैठक में अन्ना ने साफ़ कहा कि जनता कि लिए कुछ करना चाहिए, जिसका समर्थन बाबा रामदेव और जनरल वीके सिंह ने किया. अगले दिन अन्ना वापस रालेगण सिद्धि चले गए. देश में यह संदेश साफ़ चला गया कि अन्ना हजारे अब अपने साथियों अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और मनीष सिसौदिया से अलग हो चुके हैं. किरण बेदी पहले अरविंद केजरीवाल के साथ थीं, लेकिन इस मौक़े पर वे अन्ना हजारे के साथ रहीं.

किरण बेदी, सुनीता गोधारा और राकेश रफ़ीक सहित कई लोग जिनमें से किरण बेदी के अलावा, पहले कभी सार्वजनिक रोशनी में नहीं दिखाई दिए थे, अचानक सामने आ गए. उन लोगों ने अन्ना हजारे पर दबाव बनाया कि अन्ना एक नई कोर कमेटी बनाएं. अन्ना ने दिल्ली में एक बैठक भी की और तब तक लगभग दो साल बीत चुके थे. उनके तर्कों से पूरी तरह से सहमत न होते हुए भी अन्ना ने एक कोर कमेटी बनाने का फ़ैसला लिया और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन पता नहीं क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही अन्ना हजारे को लगा कि अगर वो कोर कमेटी बनाएंगें तो, यह कोर कमेटी भी उनके साथ वही व्यवहार करेगी जो अरविंद केजरीवाल वाली कोर कमेटी ने किया. इसलिए उन्होंने बहुत सावधानी पूर्वक अपने शब्दों का चयन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया. उन्होंने एक काम-चलाऊ सलाहकार समिति की घोषणा की. अन्ना ने कोर कमेटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया. अन्ना फिर रालेगण चले गए और जाने से पहले रात में उन्होंने जनरल वीके सिंह से मुलाकात की. जनरल से अन्ना ने कहा कि वे चाहते हैं कि जनरल वीके सिंह उनकी सलाहकार समिति में रहें. जनरल वीके सिंह ने अन्ना हजारे से कहा कि मैं आपके लिए सारा काम करूंगा, लेकिन मुझे अभी आप इस सलाहकार कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर भी मत रखिए. उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए काम करता रहुंगा, लेकिन जब तक आप इस कमेटी के गुण दोष को परख ना लें, तब तक आप मुझे इसमें शामिल होने के लिए दबाव न डालें.

शायद यहीं से अन्ना के मन में अपने सलाहकार कमेटी के हर सदस्य को लेकर एक शंका पैदा हो गई. अन्ना ने देखा कि अरविंद केजरीवाल के हटने के बाद उनके पास जो मिलने जाता था, वही एक-दूसरे की शिकायत करने लगता था. सलाहकार समिति के लोग भी एक-दूसरे की शिकायत करते थे. बैठकों में लोग आपस में लड़ते थे, यह सब अन्ना हजारे की आंख के सामने होता था. अन्ना का विश्वास अपने साथियों पर से कम होने लगा और उन्होंने इस सलाहकार समिति की दूसरी बैठक बुलाई ही नहीं. अन्ना देश में घूमना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने कभी अन्ना के देश में घूमने की कोई कारगर योजना नहीं बनाई और न ही कभी अन्ना की भावना को समझने का प्रयास किया. उसी तरह, इस सलाहकार कमेटी ने भी देश भ्रमण की न तो कोई योजना बनाई और न ही उनके विचारों को समझने की कोई कोशिश की. अन्ना सबके विचारों को अपने मन में परखने की कोशिश कर रहे थे. अन्ना से जो भी मिलने जाता था, वे उसकी बातें सुनते थे और अपनी बातें समाज परिवर्तन के संदर्भ में उसके सामने रख देते थे, पर जब वे देखते थे कि उनसे मिलने वाले लोग बाक़ी सारी बातें करते हैं, लेकिन समाज परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करते, तो उनके मन में एक डर और संदेह पैदा हो जाता था. इसीलिए अन्ना ने दिल्ली आना भी बहुत कम कर दिया. उन्होंने दिल्ली आने की बजाए अपना रास्ता ही बदलने का निर्णय कर लिया.

इस बीच दिसंबर 2012 में अन्ना की मुलाकात जनरल वीके सिंह और एक अखबार के संपादक से हुई. इसी मुलाक़ात के दौरान अन्ना ने 30 जनवरी को पटना में रैली करने की बात कही. इस बीच अन्ना ने अपने सारे साथियों से कहा कि वे 30 जनवरी को पटना में रैली करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ काम कर रहे उनकी सलाहकार समिति के ज़्यादातर सदस्यों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. जब अन्ना ने इस इच्छा को दोबारा जाहिर किया, तो उनके पास अंतिम रूप से यह संदेशा गया कि वहां पर दो दफ्तर बन गए हैं, दो ग्रुप बन गए हैं और नेता आपस में लड़ रहे हैं. अन्ना का मन और टूट गया, इससे पहले अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण यह कह चुके थे कि अन्ना के पास वापस लौटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है. योगेंद्र यादव ने यह सार्वजनिक बयान दिया था कि अन्ना हजारे तीन-चार महीनों में उनके पास लौट आएंगे, लेकिन ये लोग अन्ना की इच्छाशक्ति से अपरिचित थे. बस यही उनकी ग़लती थी. उन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग अन्ना को अकेला कर देंगे तो अन्ना उनके पास लौट आएंगे, लेकिन अन्ना जिस प्रक्रिया में अन्ना बने हैं, उस प्रक्रिया ने उन्हें लौहपुरुष बना दिया. दरअसल, उनकी सलाहकार समिति में हर नया आदमी अरविंद केजरीवाल जैसी ख्याति बटोरना चाहता था, लेकिन वहीं अन्ना अपने लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले साथियों की तलाश कर रहे थे. इस बीच अन्ना के पास महाराष्ट्र से कई सारे साथी आए, लेकिन अन्ना को लगा कि कोई भी राष्ट्रीय फलक के ऊपर शायद काम न कर पाए, इसलिए अन्ना रालेगण सिद्धि में ही जमकर बैठ गए. जब उनकी जनरल वीके सिंह और एक अख़बार के संपादक से मुलाक़ात हुई तो, अन्ना को लगा कि अब समाज परिवर्तन की उनकी कल्पना को आगे ले जाने वाले साथियों की तस्वीर साफ़ हो रही है. उन्होंने समाज परिवर्तन की अपनी जिन-जिन बातों को रखा, उनसे जनरल वीके सिंह और उन संपादक ने अपनी सहमति जाहिर की. वहीं यह तय हुआ की पटना में 30 जनवरी को रैली की जाए, जिसमें अन्ना जी जाएंगे और सभी मिल जुलकर समाज परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन के अन्ना के सपने को साकार करेंगे. इसके साथ ही एक और नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी.■

सभी फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 22
दिल्ली, 05 अगस्त-11 अगस्त 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना-800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
6452888
011-23418962
विज्ञापन व प्रसार +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

आईएएस पर कार्रवाई

पंजाब प्रशासन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को उनके गलत कार्यों के लिए दंडित किया जा रहा है. संघ लोक सेवा आयोग ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी कृपा शंकर सरोज और 1986 बैच के आईएएस अधिकारी बी सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए अपनी अनुमति दे दी है. फिलहाल कृपा शंकर सरोज महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक हैं और बी सरकार पंजाब मानवाधिकार आयोग के सचिव हैं. हालांकि 1979 बैच के एक अन्य आईएएस अधिकारी को छोड़ दिया गया है. सरोज को बिना सरकार के आदेश के 2004 में पंजाब एग्रो फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन में एमडी के पद पर कार्य करने का दोषी पाया गया है. सरोज पर इस पद का दुरुपयोग कर कोष से बिना किसी जांच के 17 करोड़ दस लाख जारी करने का आरोप है. दोनों अधिकारियों को वेतन में कटौती और भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित करने का फैसला किया गया है.

बिना नेतृत्व के यूपीएससी

कई जिम्मेदार सरकारी पदों पर नियुक्तियों में देरी व उनको लेकर हीला-हवाली करना यूपीए2 की पहचान बन गई है. यह तब है, जबकि सरकार का यह कार्यकाल अब अपने अंतिम चरण की ओर है. पिछले कुछ महीनों से संघ लोकसेवा आयोग में किसी सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है. अमिताभ भट्टाचार्य को यहां से स्टाफ सेलेक्शन कमीशन में नियुक्ति के लिए भेजे जाने के बाद से अब तक सरकार किसी को सचिव के रिक्त हुए पद पर नियुक्त करने के बारे में गंभीर नहीं दिख रही है. सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट सेक्रेट्रिएट ने इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कार्यरत अतिरिक्त सचिव अमरजीत सिंह का चुनाव किया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मानव संसाधन विकाम मंत्री पल्लम राजू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. अब सरकार के पास इस पद पर नये सिरे से विचार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है. ■

बेख़ौफ़ आईपीएस लॉबी

यह बाबुओं की ताकत का ही नमूना है कि कई बार मंत्री भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से डरते हैं. उनके डर का यह कारण है कि कहीं उनका कोई कदम नौकरशाही को विचलित न कर दे. सूत्रों के मुताबिक शक्तिशाली आईपीएस लॉबी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी सरकारी आवास में रहते हुए अपने कोटे के फ्लैटों को किराये पर दे रखा है. बड़ी बात यह है कि किसी कार्रवाई से बचने के लिए पूरी आईपीएस लॉबी लामबंद हो गई है. निश्चित रूप से उन अधिकारियों के खिलाफ किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की फाइलें राज्य के गृहमंत्री आर आर पाटिल के कार्यालय में भेजी होंगी, लेकिन वे उन फाइलों पर हस्ताक्षर करने में हिचकिचा रहे हैं. जिन फ्लैट्स पर उन अधिकारियों ने कब्जा जमा रखा है, वे मुंबई, पुणे और नासिक में स्थित हैं और उनमें से ज्यादातर उन अधिकारियों ने कब्जा किया है, जिन्हें काफी पहले मुंबई से बाहर स्थानांतरित किया जा चुका है. हालांकि महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख अरुप पटनायक ने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन मजबूत आईपीएस लॉबी के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है. ■

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

प्रमोद कुमार बने योजना आयोग के वरिष्ठ सलाहकार

राजस्थान कैडर के 1983 बैच के आईएएस प्रमोद कुमार आनंद अब नई भूमिका के तौर पर योजना आयोग के वरिष्ठ सलाहकार की जिम्मेदारी संभालेंगे. प्रमोद कुमार फिलहाल ग्रामीण विकास मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेट्री हैं.

अपराजिता भूमि संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव बनीं

1994 बैच की आईएएस ऑफिसर अपराजिता सारंगी की नियुक्ति भूमि संसाधन विभाग में बतौर संयुक्त सचिव हुई है. उन्होंने 1981 बैच की आईएफएस अधिकारी डॉ सविता आनंद की जगह ली है.

ऊर्जा मंत्रालय में प्रदीप कुमार को अतिरिक्त जिम्मेदारी

केरल कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार की नियुक्ति बतौर सचिव व वित्तीय सलाहकार उर्जा मंत्रालय में हुई है. प्रदीप कुमार से पहले उनकी जगह पर 1981 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश जैन कार्यरत थे.

13 आईएफएस संयुक्त सचिव बने

भारत सरकार के 1984 बैच के 13 आईएफएस को संयुक्त सचिव या समकक्ष की सूची में शामिल किया गया है, जिन्में अभय कुमार सिंह (यूपी) भगवान बक्स सिंह (एमपी) मनोज पंत (जम्मू-कश्मीर) टी वी नरसिम्हा राव (पश्चिम बंगाल) पी के पंत, अतुल कुमार शुक्ला (छत्तीसगढ़), जितेन कुमार (छत्तीसगढ़), गंबीर सिंह (उत्तराखंड) के नाम प्रमुख हैं.

प्रजापति त्रिवेदी का सेवा विस्तार

प्रजापति त्रिवेदी को एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है. प्रजापति वर्तमान में नेशलन अथॉरिटी केमिकल वीपंस कन्वेंशन में चेयरमैन व परफॉरमेंस मैनेजमेंट कैबिनेट सचिवालय में कार्यरत हैं. आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है. ■

अन्ना ने इस सभा में घोषणा की कि उनका रिश्ता इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के संगठन से नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके नाम पर अब कोई संगठन नहीं चलेगा. सिर्फ़ एक जानकारी देने वाली वेबसाइट चलेगी, जिसका नाम ज्वाइन अन्ना हजारे है.

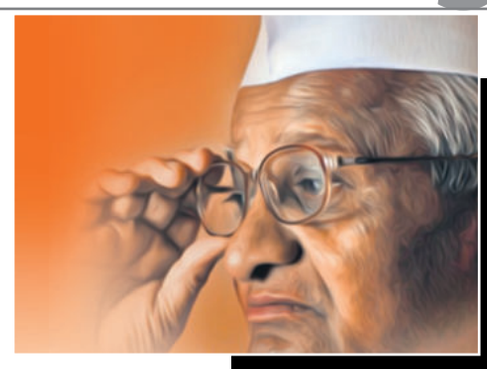

अन्ना की राजनीतिक योजना

तीस जनवरी का दिन अन्ना की ज़िंदगी और देश के लिए महत्वपूर्ण था. इसके बाद देश भर में घूमने की तैयारी शुरु हुई और अन्ना ने तीस मार्च से पंजाब के जालियांवाला बाग से अपनी जनतंत्र यात्रा शुरु करने की घोषणा कर दी. पंजाब के जालियांवाला बाग से अन्ना अपने साथियों के साथ यात्रा पर निकले और पंजाब से हरियाणा आते-आते और लोगों से बातचीत करते अन्ना को लगा कि इस देश में बड़े बदलाव की जरूरत है. जैसे ही वे उत्तर प्रदेश के नोएडा, मेरठ, मुज़फ्फ़रनगर होते हुए देहरादून पहुंचे अन्ना के सामने एक नए सत्य का पर्दा खुला. अन्ना ने कई किताबें पढ़ीं, कई लोगों से बातें की और अब तक उन्हें यह मालूम हो चला था कि यह सारा देश संविधान के ख़िलाफ़ चल रहा है.

अन्ना ने फिर एक बार धोखा खाया, क्योंकि अन्ना ने जनरल वीके सिंह और अख़बार के उन संपादक को यह सलाह दी कि उनके साथ लगे हुए पुराने जितने भी साथी हैं, उनको भी अन्ना की राजनीतिक योजना में शामिल करने की कोशिश की जाए. ईमानदारी से यह कोशिश हुई भी कि बिहार में जितने भी पुराने लोग हैं, जिनमें सर्वोदय के पुराने साथी शामिल हैं और अन्ना के इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग शामिल हैं, उनसे संपर्क किया जाए. सब लोग आए, सबने बातचीत की. तैयारी का फ़ैसला किया गया और सभी खुश-खुश चले गए. अन्ना के पास यह संदेश गया कि सब लोग मिलकर अन्ना की रैली की तैयारी करेंगे, लेकिन तमाशा जनवरी की 15 तारीख को हुआ, जब जनरल वीके सिंह और संपादक महोदय पटना गए तो मालूम चला की वहां के लोगों ने कोई तैयारी ही नहीं की है और न सर्वोदय के लोगों ने न इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोगों ने. बल्कि ऐसा क्या किया जाए कि अन्ना पटना आ ही न सकें, इस योजना पर काम हो रहा था. उन लोगों को लग रहा था कि जनरल वीके सिंह और संपादक महोदय ने अन्ना को बरगला लिया है. अन्ना रालेगण में थे. पटना में तैयारी के नाम पर केवल शून्य था.

यहां से नए सिरे से तैयारी हुई और 14 दिनों के बाद पटना के गांधी मैदान में पौने दो लाख लोगों की रैली हुई. इस रैली के लिए कुल चार लाख रुपये भी नहीं ख़र्च हुए. लोग अपने पैसे ख़र्च कर रैली में शामिल हुए, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री ने इसी मैदान पर इतनी ही संख्या के साथ की गई रैली में करोड़ों रुपये ख़र्च किए थे. अन्ना ने इस सभा में घोषणा की कि उनका रिश्ता इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के संगठन से नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके नाम पर अब कोई संगठन नहीं चलेगा. सिर्फ़ जानकारी देने वाली एक वेबसाइट चलेगी, जिसका नाम ज्वाइन अन्ना हजारे है. अन्ना ने जनतंत्र मोर्चा नाम से एक नए संगठन की घोषणा की, उन्होंने यह भी कहा कि यह संगठन वॉलिंटियर का संगठन होगा, इसमें कोई भी पदाधिकारी नहीं होगा और यह जनतंत्र के अनुरूप होगा. यहां अन्ना ने यह घोषणा की कि वे जनतंत्र के लिए लड़ेंगे.

30जनवरी, 2013 का दिन अन्ना की ज़िंदगी और देश के लिए महत्वपूर्ण था. इसके बाद, देश भर में घूमने की तैयारी शुरू हुई और अन्ना ने 30 मार्च से पंजाब के जालियांवाला बाग से अपनी जनतंत्र यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी. पंजाब के जालियांवाला बाग से अन्ना अपने साथियों के साथ यात्रा पर निकले और पंजाब से हरियाणा आते-आते और लोगों से बातचीत करते अन्ना को लगा कि इस देश में बड़े बदलाव की ज़रूरत है. जैसे ही वे उत्तर प्रदेश के नोएडा, मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर होते हुए देहरादून पहुंचे अन्ना के सामने एक नए सच का पर्दा खुला. अन्ना ने कई किताबें पढ़ीं, कई लोगों से बातें की. अब तक उन्हें यह मालूम हो चला था कि यह सारा देश संविधान के ख़िलाफ़ चल रहा है. अन्ना ने संविधान की किताबें मंगाई. संविधान सभा में क्या-क्या हुआ. चुनाव को लेकर संविधान में क्या कहा गया, इन सारी चीज़ों की जानकारी उन्होंने अपने साथ चलने वाले साथियों से इकट्ठा कीं. इन सबके अध्ययन के बाद अन्ना को लगा कि संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी शब्द ही नहीं है. तब अन्ना ने तलाश शुरू की कि आख़िरकार यह पार्टियां लोकसभा में पहुंची कैसे? तब इस बात की जानकारी हुई कि यह सारा पार्टी सिस्टम ही देश के संविधान के ख़िलाफ़ है. संविधान में जनता का ज़िक्र है कि वो अपने उम्मीदवार खड़े करेगी. उम्मीदवार चुनकर लोकसभा में जाएंगे. जहां वो जाकर अपने चुनाव क्षेत्र और देश के बारे में बहस करेंगे. समस्याओं का निदान करेंगे और कानून बनाएंगे. लोकसभा के सदस्यों का बहुमत जिसके साथ होगा, वह प्रधानमंत्री बनेगा. वह अपने मंत्रियों का चुनाव करेगा. संविधान में कहीं पर भी पार्टियों का या पार्टियों के गठजोड़ का या सबसे बड़ी पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा, इसका ज़िक्र है ही नहीं. अन्ना ने यह भी पाया कि जब यह संविधान बना था, तब राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में थीं. इसके बावजूद, संविधान बनाने वालों ने राजनीतिक दल कैसे होंगे, कैसे काम करेंगे, इस बारे में संविधान में कोई ज़िक्र ही नहीं किया है. तब अन्ना को लगा कि इस देश में बुनियादी परिवर्तन तब तक नहीं आ सकता, जब तक राजनीतिक दल लोकसभा में रहेंगे. साथ ही अन्ना इस नतीजे पर भी पहुंचे कि इस देश से भ्रष्टाचार और महंगाई जैसी मुश्किलें तब तक समाप्त नहीं होगीं, जब तक कि यह पार्टियां लोकसभा में रहेंगी. अन्ना ने यहीं पर यह भी समझा कि जहां पहले लाखों में भ्रष्टाचार होता था, वह बढ़ते-बढ़ते करोड़ों में हो गया. फिर वह पांच हज़ार करोड़, दस हज़ार करोड़, पचास हज़ार करोड़, एक लाख करोड़ अब एक लाख छिहत्तर करोड़ और 26 लाख करोड़ तक पहुंच गया. जिस रकम को कैलकुलेटर में लिख नहीं सकते उस रकम का भ्रष्टाचार पार्टियों ने और सरकारों ने मिलकर करना शुरू कर दिया. जैसे ही अन्ना को यह पता चला कि इस बड़े भ्रष्टाचार में हर पार्टी का हिस्सा है, तब अन्ना की आंखें खुल गईं. अन्ना ने कहना शुरू कर दिया कि जब तक पार्टी सिस्टम रहेगा, तब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा. महंगाई और बेरोजगारी जैसी मुश्किलें ख़त्म नहीं होंगी. अन्ना ने पार्टी सिस्टम को ही भ्रष्टाचार, ख़राब शिक्षा व्यवस्था और ख़राब स्वास्थ्य व्यवस्था का ज़िम्मेदार बताया.

अन्ना ने मुंबई में जनरल वीके सिंह के साथ मिलकर एक नीति संबधी मसौदा जारी किया, जिसका शीर्षक था, यह संसद संविधान विरोधी है. क्योंकि अन्ना इस नतीजे पर पहुंचे थे कि यह संसद संविधान में दी गई लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के ख़िलाफ़ बाज़ार आधारित क़ानून बनाने लगी है और देश के लोगों की ज़िम्मेदारी को अब अपनी ज़िम्मेदारी नहीं मान रही है. दरअसल, यह संविधान का उल्लंघन है, लेकिन सरकार ने बिना कुछ कहे संविधान की मूल अवधारणा के ख़िलाफ़ देश को चलाना तय किया और नियम और कानून बनाने शुरू किए. इसमें चंद्रशेखर जी के बाद जितनी सरकारें देश में बनी, सभी सरकारों ने हिस्सा लिया और इस देश को एक तरह से बाज़ार के हवाले कर दिया. इसके बाद, अन्ना ने एक 25 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया. इस 25 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने की मांग अन्ना ने सभी राजनीतिक दलों से की और कहा कि इस पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी और अखिलेश यादव के अलावा, किसी राजनेता या राजनीतिक दल ने अन्ना के पत्र का जवाब नहीं दिया. सोनिया गांधी ने अपने जवाब में चार लाइन के खत में कहा कि कांग्रेस हमेशा ग़रीबों के लिए लड़ती रही है और अखिलेश यादव ने लिखा कि हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आपके संघर्ष में हम हमेशा आपका साथ देंगे. इन दो ख़तों के अलावा, किसी भी पार्टी की तरफ़ से कोई जवाब तक नहीं मिला. यहां तक कि दोनों ख़तों में अन्ना के 25 सूत्रीय कार्यक्रम के ऊपर एक लाइन की प्रतिक्रिया तक नहीं थी.

जब अन्ना इस नतीजे पर पहुंच गए कि यह पार्टी सिस्टम देश के जनतंत्र के ख़िलाफ़ है तो उन्होंने इस पार्टी सिस्टम से लड़ने का फ़ैसला किया. उन्होंने देश की जनता का आह्वान किया, कि वह पार्टी सिस्टम के ख़िलाफ़ दूसरी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हों. अन्ना को उत्तराखंड में इन सवालों के जवाब मिल गए कि लोग इस विषय को समझ भी पाएंगे या नहीं. उन्होंने पाया कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि बिना राजनीतिक दलों के यह देश कैसे चलेगा, जबकि जनता उत्तराखंड में यह कह रही थी कि पार्टियों को हटाना बहुत ज़रूरी है नहीं तो देश से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा. अन्ना उत्तराखंड की यात्रा समाप्त कर दिल्ली आए और उन्होंने प्रसिद्ध संविधानविद् सुभाष कश्यप से मुलाकात की. सुभाष कश्यप ने कहा कि यह बात सही है कि संविधान में राजनीतिक पार्टियों का जिक्र नहीं है, लेकिन इतने दिनों से राजनीतिक पार्टियों की व्यवस्था चली आ रही है तो बिना राजनीतिक पार्टियों के देश कैसे चलेगा. अन्ना ने बाहर निकलकर अपने मन में दृढ़ फ़ैसला ले लिया लिया कि यह सवाल राजनीतिक है और संवैधानिक है. चूंकि संविधान में राजनीतिक पार्टियों का जिक्र नहीं है, इसलिए वह इस सवाल के ऊपर सियासी पार्टियों से लड़ेंगे. अन्ना ने सारे देश में पार्टियों के ख़िलाफ़ संविधान की दुहाई देकर एक लड़ाई शुरू कर दी. यहीं पर अन्ना द्वारा देश को एक राजनीतिक विकल्प देने के मसले का एक उत्तर भी मिलता है. अन्ना ने कहा कि अगर एक चुनाव क्षेत्र में 20 लोग भी बिना पार्टियों के खड़े होते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, जिसे लोग चुनेंगे वो इन पार्टियों के प्रतिनिधियों से अच्छा होगा. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टियां अपने ईमानदार कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देती हैं. पार्टियां या तो वंशवाद और परिवारवाद चला रही हैं या टिकटों को बेच रही हैं. अगर कोई अच्छा व्यक्ति पहुंच भी जाता है तो वह पार्टियों के माफिया स्वरूप से डरकर बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता. यहीं पर अन्ना ने एक दूसरा रास्ता भी अपने साथियों से बातचीत कर सोचा है. अन्ना अन्य पार्टियों के अच्छे लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टियों को छोड़ कर बाहर आएं और जनता के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ें.

अब यहां सवाल यह उठता है कि अन्ना हजारे किसे समर्थन देंगे. अगर एक निवार्चन क्षेत्र में 15 लोग खड़े हो जाते हैं तो ऐसे में अन्ना का समर्थन किसे मिलेगा. अन्ना ने कई बार बातचीत में अपने साथियों को यह साफ़ किया है कि जो उनकी बात को ज़्यादा मानेगा. मसलन जो यह कहेगा कि मैं गांवों को सर्वशक्तिशाली बनाने के लिए कानून बनाने की मुहिम में साथ देगा, उसे ही अन्ना का समर्थन प्राप्त होगा. जो यह वायदा करेगा कि मैं जनता के सवालों को लोकसभा में उठाऊंगा, उसे ही अन्ना का साथ मिलेगा. तीसरी शर्त यह होगी कि वह अपना इस्तीफा अपने चुनाव कमेटी के पास शपथ पत्र के रूप में पहले ही जमा कराएगा और उस कमेटी को यह अधिकार देगा कि जिस दिन कमेटी को लग जाए कि यह व्यक्ति लोकसभा में उन सवालों को नहीं उठा रहा है, जिसका वायदा वह देश की जनता से करके गया है, वो कमेटी उस इस्तीफे को सीधे लोकसभा के पास भेजी देगी, जिसमें उस प्रत्याशी के इस्तीफे का शपथ पत्र लगा होगा. यह अन्ना के राइट टू रिकॉल का एक अलग तरह का प्रयोग है, जो अन्ना के 25 सूत्री कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संसद में संघर्ष करेगा.

अन्ना ने अभी तक अपने समर्थन की शर्तें सार्वजनिक नहीं की हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पास देश भर से यह संदेश आने लगा है कि अगर वे चुनाव में खड़े हों तो क्या अन्ना उनका समर्थन करेंगे. अन्ना सबसे यह कह रहे हैं कि अगर वे पार्टी से बाहर आकर संविधान के अनुरूप चुनाव लड़ेंगे तो मैं समर्थन करने के बारे में सोचूंगा, लेकिन समर्थन करने की उनकी जो शर्तें हैं उसे जो उम्मीदवार मानेगा, उसी के लिए अन्ना हजारे प्रचार करने जाएंगे.

सवाल आम आदमी पार्टी का भी सामने है. अरविंद केजरीवाल हर जगह अन्ना के उम्मीदवार के रूप में अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी के लोग हर जगह यह बता रहे हैं कि वो अन्ना के समर्थक हैं, जबकि अन्ना हर जगह यह कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी, चाहे वह आम आदमी पार्टी ही क्यों न हो, वह उनके समर्थन की हकदार नहीं है, क्योंकि वह संविधान के ख़िलाफ़ खड़ी है. उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को अच्छा आदमी मानता हूं, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल संविधान के ख़िलाफ़ खड़े हैं. इस सवाल पर कि अगर अरविंद केजरीवाल और उनके साथी अपनी पार्टी भंग कर दें तो? अन्ना ने साफ उत्तर दिया कि तब वे अच्छे उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे. अच्छे का तात्पर्य यहां यह है कि उम्मीदवार की सार्वजनिक छवि ठीक हो, उसके ऊपर भ्रष्टाचार और व्यभिचार के आरोप न हों और वो जनता के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति हो.

दरअसल, अन्ना राजनीति में कार्यकर्ता की हैसियत दोबारा वापस लाना चाहते हैं. अन्ना जो काम करते हैं, उसे संसद में जाना चाहिए के सिद्धांत पर नए राजनीतिक विकल्प की नींव रखना चाहते हैं. इसका मतलब अगर अन्ना इस देश में 500 उम्मीदवार खड़े करते हैं, जो उनके परिभाषा के हिसाब से चरित्रवान हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं और वे अन्ना के 25 सूत्रीय कार्यक्रम को मानते हैं. साथ ही जो लोग राइट टू रिकॉल के सिद्धांत के तहत पहले ही अपना इस्तीफा अपने क्षेत्र की कमेटी के पास रखते हैं, तो अन्ना उनके प्रचार में जाएंगे. अगर इन 500 उम्मीदवारों में एक से लेकर 300 तक अन्ना की वजह से लोकसभा में पहुंच पाएं तो इस देश का राजनीतिक इतिहास बदल जाएगा. अन्ना के इस राजनीतिक विकल्प में कई पेंच हैं और कई सवाल भी हैं. कई लोगों का मानना है कि जिस तरह की थैलियां हमारी राजनीति में चल रही हैं और जिस तरह बड़े उद्योगपति सांसदों को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, अगर वैसा ही हुआ तो क्या होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थीं तो एक बार यह ख़बर आई थी कि केके बिड़ला लोकसभा के 80 सांसदों को महीने में पैसे देते थे और उन सांसदों की ईमानदारी केके बिड़ला के प्रति थी. क्या एक हज़ार, दो हज़ार करोड़ का इंतज़ाम करने वाला इन पार्टियों से बाहर रहने वाले लोकसभा सदस्यों को ख़रीदने की कोशिश नहीं कर सकता. अन्ना का इस पर सीधा जवाब है कि नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम देश बदलने की बात करते हैं, जनतंत्र लाने की बात करते हैं तो जनता के चुने हुए व्यक्तियों के मन में जनता का डर भी होता है कि अगर उसने कुछ गलत किया तो वह अगली बार जीत भी नहीं पाएगा और उसके चुनाव क्षेत्र के लोग उसे लोकसभा से वापस बुला लेंगे.

देखना है कि अन्ना जिस तरह के राजनीतिक विकल्प की बात कर रहे हैं, उस राजनीतिक विकल्प को राजनीतिक दल कोई महत्व देते हैं या नहीं. और अगर राजनीतिक दल महत्व नहीं देते हैं और जनता अन्ना के इस सिद्धांत को महत्व देती है तो देश में किस तरह की राजनीतिक अग्नि परीक्षा लोगों को देनी होगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता. हां, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि देश में जिस तरह की राजनीतिक बयार अभी बह रही है, उसमें एक तरफ़ अन्ना हजारे हैं और दूसरी तरफ अन्ना हजारे. अब जनता के ऊपर है कि वह राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देकर भ्रष्टाचार, महंगाई, ख़राब शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के पक्ष में वोट देती है या अन्ना हजारे के पक्ष में वोट देकर उनसे लड़ने और उन्हें मिटाने का संकल्प व्यक्त करती है.■

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

संतोष भारतीय
editor@chauthiduniya.com

बिहार

> 21 जनवरी, 2008 को न्यायालय ने जी न्यूज के विरुद्ध अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि सुभाष चंद्रा की कंपनी मीडिया वेस्ट प्रा.लि. एक निवेश कंपनी है, जिसने यूएनआई के सारे शेयर 32 करोड़ 4 लाख रुपये में ख़रीदे हैं, जबकि यूएनआई के नियमानुसार, उसके शेयर केवल किसी अख़बार को ही बेचे जा सकते हैं.

यूएनआई बंदी की क़गार पर!

भारत की सबसे बड़ी एवं प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) ज़बरदस्त आर्थिक तंगी की शिकार है और किसी भी समय बंद हो सकती है. एजेंसी के कर्मचारियों को वेतन भी 11 माह की देरी से मिल रहा है. कहा जाता है कि इस पर आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य का कब्ज़ा है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूएनआई और इस पर निर्भर देश के हज़ारों छोटे-बड़े क्षेत्रीय समाचारपत्रों की मौत हो जाएगी? पढ़िए यह विशेष रिपोर्ट...

डॉ. क़मर तबरेज़

यूएनआई के आर्थिक संकट की कहानी 2007 से शुरू होती है. उस समय जी न्यूज समूह के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड के एक्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट एवं यूएनआई के चेयरमैन नरेश मोहन और वहां की यूनियन में बैठे उत्तम लाल एवं जवाहर गोयल जैसे लोगों के साथ मिलकर बेहद गोपनीयता और ग़लत नीयत से इस समाचार एजेंसी के सभी शेयर 32 करोड़ 4 लाख रुपये में ख़रीद लिए. उन्होंने इस पर पूरी तरह अपना क़ब्ज़ा जमाने की कोशिश की. उक्त शेयर दरअसल, सुभाष चंद्रा की इंवेस्टमेंट कंपनी मीडिया वेस्ट प्रा.लि. ने ख़रीदे थे और इस मामले में इतनी गोपनीयता बरती गई कि यूएनआई के किसी भी कर्मचारी को इसकी कानोंकान ख़बर नहीं हो पाई, लेकिन अगले दिन जब अंग्रेज़ी दैनिक डीनएन में यह ख़बर प्रकाशित हुई, तो यूएनआई के कर्मचारियों को पता चला और वे शर्मिंदा हुए कि इतनी बड़ी ख़बर ख़ुद उनकी एजेंसी को मालूम नहीं हो सकी.

इस ख़बर पर यूएनआई की स्टॉफ यूनियन और कर्मचारियों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई. उन्होंने इस मामले में न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने भी उनके पक्ष में फ़ैसला किया. 21 जनवरी, 2008 को न्यायालय ने जी न्यूज के विरुद्ध अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि सुभाष चंद्रा की कंपनी मीडिया वेस्ट प्रा.लि. एक निवेश कंपनी है, जिसने यूएनआई के सारे शेयर 32 करोड़ 4 लाख रुपये में ख़रीदे हैं, जबकि यूएनआई के नियमानुसार, उसके शेयर केवल किसी अख़बार को ही बेचे जा सकते हैं. दूसरा यह कि मीडिया वेस्ट प्रा.लि. कंपनी के नियम- क़ानूनों में यह उल्लेख है कि उसके द्वारा अर्जित मुनाफ़ा कोई बाहर नहीं निकाल सकता है, बल्कि उसे इसी कंपनी में ही दोबारा निवेश करना होगा. न्यायालय के अनुसार, इस प्रकार के नियम-क़ानून भी यूएनआई के शेयर खरीदने की अनुमति नहीं देते.

न्यायालय के इस फ़ैसले के बाद जी न्यूज समूह को अपने पैर वापस खींचने पड़े, लेकिन यहीं से यूनएनआई के आर्थिक संकट की कहानी शुरू होती है. दरअसल, जी न्यूज समूह ने शेयर खरीदने के बाद जो 32 करोड़ 4 लाख रुपये यूएनआई के एकाउंट में जमा कराए थे, अदालत का फ़ैसला आने के बाद उसने अपनी उक्त धनराशि वापस लेनी चाही. लेकिन यहां भी एक खेल खेला गया. चूंकि सुभाष चंद्रा ने यह सारा खेल स्वयं यूएनआई की यूनियन के साथ मिलकर किया था. लिहाज़ा न्यायालय का फ़ैसला आ जाने के बाद यूनियन के उन्हीं लोगों ने एक रणनीति के तहत जी न्यूज समूह द्वारा जमा कराए गए पैसों की फिज़ूलख़र्ची शुरू कर दी, ताकि यूएनआई कभी उक्त पैसा लौटा न सके और इस तरह उसकी परेशानियां बढ़ती जाएं. मसलन, यूएनआई परिसर में घास लगाने के लिए बेहिसाब पैसा ख़र्च किया गया, एक शौचालय बनवाने के लिए चार लाख रुपये ख़र्च किए गए. इसी प्रकार पैसों का जमकर बंदरबांट किया गया. इसमें यूएनआई मैनेजमेंट का कोई हाथ नहीं था, बल्कि यह सारा खेल स्वयं सुभाष चंद्रा और एजेंसी की यूनियन में मौजूद उनके साथियों की साठगांठ से खेला जा रहा था. नतीजतन, जब जी समूह को पैसा लौटाने का समय आया, तो उसके खाते में फिक्स्ड डिपोजिट के रूप में केवल 27 करोड़ रुपये ही वापस जमा कराए जा सके. शेष धनराशि को लेकर न्यायालय के हस्तक्षेप से यह तय हुआ कि यूएनआई 22 लाख रुपये प्रतिमाह की किस्त के रूप में उसे वापस करेगी.

उन्हीं दिनों एक और रोचक घटना हुई. जी समूह और यूएनआई के बीच इस मामले की सुनवाई के दौरान आनंद बाज़ार पत्रिका (एबीपी) समूह ने न्यायालय को यह विश्वास दिलाया था कि वह यूएनआई को आर्थिक संकट से निकाल लेगा. न्यायालय ने उसे यह ज़िम्मेदारी सौंप दी, लेकिन बाद में स्वयं आनंद बाज़ार पत्रिका समूह अपने वादे से मुकर गया. यूएनआई ने इस पर विचार-विमर्श करना शुरू किया कि क्यों न आनंद बाज़ार पत्रिका समूह के विरुद्ध न्यायालय की अवहेलना का मामला दर्ज कराया जाए, लेकिन गहन विचार-विमर्श के बाद यह मालूम हुआ कि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, बल्कि वह यूएनआई से सही ढंग से परिचित नहीं है, इसीलिए उसे अपना काम करने में कठिनाई हुई. यह तर्क इस बात से साबित किया जा सकता है कि पीके माहेश्वरी जब एबीपी के चेयरमैन थे, तब वह स्वयं यूएनआई को वीआरएस के लिए प्रत्येक माह 10 लाख रुपये की सहायता अपने फंड से करते थे. इसके अलावा, आनंद बाज़ार पत्रिका ने यूएनआई की कई बार आर्थिक सहायता की.

चौथी दुनिया को कुछ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यूएनआई की हिंदी सेवा के कुछ कर्मचारी अब भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम यूएनआई हिंदी के मौजूदा सदस्य मुकेश कौशिक एवं मोहनलाल जोशी का है. यही नहीं, मुकेश कौशिक और लालकृष्ण आडवाणी के बीच नज़दीकी संबंधों की बात भी किसी से छिपी नहीं है. कहा यह भी जा रहा है कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आते ही एक बार फिर यूएनआई पर क़ब्ज़ा करने की पूरी कोशिश की जाएगी. ग़ौरतलब है कि कुछ सालों पहले आरएसएस ने अपनी एक अलग समाचार एजेंसी स्थापित करने का प्रयास किया था और इसके लिए उसने यूएनआई को आसान टारगेट समझते हुए उस पर क़ब्ज़ा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका. यही कारण है कि पिछले दिनों जब यूएनआई के कुछ लोगों ने कांग्रेसी नेताओं से इस संस्था को आर्थिक संकट से उबारने के लिए गुहार लगाई, तो उन्होंने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि भाई, यह तो संघियों की संस्था है, उसमें हम भला आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? इससे साबित होता है कि कांग्रेस भी यूएनआई को आरएसएस से जुड़ी एजेंसी मानती है. ऐसे में, भला कांग्रेस के नेतृत्व वाली वर्तमान यूपीए सरकार से यह आशा कैसे की जा सकती है कि वह इसे आर्थिक संकट से बाहर निकालेगी.

> **चौथी दुनिया को कुछ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यूएनआई की हिंदी सेवा के कुछ कर्मचारी अब भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम यूएनआई हिंदी के मौजूदा सदस्य मुकेश कौशिक एवं मोहनलाल जोशी का है. यही नहीं, मुकेश कौशिक और लालकृष्ण आडवाणी के बीच नज़दीकी संबंधों की बात भी किसी से छिपी नहीं है.**

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, हाल में यूएनआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन विश्वास त्रिपाठी, जो संयोग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के सीईओ भी हैं, ने बैकडोर से यूएनआई में 50 लाख रुपये का निवेश किया है. ज़ाहिर है कि यूएनआई इस पैसे को शेयर बेचकर प्राप्त किया जाने वाला पैसा कभी नहीं बताएगी, बल्कि इसे कर्ज के रूप में दर्शाएगी. अब सवाल यह उठता है कि क्या विश्वास त्रिपाठी यूएनआई के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? क्या सुभाष चंद्रा की तरह उनके ख़िलाफ़ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि विश्वास त्रिपाठी का एक भांजा यूएनआई में बतौर रिपोर्टर काम रहा है, लेकिन असल में वह यूएनआई के सीईओ के रूप में जाना जाता है और उसके ख़िलाफ़ बोलने का किसी में साहस नहीं है. यूएनआई में भय का माहौल है. हर किसी को यह डर है कि कहीं इस संस्था पर ताला न लग जाए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की ओर से इसे कमज़ोर करने के प्रयास लगातार हो रहे हैं और तानाशाही बरकरार है, जिससे कामकाज पर फ़र्क पड़ रहा है. अब ज़रूरत इस बात की है कि सरकार इसे गंभीरता से ले और हस्तक्षेप करके यूएनआई को संकट से बाहर निकालने की कोशिश करे, क्योंकि अगर यूएनआई पर ताला लटकता है, तो यह केवल एक संस्था का अंत नहीं होगा, बल्कि देश के ऐसे सैकड़ों समाचारपत्र भी दम तोड़ देंगे, जो ख़बरों के लिए पूरी तरह से यूएनआई पर ही निर्भर हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

उर्दू सेवा सबसे अव्वल

यूएनआई उर्दू सेवा की शुरुआत 1992 में हुई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हाराव ने 21 जून, 1992 को संसद की एनेक्सी में इसका उद्घाटन किया था. सरकार की ओर से उर्दू सेवा के लिए पहली बार 25 लाख रुपये भी दिए गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उक्त पैसे उर्दू या उर्दू वालों पर ख़र्च नहीं हुए, बल्कि यूएनआई में पहले से मौजूद हिंदी एवं अंग्रेज़ी के स्टॉफ को इस प्रकार बोनस दे दिया गया, जिससे उर्दू एवं उर्दू वालों के साथ भेदभाव का दौर पहले दिन से ही शुरू हो गया. विडंबना तो यह है कि यूएनआई उर्दू सेवा के कर्मचारी जिन कंप्यूटरों पर काम करते हैं, वे भी संस्था की ओर से नहीं मिले, बल्कि एनसीपीयूएल ने अपनी ओर से दान के रूप में दिए हैं. इसके अलावा, 1992 से लेकर अब तक जितने भी कर्मचारी यूएनआई उर्दू सेवा छोड़कर दूसरी जगह गए, उनके पद आज तक नहीं भरे गए. जबकि यूएनआई में अंग्रेजी एवं हिंदी के मुक़ाबले उर्दू सेवा की पहुंच अधिक है. देश के 80 से अधिक उर्दू अख़बार यूएनआई की सेवाएं ले रहे हैं और उसकी ख़बरों को वरीयता एवं महत्व के साथ स्थान देते हैं. यही कारण है कि यूएनआई के हिंदी एवं अंग्रेजी के अधिकतर लोग जब कोई विशेष रिपोर्ट या लेख तैयार करते हैं, तो वे उर्दू सेवा के लोगों के सहयोग से उसे उर्दू अख़बारों में प्रकाशित कराने की कोशिश करते हैं. वजह, उन्हें मालूम है कि हिंदी एवं अंग्रेजी के अख़बारों में उनकी रिपोर्ट या लेख को जगह नहीं मिलेगी. जहां तक उर्दू सेवा से होने वाली आमदनी का सवाल है, तो चूंकि एनसीपीयूएल उन सभी उर्दू अख़बारों को 50 प्रतिशत सब्सिडी देता है, जो यूएनआई से ख़बरें लेते हैं. इस प्रकार यूएनआई उर्दू सेवा की आमदनी में कभी कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसके उर्दू अख़बारों की ओर से उसे हमेशा समय से पैसा मिलता रहा है.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल विस्तार के निहितार्थ निकाले जाएं, तो यह बात साफ़ हो जाती है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव की मंशा को सीएम अलिखेश यादव परवान चढ़ा रहे हैं. मंत्रिमंडल विस्तार के जरिये बेनी प्रसाद वर्मा को घेरने और पिछड़ों पर डोरे डालने के साथ ही प्रदेश के पूर्वी इलाक़ों में पार्टी की जड़ें मजबूत करने की कवायद सपा नेताओं के बीच साफ़ दिखाई दी.

अखिलेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार

विकास का नारा

जातिवाद का सहारा

अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब उनसे प्रदेश के लोगों को बहुतेरी उम्मीदें थी. एक बारगी ऐसा लगा था कि सुबे को जातिय राजनीति से छुटकारा मिलेगा. प्रदेश में एक नई किस्म की सियासत होगी जो युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगी, लेकिन अखिलेश ने परिवारवाद की चपेट में आकर लोगों की आशाओं पर पानी फेर दिया.

अखिलेश की राजनीति में कथनी और करनी का अंतर समाजवादी पार्टी और स्वयं उनके लिए सुखद नहीं कहा जा सकता. प्रदेश की जनता और ख़ासकर युवाओं ने अखिलेश को इसलिए वोट दिया था, क्योंकि उन्होंने साफ-सुथरे विचारों के साथ राजनीति में प्रवेश किया था. उम्मीद थी कि वह प्रदेश की राजनीति का चेहरा बदलने वाले नायक साबित होंगे, दशकों से कोढ़ बन गई जातिवाद की राजनीति से छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन अखिलेश ने अपने कुनबे की सियासी ख्वाहिशों के लिए अपने विचारों की तिलांजलि दे दी.

लालबत्ती नहीं मिलने से नाराज़गी

अखिलेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ विरोध भी शुरू हो गया है. पथरदेवा के सपा विधायक शाक़िर अली ने अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा कि सपा का भाजपा से समझौता हो गया हैं. इसलिए मुझे मंत्री नहीं बनाया गया. भाजपा मजबूत रहेगी, तभी समाजवादी पार्टी मजबूत होगी. पहली बार जीतकर आए आनंद सिंह को मंत्री बना दिया गया. मैं 18 साल से पार्टी में निष्ठा के साथ काम कर रहा हूं, फिर भी मुझे यह ईनाम मिला. यहां तक कि मुझसे किसी ने बात करना भी उचित नहीं समझा.

लालबत्ती आर्थिक बोझ : रालोद

राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के किए गए विस्तार पर कहा कि पूरा प्रदेश बाढ़ के भीषण चपेट में है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबत्ती बांटकर प्रदेश पर आर्थिक बोढ़ बढ़ाते जा रहे हैं. जनता महंगाई की मार से तड़फड़ा रही हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में प्रदेश व देश में 26वें कृषि विकास दर में, 17वें औद्योगिक विकास दर में 20वें तथा साक्षरता के मामले में 22वें स्थान पर हैं. यह तस्वीर है देश के सबसे बड़े राज्य की चाहे आर्थिक हो या सामाजिक हर मानक पर उत्तर प्रदेश साल दर साल पिछड़ता जा रहा है.

मंत्रिमंडल नहीं, नीयत बदलें: भाजपा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विफलताएं छिपाने के लिए अपने मंत्रिमंडल में बदलाव कर रहे हैं. इससे प्रदेश की जनता का भला नहीं हो सकेगा. हर मोर्चा पर फेल साबित रही सपा सरकार तेजी से जनता का भरोसा खो रही हैं. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बसपा के हमराह हो चुके सपाई ख़ुद ही एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं. यादव परिवार का आंतरिक संकट सरकार के कामकाज पर हावी हो चुका है. क़ानून व्यवस्था सुधरने के बजाए दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही हैं. बुनियादी जन सुविधाओं पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है. केवल वोटबैंक का समीकरण सुधारने के लिए सपा नेतृत्व तुष्टीकरण एवं जातिवाद के हथकंडे आजमा रहा हैं.

सपा में हैं सत्ता के कई केंद्र: कांग्रेस

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी का मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में कहना था कि यह एक हताश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार है, जो जान चुकी है कि आने वाले समय में जनता इसे दूर फेंक देगी. त्रिपाठी ने कहा कि इस विस्तार से सपा के भीतर सत्ता के कई केंद्र होने के आरोप की पुष्टि होती है. इस विस्तार में कुछ भी सकारात्मक नहीं है और यह विस्तार एक तरह से सरकारी ख़ज़ाने पर डाका डालने जैसा है.

अजय कुमार

प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 16 महीने के शासन काल में तीसरी बार अपनी टीम (मंत्रिमंडल) को मजबूती प्रदान करने के लिए विस्तार का सहारा लेना पड़ा. वैसे तो मंत्रिमंडल में कौन रहेगा और कौन नहीं, यह तय करना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे प्रदेश पर पड़ता है. इसलिए ऐसे मसलों पर किसी को भी टीका–टिप्पणी करने का अधिकार है. ख़ासकर तब यह और भी ज़रूरी हो जाता है, जब सूबे के सुल्तान जनता के सामने विकास का नारा देते हैं और पीछे से अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए जातिवाद की राजनीति (मंत्रिमडल विस्तार यही संकेत देता है) का सहारा लेते हैं. वह ऐसे क़दम किसी के दबाव में उठाते हैं या फिर टेक्नोटेक सीएम को राजनीति का यह रास्ता (जातिवाद) ज़्यादा सुगम लगता है. अखिलेश की राजनीति में कथनी और करनी का अंतर समाजवादी पार्टी और स्वयं उनके लिए सुखद नहीं कहा जा सकता. प्रदेश की जनता और ख़ासकर युवाओं ने अखिलेश को इसलिए वोट दिया था, क्योंकि उन्होंने साफ–सुथरे विचारों को राजनीति में प्रवेश किया था. उम्मीद थी कि वह प्रदेश की राजनीति का चेहरा बदलने वाले नायक साबित होंगे, दशकों से कोढ़ बन गई जातिवाद की राजनीति से छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन अखिलेश ने अपने राजनीतिक कुनबे की ख्वाहिशों के लिए अपने विचारों की तिलांजलि दे दी. इस बात का एहसास एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार देखने पर हुआ. वह बेनी बाबू की काट तलाशते, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाते, बसपा–कांग्रेस और भाजपा को घेरने, सपा नेताओं की नाराज़गी से बचने, अति पिछड़ों को लुभाने, लोकसभा चुनाव में सपा की नैया पार लगाने के चक्कर में प्रदेश के विकास और क़ानून व्यवस्था की बात भूल गए. इस बात का आगाज मंत्रिमंडल विस्तार के दूसरे दिन आजमगढ़ में बसपा नेता और पूर्व विधायक सर्वेश की हत्या से हो गया कि प्रदेश में आपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल विस्तार के निहितार्थ निकाले जाएं, तो यह बात साफ़ हो जाती है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव की मंशा को सीएम अलिखेश यादव परवान चढ़ा रहे हैं. मंत्रिमंडल विस्तार के ज़रिये बेनी प्रसाद वर्मा को घेरने और पिछड़ों पर डोरे डालने के साथ ही प्रदेश के पूर्वी इलाक़ों में पार्टी की जड़ें मजबूत करने की कवायद सपा नेताओं के बीच साफ़ दिखाई दी. अखिलेश कैबिनेट में शामिल किए गए चारों मंत्री पूर्वी इलाक़े के हैं. इनमें नारद राय को छोड़कर अन्य तीनों पिछड़े वर्ग से आते हैं.

कुछ बातें चौंकाने वाली भी हुईं. अप्रत्याशित तरीक़े से राममूर्ति वर्मा की पदोन्नति की गई है. वर्मा अंबेडकर नगर ज़िले की अकबरपुर विधानसभा सीट से विधायक है. वह दुग्ध विकास राज्य मंत्री थे. उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर उनका राजनीतिक क़द बढ़ाया गया. ऐसा बेनी के चलते किया गया. केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने हाल में ही अंबेडकरनगर के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में इस्पात के एक बड़े कारखाने की नींव रखी थी. इससे सपा के कान खड़े हो गए. अंबेडकर नगर में कुर्मी जाति के मतदाताओं का प्रतिशत अच्छा–ख़ासा हैं. इसीलिए बेनी के अकबरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई थीं. माना जा रहा है कि वर्मा को घेरने और कुर्मी बिरादरी में एक बड़े नेता उभारने की कवायद में राममूर्ति वर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया हैं. सपा 2014 के लोकसभा चुनाव में बेनी को किसी भी तरह जीत से दूर रखना चाहती है. बेनी वर्मा ने हाल के दिनों में अपने राजनीतिक सखा रहे सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर तल्ख टिप्पणियां की थी, जिससे दोनों के संबंध और कड़वे हो गए है. यह और बात है कि चुनावी चिंता में डूबे बेनी ने समय रहते मुलायम के प्रति अपने सुर बदल ज़रूर लिए, लेकिन अभी भी सपा को बेनी पर विश्वास नहीं हुआ है. राममूर्ति वर्मा को प्रोन्नति देकर केंद्रीय इस्पात मंत्री को घेरने की कवायद की गई हैं.

कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले एक अन्य नेता नारद राय राज्य के पूर्वी ज़िला बलिया ज़िले की सदर सीट से विधायक है. भूमिहार जाति का पूरब में अच्छा ख़ासा दबदबा और वोटबैंक है. भूमिहार आमतौर पर किसी पार्टी से प्रतिबद्ध नहीं रहते. इसलिए सपा की इस बिरादरी पर नज़रें काफ़ी समय से लगी थी. मुलायम सिंह यादव ने नारद राय को अखिलेश यादव सरकार में शामिल करवाकर भूमिहार नेतृत्व उभारने और इस जाति को अपनी पार्टी की ओर खींचने की कोशिश की है. तीसरे कैबिनेट मंत्री के रूप में गाजीपुर के कैलाश यादव ने शपथ ली हैं. कैलाश यादव का उनके जिले गाजीपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव हैं. पूरब पर सपा इसलिए ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि यह इलाका बसपा, कांग्रेस और भाजपा के ज़्यादा क़रीब है. बसपा के यहां 21 में से आठ, भाजपा चार तथा कांग्रेस के तीन सांसद हैं. सपा के छह सांसद पूरब से आते हैं. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में शपथ लेने वाले गायत्री प्रसाद प्रजापति को राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी में सेंध लगाने और अति पिछड़ा बिरादरी का ईनाम दिया गया है. कांग्रेस के गढ़ में सपा को ताक़तवर बनाने के लिए प्रजापति का राजनीतिक कद बढ़ाया गया हैं. प्रजापति अति पिछड़ों को सपा के पक्ष में गोलबंद करने के लिए काफ़ी समय से काम कर रहे हैं. सपा इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का भी प्रयास कर रही है. इस संबंध में एक प्रस्ताव केंद्र के पास पड़ा हुआ भी है.

समाजवादी नेताओं के बीच मंथन मोदी को लेकर भी चल रहा है. यह बात भले ही सार्वजनिक रूप से सपाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी के चलते उन्हें कुछ वोट इधर–इधर होने का डर सता रहा है. इसीलिए तीसरे विस्तार को मोदी फैक्टर से भी जोड़कर देखा जा रहा है. विश्लेषकों का मानना है कि नरेंद्र मोदी के कारण अगर मतों का ध्रुवीकरण सांप्रदायिकता के आधार पर होता है तो सपा से मुस्लिम मत कुछ न कुछ खिसकेगा और ऐसी स्थिति में पिछड़े व भूमिहार मतों से इसकी भरपाई की जा सकेगी. इसीलिए इन वर्गों को मंत्रिमंडल विस्तार में महत्व मिला. बुंदेलखंड को मंत्रिमंडल से अछूता रखा गया. यह बात लोगों के समझ में नहीं आई, लेकिन सपा को क़रीब से जानने वालों का कहना है कि बुंदेलखंड में सपा की जड़ें मजबूत करने के लिए ही पूर्व मंत्री और बसपा नेता बाबू सिंह कुशवाहा के भाई और पत्नी को सपा में शरण दी गई है. राज्य के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों की बात की जाए तो इन इलाक़ों में सपा प्रमुख व उनके परिवार का अच्छा ख़ासा प्रभाव है. इसलिए यहां से किसी अन्य नेता को उभारने की जरूरत नहीं समझी गई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सपा अपने मंत्री राजेंद्र चौधरी और राम सकल गूजर के माध्यम से ही साधेगी. बात महिलाओं और युवाओं की कि जाए तो उन्हें भी निराशा हाथ लगी. हाल ही में मुलायम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि महिलाओं की अनदेखी ठीक नहीं है. इसके बाद उम्मीद जागी थी कि अखिलेश के कैबिनेट में महिलाओं की संख्या कुछ न कुछ ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अखिलेश के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले कुछ युवा विधायकों को भी उम्मीद थी कि उन्हें मौक़ा मिलेगा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में पूरी तरह से मुलायम की चली, इसलिए पचास पार के नेताओं को ही लालबत्ती नसीब हो पाई.

समाजवादी पार्टी और सरकार ने काफ़ी फुंक–फुंक कर क़दम उठाए. किसी विवाद से बचने के लिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और परिवारवाद का आरोप न लगे इसलिए मधु गुप्ता को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, जबकि दोनों के शामिल किए जाने की काफ़ी चर्चा थी. जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी को भी मंत्रिमंडल विस्तार से झटका लगा है. वह वैसे तो सपा से नाराज़ चल रहे थे, लेकिन पिछले दिनों गुपचुप तरीक़े से बुखारी ने मुलायम से मुलाक़ात की थी, जिसके बाद यह कहा जा रहा था बुखारी अपने दामाद को मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिये प्रयासरत हैं. तीसरे मंत्रिमंडल विस्तार के साथ अखिलेश कैबिनेट की संख्या 58 हो गई है. अभी भी दो और मंत्री बनाए जाने हैं. कैबिनेट में दो और मंत्रियों को शामिल करने की गुंजाइश छोड़ते हुए अखिलेश ने लोकसभा चुनाव से पहले एक और फेरबदल की चर्चाओं को हवा दे दी हैं. कहा जा रहा है कि जल्द ही एक और फेरबदल हो सकता है, जिसके तहत कुछ नए चेहरों को शामिल करने के साथ साथ कुछ मौजूदा मंत्रियों के पर कतरने के एजेंडे पर भी अमल किए जाने की संभावना है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सपा तमाम मसलों पर केंद्र को घेर रही है. उसने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को मनमर्जी से पेट्रोल–डीजल के दाम बढ़ाने की छूट दे दी है. तेल कंपनियों ने छह हफ्तों में लगातार चौथी बार पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए है. पेट्रोल की क़ीमतों में पहले कुछ वर्षों में, फिर कुछ महीनों में एक बार फिर बढ़ोत्तरी होती थी, लेकिन अब तो हर सप्ताह दामों में उतार चढ़ाव नज़र आता है. पेट्रोल के साथ डीजल के दामों में भी बढ़त होती है, तो ईंधन गैस के भी दाम बढ़ा दिए जाते हैं, इससे माल ढुलाई मंहगी होती है.

सियासी आपदा में बहुगुणा

उत्तराखंड आपदा में हज़ारों लोगों की जानें चली गईं, लेकिन आपदा से पहले मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी प्रदेश सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई. हद तो तब हो गई, जब आपदा के बाद बचाव और राहत कार्यों में भी बदइंतजामी देखने को मिली. अब प्रदेश के मुख्यमंत्री आलाकमान के निशाने पर हैं.

जबर सिंह वर्मा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए प्राकृतिक आपदा सियासी आपदा भी बन सकती है. दरअसल, इस भयंकर त्रासदी से निपटने में प्रदेश सरकार का पूरा तंत्र जिस तरह से नाकाम रहा और मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर राज्य प्रशासन का जो नाकारापन सामने आया है, इससे कांग्रेस हाईकमान बेहद खफा हैं. मुख्यमंत्री की मंत्रियों, विधायकों और पार्टी नेताओं से संवादहीनता और अविश्वास को देखते हुए राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने पहले वरिष्ठ नेता मोती लाल वोरा के नेतृत्व में दिल्ली से कई नेताओं को देहरादून भेजा. तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या समेत कांग्रेस सेवा दल के कई राष्ट्रीय नेताओं को कैंप लगाकर राहत कार्यों में तेजी लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इसके बाद, राहुल गांधी, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से लेकर प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी तक को राहत कार्यों की समीक्षा करने के लिए उत्तराखंड आना पड़ा. उन्हें कांग्रेस सरकार में शामिल मंत्री और विधायकों से लेकर प्रभावित जनता की नाराज़गी भी खूब झेलनी पड़ी. खासकर, सीएम विरोधी खेमे ने उनके पास शिकायतों की खूब झड़ियां लगाईं.

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का ज्यादा समय दिल्ली में बीतना, तबाही वाले दिन भी उनका दिल्ली में ही डेरा डाले रहना, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सीएम द्वारा हवाई सर्वेक्षण करना, 18 जून को देहरादून में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केदारनाथ की तबाही को गंभीरता से न लेना और इसके बाद राहत कार्यों की समीक्षा के लिए कई दिनों तक मंत्रिमंडल की बैठक न बुलाना, राहत कार्यों की निगरानी के लिए मंत्रियों, विधायकों को प्रभावित क्षेत्रों में न भेजना, आपदा राहत की ज़िम्मेदारी पहले ही कई मामलों में विवादों में रहे आईएएस अधिकारी राकेश शर्मा को सौंपने, बिछड़े अथवा मृतकों की संख्या की सही जानकारी नहीं मिलना, संपर्क मार्गों से कटे गांवों की सही सूची तक जारी नहीं होने, सरकार के मंत्री, विधायकों की नाराजगी बार–बार सामने आने जैसे कदमों ने कांग्रेस नेतृत्व का सिरदर्द बढ़ा दिया है.

सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेतृत्व तक यह बात पहुंचा दी गई है कि तबाही की शुरुआत 16 जून की रात से हुई. इसके पहले 13 और 14 जून से ही पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही थी. मौसम विभाग ने भी भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने का अलर्ट जारी कर दिया था. बावजूद इसके, यात्रा जारी रखी गई. जिससे केदारनाथ, यममुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री समेत चारधाम यात्रा मार्गों पर हजारों लोग पहुंचते रहे. चारधाम यात्रा की राज्य सरकार निगरानी तक नहीं कर रही थी. सारा दारोमदार बस और टूर ऑपरेटरों के भरोसे था. चारों धाम कितने यात्री जा रहे थे, इसका तो रिकॉर्ड ही नहीं था.

राहत और बचाव कार्यों में लापरवाही के चलते हो रही किरकिरी और हाईकमान की टेढ़ी होती नज़र को भुनाने में अब बहुगुणा के धुरविरोधी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री हरीश रावत और उनके समर्थक भी एक बार फिर गुर्राने लगे हैं. अपनी सरकार के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोल चुके ये नेता आपदा आने के बाद शांत हो गए थे, लेकिन अब राहत और बचाव कार्यों में घोषणाओं के मुताबिक तेजी नहीं आने का मसला उठाते हुए एक बार फिर इस गुट के सांसद, विधायकों ने सीएम के विरोध में

झंडा थाम लिया है. कांग्रेस के ही धारचूला विधायक हरीश धामी ने राज्य सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए तहसील प्रांगण में धरना शुरू कर दिया है, जबकि सर्वाधिक आपदा प्रभावित केदारनाथ क्षेत्र से कांग्रेस की ही दूसरी विधायक शैलारानी रावत प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी और मुख्यमंत्री के सामने ही अपने क्षेत्र की अनदेखी होने पर धरने पर बैठने की चेतावनी दे चुकी हैं. उनका आरोप है कि केदारनाथ क्षेत्र में करीब एक हजार स्थानीय लोग आपदा में मरे. सैकड़ों दुकानें–मकान बहे हैं, लेकिन उनके बार–बार कहने के बावजूद सीएम कोई सुध नहीं ले रहे. स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल भी फंसे लोगों को निकालने में प्रशासन की ढिलाई पर रोश जता चुके हैं. सांसद प्रदीप टम्टा अपने संसदीय क्षेत्र में राहत और बचाव सामग्री नहीं पहुंचाने को लेकर मुखर हैं, जबकि राज्यपाल अजीज कुरैशी भी आपदा से निपटने में बहुगुणा सरकार के इंतजामों पर टिप्पणी कर चुके हैं.

आपदा से निपटने में बहुगुणा सरकार की नाकामी का मसला उनके विरोधी हाईकमान तक लगातार पहुंचा रहे हैं. इन नेताओं ने प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी से मुलाकात करके भी अपनी नाराजगी जाहिर की. हालांकि, शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें फिलहाल संयम बरतने की नसीहत देते हुए भरोसा दिया है कि राहत और बचाव अभियान खत्म होने के बाद इनकी शिकायतों पर सुनवाई होगी. इससे फिलवक्त स्थिति संभली हुई दिख रही है. प्रदेश सरकार के मुखिया की सुस्ती और भाजपा के मुख्यमंत्रियों समेत उत्तराखंड में उनके नेताओं की सक्रियता ने भी कांग्रेस हाईकमान की नींद उड़ा रखी है. शासन–प्रशासन की खस्ताहालत की वजह से आपदा से निपटने के लिए केंद्र से मिली एक हजार करोड़ की राहत राशि का सही उपयोग भी हो सकेगा या नहीं. इसे लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व को संशय है. यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोर शोर से उठ रही है कि यह प्राकृतिक आपदा विजय बहुगुणा के लिए सियासी आपदा साबित होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

तू डाल-डाल, मैं पात-पात

राजनीति में न तो कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और न ही दुश्मन. यह बात सपा, बसपा और कांग्रेस के राजनीतिक सौदेबाजी को लेकर आपसी तिकड़मों से साबित हो जाती है. ये पार्टियां जो नाटक रच रही हैं, वह जनता के दिखावे और दबाव की राजनीति से ज़्यादा कुछ भी नहीं.

संजय सक्सेना

समाजवादी पार्टी एक तरफ केंद्र की यूपीए सरकार को अपनी बैशाखी का सहारा दे रही है, तो दूसरी तरफ इसे कोसने का कोई मौक़ा भी नहीं छोड़ रही है. यही हाल कांग्रेस का है, वह समाजवादी पार्टी और बसपा से समर्थन भी ले रही है. और दोनों की जड़ो में मट्ठा डालने का भी काम कर रही है.कई मुद्दों पर तीनों दलों के बीच गहरा मतभेद दिखाई दे रहा है.बस फर्क इतना है कि समाजवादी नेता अपनी नाराजगी का इजहार खुले आम कर रहे हैं, वहीं बसपा नेत्री दबी जुबान इस्तेमाल कर रही हैं.यही वजह है यूपीए–2 में समाजवादी पार्टी के मुकाबले बसपा को कांग्रेस अपने ज्यादा करीब पा रही है.कहा यह भी जा रहा है कि मुलायम का प्रधानमंत्री बनने का सपना कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ती खाई की मुख्य वजह बनता जा रहा है, जबकि मायावती अपने आप को प्रधानमंत्री की रेस से दूर रखे हुए हैं, भले ही मौका देखकर वे करवट बदलने से बाज नहीं आएंगी, यह राजनीति का नियम भी है. यहां वफादारी और बेवफाई का सिलसिला एक साथ चलता हैं.

समाजवादी पार्टी सभी मोर्चो पर केंद्र सरकार और कांग्रेस को घेर रही है. लगता है सपा मानसून सत्र से पहले कांग्रेस पर अधिक से अधिक दबाव बना लेना चाहती है, ताकि कांग्रेस को कुछ मुद्दों पर झुकाया जा सके. इसी सोच के चलते सपा नेताओं ने राग अलापना शुरू कर दिया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस से दिल्ली की कुर्सी छिन जानी है. जनता त्रस्त है और देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है. सीमाएं असुरक्षित है. घरेलू मोर्चे पर भी केंद्र की यूपीए सरकार का रिजल्ट कार्ड बहुत ख़राब है. इससे क्षुब्ध और कुंठित कांग्रेस जाते–जाते जनता को गहरे आघात देने का मन बना चुकी है. मंहगाई और भ्रष्टाचार को खुली छूट दे दी गई है, ताकि आम आदमी जीते जी मृतप्राय हो जाए. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने हाल में ही चालू सत्र की पहली

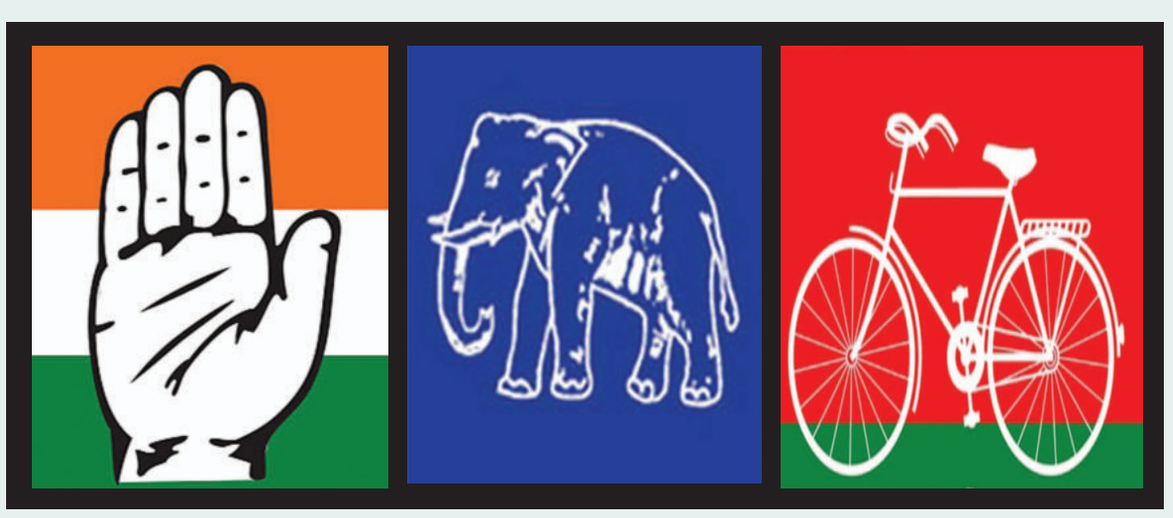

तिमाही में मनरेगा के पैसे के कम खर्च के लिये राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ा, तो सपा–कांग्रेस में तकरार शुरू हो गई है. जयराम नरेश ने मनरेगा में लापरवाही का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाते हुए मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था. इस पर उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) अरविंद सिंह गोप ने जबावी हमला करते हुए यहां तक बोल दिया कि जयराम रमेश झूठ बोल रहे हैं. अन्य राज्यों की अपेक्षा उप्र में मनरेगा की प्रगति चौथे नंबर पर है. गोप ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र की वजह से मनरेगा कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है.

सपा तमाम मसलों पर केंद्र को घेर रही है. उसने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को मनमर्जी से पेट्रोल–डीजल के दाम बढ़ाने की छूट दे दी है. तेल कंपनियों ने छह हफ्तों में लगातार चौथी बार पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं. पेट्रोल की क़ीमतों में पहले कुछ वर्षों में, फिर कुछ महीनों में एक बार बढ़ोत्तरी होती थी, लेकिन अब तो हर सप्ताह दामों में उतार चढ़ाव नज़र आता है. पेट्रोल के साथ डीजल के दामों में भी बढ़त होती है, तो ईंधन गैस के भी दाम बढ़ा दिए जाते हैं, इससे माल ढुलाई मंहगी होती है. गैस के दाम बढ़ने से घरेलू बजट अस्त व्यस्त होता है. कांग्रेस के सांसद और पूर्व नौकरशाह पीएल पुनिया ने सपा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को विकास, अमन और खुशहाली दी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ग़ैर कांग्रेसी सरकारों ने प्रदेश में विकास और तरक्की के रास्तों को अवरुद्ध करके यहां जातिवाद का विष फैला दिया.

बहरहाल, सपा के अरोपों को अनदेखा नहीं किया जा सकता. खुद सरकारी आंकड़े बताते है कि मंहगाई जून में बढ़कर 486 फीसदी हो गई, जो कि मई में 470 फीसदी थी. जून में खाद्य उत्पादों के थोक मूल्य सूचकांक में 974 फीसदी की वृद्धि अंकित की गई है. प्याज और सब्ज़ी की कीमतें तो आसमान छूने लगी है. प्याज की क़ीमतों में जून, 2013 में 114 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. सब्ज़ियों की मंहगाई दर जून, 2013 में

समाजवादी पार्टी सभी मोर्चों पर केंद्र सरकार और कांग्रेस को घेर रही है. लगता है सपा मानसून सत्र से पहले कांग्रेस पर अधिक से अधिक दबाव बना लेना चाहती है, ताकि कांग्रेस को कुछ मुद्दों पर झुकाया जा सके. इसी सोच के चलते सपा नेताओं ने राग अलापना शुरू कर दिया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस से दिल्ली की कुर्सी छिन जानी है. जनता त्रस्त है और देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है. सीमाएं असुरक्षित है. घरेलू मोर्चे पर भी केंद्र की यूपीए सरकार का रिजल्ट कार्ड बहुत ख़राब है.

1647 बढ़ी, जो मई, 2013 में 485 प्रतिशत थी. चावल की मंहगाई दर जून में क्रमश: 1718 और 1911 प्रतिशत थी, जो मई, 2013 में 1601 तथा 1848 प्रतिशत थी.

सपा की बातों में दम लगता है. देश में कथित अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रहते भी रुपए की क़ीमत में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है. रुपया डालर के मुक़ाबले गिरकर 6121 के निम्न स्तर पर पहुंच गया है. निर्यात में 46 फीसदी और औद्योगिक उत्पादन में 16 प्रतिशत की गिरावट आने से देश की अर्थव्यवस्था की चिंताजनक स्थिति का प्रदर्शन होता है. वित्तमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ रिजर्व बैंक के गवर्नर सुब्बाराव की बैठकें भी बेनतीजा साबित हो रही हैं. देश में बढ़ती मंहगाई पर संसद में मुलायम सिंह यादव ने केंद्र सरकार से डॉ. राम मनोहर लोहिया की दाम बांधों नीति अपनाने का आग्रह किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इनके सुझावों पर ध्यान नहीं दिया. नतीजा सामने है. देश दुनिया के सामने भारत की किरकिरी हो रही हैं. देशवासी बुरी तरह परेशान हैं और दुश्वारियों में घिरे हैं. कितने ही ग़रीबों ने कुपोषण और किसानों ने बदहाली के चलते अपनी जानें गवाई है.

इधर, बात बसपा की कि जाए, तो बसपा सुप्रीमो मायावती आगे से कांग्रेस के लिए ज़्यादा मुफीद साबित हो रही हैं. तुनकमिजाजी के चलते पल भर में गंठबंधन तोड़ने और साथ छोड़ने में देरी नहीं करने वाली माया ने अब प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे को छोड़कर किसी भी मसले पर यूपीए सरकार के सामने मुश्किल खड़ी नहीं की. इसलिए कांग्रेसी उन पर मुलायम के मुक़ाबले ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं. माया का पीएम रेस में खुले तौर पर शामिल नहीं होना भी कांग्रेस को भला लग रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

जनतंत्र यात्रा

सामाजिक और व्यवस्था परिवर्तन के मसले पर अन्ना हजारे की देश भर में यात्रा जारी है. इसी क्रम में अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंची, जहां उन्हें अपार जनसमर्थन हासिल हुआ. उत्तर प्रदेश में अन्ना जहां-जहां से गुजरे, वहां-वहां के लोगों ने अन्ना को उनकी मुहिम में अपना साथ देने का वायदा किया.

इफ्तार पार्टी

चौथी दुनिया ने 22 जुलाई को दिल्ली के कांस्टीट्यूशनल क्लब में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया. इसमें अन्ना हजारे सहित कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की. प्रख्यात राजनीतिज्ञों, लेखकों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की मौजूदगी ने पार्टी को रौनक बख्शी.

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

मर्यादा में रहना ज़रूरी है

बिहार का मिड डे मील हो या नरेंद्र मोदी का अमेरिकी वीजा से जुड़ा मुद्दा, दोनों ही घटनाएं चिंता का कारण हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम अपने व्यवहार को भ्रमित करें. हमें संसदीय गरिमा के अनुकूल रहना होगा, साथ ही शिष्टता व सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका को बेहतर बनाए रखना होगा, क्योंकि हमारा देश इन्हीं आदर्शों के लिए जाना जाता है. हमें इसे नहीं खोना चाहिए.

पिछले सप्ताह दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं. हालांकि उन घटनाओं की प्रकृति एक-दूसरे से अलग हैं, लेकिन दोनों ही चिंता का कारण हैं. पहली घटना है, बिहार में मिड-डे-मील कार्यक्रम के तहत परोसे गए ख़राब भोजन के कारण 23 स्कूली बच्चों की मौत. प्रथम दृष्टतया ऐसा लगा कि यह महज एक दुर्घटना थी, जो परोसे गए भोजन में कीटनाशक मिले होने के कारण घटी, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए-नए ख़ुलासे हो रहे हैं. स्कूल प्रभारी की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि ये मौतें महज दुर्घटनावश नहीं हुई हैं. इसका मतलब, यह मामला कहीं ज़्यादा गंभीर है.

इससे जाहिर होता है कि इस कार्यक्रम में जानबूझ कर अनियमितताएं बरती जा रही हैं. कुछ लोग इन योजनाओं को लोगों की, विशेषकर बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल कर पैसा बनाने का माध्यम बता रहे हैं. बिहार की इस घटना के बाद दूसरे अलग-अलग राज्यों से मिड-डे-मील कार्यक्रम को लेकर ऐसी ही घटनाओं की ख़बरों का आना यह साबित करता है कि पिछले कई वर्षों से मिड-डे-मील कार्यक्रम संगठित रूप से कुप्रबंधन का शिकार है. देश में जिस तरह से घोटालों और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है, करोड़ों की लागत से चलाया जा रहा यह मिड-डे-मील प्रोग्राम भी उसी भ्रष्टाचार का शिकार बन गया है. यहां सवाल यह उठता है कि अब इसे बेहतर बनाने के लिए क्या क़दम उठाए जा सकते हैं. क्या इसे बंद कर कोई अलग कार्यक्रम शुरू किया जाए या इसी कार्यक्रम को जारी रखते हुए भोजन न देकर सख्त विनियमन के तहत सीधा नक़द लाभ दिया जाए. इस तरह के सुझाव आ रहे हैं. बावजूद इसके, एक बात तो स्पष्ट है कि ऐसा कुछ ज़रूर होना चाहिए, जिससे यह घटना फिर से दोहराई न जा सके, क्योंकि आप तो पैसे ख़र्च कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम बच्चों की मौत के रूप में सामने आ रहा है. यह निश्चित रूप से अस्वीकार्य है.

कुछ राज्यों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं हैं. सबसे पहले यह कार्यक्रम तमिलनाडु में शुरू हुआ, लेकिन कुछ राज्यों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और उन राज्यों ने बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किए बिना इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी. भले ही इस कार्यक्रम के लिए केंद्र पूंजी दे रहा है, लेकिन सभी राज्य एक ही मॉडल के साथ नहीं चल सकते. यह मॉडल हर राज्य में अलग-अलग होना चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस राज्य की क्षमता कितनी है और वहां का प्रशासनिक स्तर क्या है?

दूसरा मसला, जो इतना गंभीर नहीं है, लेकिन विचलित ज़रूर करता है, वह है नरेंद्र मोदी का अमेरिकी वीजा से जुड़ा मुद्दा. इस बात को लेकर दो तरह की बहस हो सकती है. कोई भी यह तर्क दे सकता है कि भारत में किसी भी राज्य के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को अमेरिका के लिए वीजा से इंकार नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका के किसी राज्य के गवर्नर से आप भले ही सहमत हों या असहमत हों, लेकिन उन्हें भारत का वीजा देने से इंकार नहीं किया जा सकता. कई वर्ष पहले भी वीजा के लिए इंकार किया गया था, तब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उसने कोई विरोध नहीं किया था, जबकि केंद्र सरकार इस मसले पर अमेरिका का विरोध कर सकती थी. हम भी नरेंद्र मोदी से असहमति रखते हैं, लेकिन किसी का अमेरिका जाना बहुत ही छोटा मसला है और नरेंद्र मोदी उन लोगों में शामिल भी नहीं हैं कि जो अमेरिका जा रहे हैं और वहां के प्रशासन को उनकी यात्रा को लेकर इस क़दर सजग होना पड़े कि उनको वीजा देने से ही इंकार कर दिया जाए. हालांकि असल मुद्दा यह नहीं है. इसके अलावा, दो बातें ऐसी हैं, जो परेशान करने वाली हैं.

क्या इस देश के सांसदों का यह काम है कि वे अमेरिकी प्रशासन को याचिका भेजें? आप अपना अवमूल्यन कर रहे हैं. आप इस देश की संसद का अवमूल्यन कर रहे हैं. मैं यह नहीं जानता कि प्रधानमंत्री इस मसले पर क्या सोचते हैं, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि प्रधानमंत्री को अब जरूर कोई कदम उठाना चाहिए. यह वह मौका है, जब वह देश के प्रधानमंत्री की तरह कोई फैसला लें.

सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जब अमेरिका जाते हैं और प्रेस को यह बयान देते हैं कि मैं अमेरिकी प्रशासन से यह निवेदन कर रहा हूं कि वह नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा दे. क्षमा कीजिएगा, यह कहीं से किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व नहीं है. वीजा के लिए व्यक्तिगत रूप से आवेदन किया जाना चाहिए. हां, अगर इस विषय में किसी को अमेरिकी सरकार से बात करने की ज़रूरत भी पड़ती है, तो वह भारत सरकार है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष. इस तरह से तो आप अमेरिकी सरकार के सामने ख़ुद को नीचा दिखा रहे हैं. दूसरी बात यह है कि 65 सांसद इस आशय की याचिका लिख रहे हैं कि कृपया वीजा का मना करना जारी रखिए. ये सांसद कौन हैं? भाजपा का विरोध करने वाले अन्य दलों के लोग? उनमें से 19 लोगों ने तो यह कह दिया कि हमने ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, क्या उन्होंने इस बारे में सोचा कि वे क्या कर रहे हैं? क्या इस देश के सांसदों का यह काम है कि वे अमेरिकी प्रशासन को याचिका भेजें? आप अपना अवमूल्यन कर रहे हैं. आप इस देश की संसद का अवमूल्यन कर रहे हैं. मैं यह नहीं जानता कि प्रधानमंत्री इस मसले पर क्या सोचते हैं, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि प्रधानमंत्री को अब ज़रूर कोई क़दम उठाना चाहिए. यह वह मौक़ा है, जब वह देश के प्रधानमंत्री की तरह कोई फ़ैसला लें. प्रधानमंत्री को अवश्य उन सांसदों को बताना चाहिए कि यह आपका दायित्व नहीं है. आपकी भूमिका यह है कि आप संसद में बहस करें, जहां से प्रायः वे गैरहाजिर रहते हैं. वे अपना वेतन ले रहे हैं, अन्य सुविधाएं ले रहे हैं, उनके पास संसद में मौजूद रहने का समय नहीं है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन को याचिका लिखने का समय है. निश्चित तौर पर उन्हें तर्कसंगत व्यवहार करना होगा. चुनाव नजदीक आ रहा है और जैसा कि मैं समझता हूं कि राजनीतिक पार्टियों में गुस्सा है. बहुत से मसलों पर मेरा भी मतभेद है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम अपने व्यवहार को भ्रमित करें. हमें संसदीय गरीमा के अनुकूल रहना होगा, साथ ही शिष्टता व सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका को बेहतर बनाए रखना होगा, जिसके लिए हमारा देश स्वतंत्रता के समय से ही जाना जाता है. मेरा मानना है कि हमें इसे नहीं खोना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

शंका-समाधान

ठाकुर दास बंग

भारत के दारिद्र का तथा उसके निवारण के लिए हमने अब तक आंदोलन-संबंधी जो विवेचन किया, उसका मुख्य हिस्सा लोगों को जंच जाता है, लेकिन कुछ शंकाएं दिमाग में उठती रहती हैं. एक प्रश्न यह किया जाता है कि इस किसान-आंदोलन में मजदूर क्यों शामिल होंगे? वाजिब दाम मिलने से किसानों को शक्ति बढ़ेगी और उससे मजदूर का शोषण बढ़ सकता है, यह तर्क भी यदा-कदा उछाला जाता है. इसका उत्तर साफ है. यह आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन नहीं है. इस आंदोलन के उद्देश्य में किसान को लागत-ख़र्च पर आधारित उचित दाम, मजदूर को जीवन-यापन के लिए आवश्यक उचित मजदूरी, कारीगर को गांव में पूरा काम और उपभोक्ता को वाजिब दाम में शुद्ध वस्तु की आपूर्ति-इन चारों का यह सम्मिलित यानी पैकेज कार्यक्रम है. चूंकि मजदूरों को उचित मजदूरी मिले, यह इस आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा है, अतः मजदूरों को इसमें शामिल होने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी. कई किसान-नेताओं ने मजदूरों की वाजिब मजदूरी को अपने आंदोलन के उद्देश्यों में दाखिल भी किया है. जैसे-महाराष्ट्र कपास उत्पादक संघ ने ऊपर की मांगों को लेकर आंदोलन चलाया है और बढ़ाई हुई मजदूरी के आधार पर लागत-खर्च गिन कर कपास के लिए उचित दाम की मांग की है. इसलिए बढ़ाई हुई मजदूरी इस आंदोलन की मांग का एक अंग हो गया है. अनुभव भी यह बतलाता है कि एक बार किसानों को उचित दाम मिले, तो मजदूरी भी बढ़ जाती है. न बढ़ी, तो मजदूर आंदोलन करके उसे ले सकते हैं. उस समय आर्थिक न्याय चाहने वाले सब लोग मजदूरों की जायज मांग के लिए चलाए जानेवाले आंदोलन में शामिल होंगे, यानी इसमें कई किसान भी शामिल होंगे. इसलिए यह प्रश्न समाप्त हो जाता है. कोई यह नहीं कहता कि आज मजदूर-किसान में मनमुटाव या संघर्ष नहीं है, लेकिन इन दोनों को उनका हक़ मिले, इसलिए यह ज़रूरी है कि कृषि के उत्पादन को वाजिब मूल्य मिलना चाहिए. अन्यथा कल का बड़ा किसान आज छोटा किसान और आने वाले कल में मजदूर बनेगा, यह बताने के लिए ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है.

किसान को वाजिब दाम देने से कच्चे माल के भाव बढ़ेंगे. फलस्वरूप पक्के माल के दाम बढ़ेंगे. इससे कृषि उपज का उत्पादन-खर्च बढ़ेगा और कृषि-उपज के भाव और बढ़ाने होंगे. अतः एक दुश्चक्र निर्माण होगा और महंगाई बढ़ेगी. अतः किसान को वाजिब दाम दिए जाने से महंगाई बढ़ेगी, यह हौवा खड़ा किया जाता है. नागपुर के किसान-नेता डॉ. बोकरे ने पक्का माल बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से ही आंकड़े लेकर निम्न तथ्य प्रकाश में लाए हैं:

वस्तु का नाम	उत्पादन ख़र्च	क़ीमत
चाय	21-50 प्रति किलो	28-00 प्रति किलो
चीनी	2-10 प्रति किलो	8-00 प्रति किलो
मुंगफली तेल	7-78 प्रति लीटर	27-00 प्रति लीटर
सिंथेटिक कपड़ा	4-48 प्रति मीटर	25-00 प्रति मीटर
सूती कपड़ा	3-00 प्रति मीटर	6-00 प्रति मीटर

बिहार में आलू का लागत-खर्च गत वर्ष 62-50 रुपया प्रति कुंतल आया था. उत्पादकों ने उसे 55 रुपया प्रति कुंतल की दर से बेचा. उसे तीन महीने शीतगृह में रखने पर उपभोक्ता को वह 142 रुपया प्रति कुंतल बेचा गया. इन आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि कई वस्तुओं की कीमत कम कर के ही उत्पादक को मूल्य अधिक दिया जा सकता है. कई वस्तुओं के बारे में शायद कीमत कम न की जा सके, लेकिन वह बढ़ेगी भी नहीं. सचमुच पक्के माल के उत्पादन-खर्च में कच्चे माल की कीमत का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है. कपड़े में कपास की कीमत 10 प्रतिशत है. अतः कच्चे माल की कीमत बढ़ जाने से कारखाने के मालिक को या व्यापारियों को अपना मुनाफा थोड़ा-सा घटाना होगा, इतना ही फर्क पड़ेगा. वास्तव में कृषि-माल के भाव न बढ़ने पर भी या नाममात्र बढ़ने पर भी पक्के माल की कीमतें आकाश को छू रही हैं. कपास की कीमत पिछले पांच-सात वर्षों में विशेष नहीं बढ़ी, कभी-कभी तो घटी. इसी अवधि में कपड़े की कीमतें दुगुने से ज्यादा बढ़ गईं. रासायनिक खाद की कीमतें, कीटनाशकों की कीमतें कई गुना बढ़ गईं. इस महंगाई के दुष्परिणामों को देहाती सहन कर ही रहा है, लेकिन इसके लाभ से वह वंचित रखा गया है. मुद्रास्फीति न हो, इसलिए किसान लागत से कम भाव स्वीकार करे और हमेशा घाटे में खेती चलाए, यह निष्कर्ष निकलता हो, तो 80 प्रतिशत भारतीयों के हितों को 20 प्रतिशत के स्वार्थ पर न्योछावर करनेवाली अर्थ-व्यवस्था जितनी जल्द समाप्त हो, उतना अच्छा. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

किसके सिर बंधेगा सेहरा

22 जुलाई, 2013 की आवरण कथा-कौन कछुआ, कौन खरगोश पढ़ी, अच्छी लगी. यह भी पता चला कि चौथी दुनिया किस तरह ख़बरों की नब्ज पकड़ कर बेबाकी से अपनी राय देता है. हालांकि मीडिया में कयास लगाने का काम धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन ऐसा कयास, जो सच साबित हो जाए, तारीफ़ के काबिल है. इससे पहले भी मैंने चौथी दुनिया की कई रिपोर्ट्स पढ़ीं, जो बाद में सच साबित हुईं, जैसे टूजी घोटाला, कोयला घोटाला, आईपीएल घोटाला आदि. बकौल लेखक, राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल 2014 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कर रहे हैं. अगर यह बात सच है, तो क्या इसका एहसास नरेंद्र मोदी को नहीं है? अगर है, तो फिर वह अगुवाई क्यों कर रहे हैं चुनाव प्रचार अभियान का? लेखक के अनुसार, चुनाव बाद अगर भाजपा सत्ता में आई, तो नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री होंगे. अगर ऐसा होता है, तो क्या जनता अपने आपको ठगा हुआ महसूस नहीं करेगी, जो नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर वोट करेगी? खैर, यह देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में जनता किसके सिर सेहरा बांधती है.■

-सैफी, मुंगेर, बिहार.

भ्रष्ट है सरकार

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-भारत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, पढ़ा. मैं लेखक की बातों से पूरी तरह सहमत हूं. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. अगर विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग बंटकर रहने लगेंगे, तो देश गर्त में चला जाएगा. लेखक ने कहा कि मुसलमानों का एक वर्ग अपनी मांगें शांतिपूर्ण तरीके से नहीं उठाता, बल्कि वह हिंसात्मक तरीक़ा अपनाता है. देश का कोई भी नागरिक इस तरीके को गलत ही मानेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. हालांकि इस सत्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि सरकार और उसके महकमे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं. ऐसे में उनका ध्यान जनता और उसकी परेशानियों पर नहीं जाता. परिणाम यह होता है कि परेशान लोग हथियार उठा लेते हैं या गलत लोगों के हाथों में पड़ जाते हैं. सरकार को चाहिए कि वह लोगों की मांगें ध्यान से सुने और उनका उचित समाधान निकाले. इंसाफ पाने की आस में लोग अदालत के चक्कर लगाते रहते हैं. उन्हें खाकी वर्दी देखकर आज भी डर लगता है. सच बात तो यह है कि वोट के लिए हर पार्टी मुसलमानों के साथ सियासत कर रही है.■

-निशांत, पटना, बिहार.

क्या सचमुच दंगे होने वाले हैं

पिछले दिनों चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-दंगे होने वाले हैं, पढ़ा. कहीं न कहीं सच्चाई ज़रूर है, क्योंकि चुनाव से पहले शीर्ष नेताओं के बयान और बोधगया बम विस्फोट कुछ यही इशारा करते हैं. चुनाव से पहले अक्सर देश में माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है. गुजरात दंगा मोदी के प्रधानमंत्री बनने की राह में कांटा बन चुका है. बाबरी विध्वंस ने उत्तर प्रदेश में भाजपा एवं कांग्रेस की तकदीर लिख दी है. भागलपुर दंगे ने बिहार से कांग्रेस की विदाई कर दी. दरअसल, नेताओं को समझना होगा कि यह युवाओं का देश है. आज विकास की राजनीति होनी चाहिए, जबकि हो रही है विनाश की राजनीति. जनता को भी चाहिए कि वह मंदिर-मस्जिद जैसे मुद्दों में उलझ कर देश को पीछे न धकेले और चुनाव के समय अपने वोट का सदुपयोग करके उन लोगों को संसद में भेजे, जो देश के विकास के लिए काम कर सकें.■

-विनय, सहरसा, बिहार.

दीर्घकालीन योजनाएं ज़रूरी

प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए अल्पकालीन योजनाओं से कोई भला नहीं होने वाला, बल्कि इसके लिए दीर्घकालीन योजनाओं की ज़रूरत है. दीर्घकालीन योजनाओं में तीन प्रमुख तत्व होने चाहिए. सर्वप्रथम इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तत्काल योजनाओं की ज़रूरत होगी. दूसरी बात यह कि आपदा से जुड़े जोखिमों का सही आकलन करना होगा. तीसरी बात, विकास के जुड़े पर्यावरण को कोई नुक़सान न हो, यानी सतत् विकास का ढांचा तैयार हो. दरअसल, विकास के नाम पर पर्यावरण का दोहन होता आया है. यही कारण है कि 35 सेंटीमीटर वर्षा से यह हालत उत्पन्न हो गई, जबकि इससे पहले 50 सेंटीमीटर वर्षा से भी कुछ नहीं होता था. सच तो यह है कि जिस हिसाब से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, उस हिसाब से बुनियादी ढांचे का समुचित विकास नहीं हुआ.

- अशोक, दरभंगा, बिहार.

अलग राज्य सिर्फ़ लूट का जरिया

चौथी दुनिया के पिछले अंक में अलग तेलंगाना मुद्दे पर एक रिपोर्ट पढ़ी. रिपोर्ट में कुछ नया तो नहीं था, पर तेलंगाना पर पूरा विवरण मौजूद था. सवाल यह उठता है कि क्या अलग राज्य जनता के हित में है या फिर इससे केवल मंत्रियों की कुर्सी में इजाफा होगा? बड़ा सवाल यह उठता है कि जिन राज्यों का गठन हुआ, क्या उनका विकास हो पाया है? सच्चाई तो यह है कि राज्यों के गठन से केवल लूट की आज़ादी मिली है. झारखंड इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है.■

-चंद्रभूषण, मधुबनी, बिहार.

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें:
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

भाजपा को सच बोलना चाहिए

यह देश आज़ादी के बाद से सांप्रदायिकता के आग में जल रहा है. हमेशा लगता है कि न जाने कब दंगा हो जाए. हमेशा लगता है कि न जाने कब असुरक्षा का माहौल बन जाए और इसी वातावरण में विदेशी ताक़तें अपना खेल दिखा जाती हैं. पड़ोसी देश से आए पैसे और हथियार हमारे देश को परेशान कर जाते हैं. हथियार और पैसे सिर्फ़ पड़ोसी देश से नहीं आते, हथियार और पैसे उन देशों से भी आते हैं जो हमारे पड़ोसी नहीं है, लेकिन जिनका स्वार्थ हमारे देश की अस्थिरता में है.

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को भारतीय जनता पार्टी को ये सलाह देना चहिए कि वो देश के लोगों से ये कहे कि अगर देश के लोग अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें. उसे ये भी सलाह देनी चाहिए कि सिर्फ़ अयोध्या में ही नहीं, अगर मथुरा और काशी में मस्जिदों को हटा कर सारी जगह कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ मंदिर को देनी है तो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को ये भी भाजपा के द्वारा घोषित करवाना चाहिए कि धारा 370 कॉमन सिविल कोड अगर देश के लोग चाहते हैं तो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और आख़िर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को ये फ़ैसला लेना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के लोगों से कहे कि अगर दोनों कश्मीर का मसला हल करना है और उन्हें भारत में मिलाने की स्पष्ट घोषणा करनी है तो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें.

मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को इससे भी बढ़कर फ़ैसला लेना चाहिए और वो फ़ैसला है कि वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के लोगों से कहे कि अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें. और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बिना किसी से समझौता किए हुए आरएसएस के नीतियों के ऊपर चलकर लोगों से वोट देने की अपील करनी चाहिए. ये इसलिए आवश्यक है कि 60 साल बीत गए, संघ के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता दृश्य से हट गए. नए नेता आ रहे हैं और जो नए लोग आ रहे हैं, वो लोग संघ के बुनियादी विचारधारा में भरोसा नहीं करते. अब ख़ुद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग भी अपनी बुनियादी विचारधारा में भरोसा नहीं करते. उनकी शाखाएं कम हो रही हैं, लोग शाखाओं में उस उत्साह के साथ जाते नहीं हैं और अब संघ के निष्ठावान स्वयंसेवकों के लड़के भी मॉल कल्चर और डिस्को कल्चर को पसंद करने लगे हैं. इसीलिए अगर इस बार स्पष्ट घोषणा नहीं होती है, तो संघ के बचे खुचे भारतीय जनता पार्टी के जीवित, लेकिन निष्ठावान पर बेअसर नेता इसी तरह दुनिया से विदा हो जाएंगे. अगर भाजपा इन नीतियों पर घोषणा कर चुनाव लड़ती है तो उनका यह देश के ऊपर एक तरह से उपकार होगा.

यह देश आज़ादी के बाद से सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है. हमेशा लगता है कि न जाने कब दंगा हो जाए, न जाने कब असुरक्षा का माहौल बन जाए. इसी वातावरण में विदेशी ताक़तें अपना खेल दिखा जाती हैं. हमारे पड़ोसी देश से आए पैसे और हथियार हमारे देश को परेशान कर जाते हैं. हथियार और पैसे सिर्फ़ पड़ोसी देश से नहीं आते, हथियार और पैसे उन देशों से भी आते हैं जो हमारे पड़ोसी नहीं है, लेकिन जिनका स्वार्थ हमारे देश की अस्थिरता में है.

इस बात का फ़ैसला होना आवश्यक है कि देश के लोग हिंदू के नाम पर सांप्रदायिक नीतियों में भरोसा करते हैं या नहीं. अगर देश इन घोषणाओं के समर्थन में खड़ा होता है और लोकसभा में तीन सौ के आस पास भारतीय जनता पार्टी के सदस्य चुनकर पहुंचते हैं तो मान लेना चाहिए कि देश के लोग मुसलमानों समेत सभी अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पक्ष में हैं. पर अगर ऐसा नहीं होता है और इन घोषणाओं के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सीटें 80 से 140 के बीच में आती हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को ये वायदा करना चाहिए कि वे अपनी उन नीतियों छोड़ देंगे, जिन पर देश से उन्होंने राय मांगी थी और देश ने उनका समर्थन नहीं किया.

दरअसल, इस देश को अगर बर्बादी से बचाना है, देश को अगर धर्म और जाति के भूल भूलैया से निकालकर, सर्वांगिण विकास की सीधी रोड पर चलाना है तो एक बार इसका फ़ैसला होना ज़रूरी है. आज़ादी के बाद से ही हम डर के माहौल में रह रहे हैं. मुसलमान एक खौफ की जिंदगी जी रहे हैं.

मुसलमानों का कहना है कि उन्हें ना रोजगार में हिस्सा मिल रहा है, न शिक्षा में हिस्सा मिल रहा है, न व्यापार में हिस्सा मिल रहा है और न देश के राजनीति में हिस्सा मिल रहा है. जब इतनी चीजों में हिस्सा नहीं मिल रहा है तो देश की अर्थनीति में तो हिस्सा लेने का सवाल ही नहीं उठता. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई है. सच्चर कमेटी की सिफारिश या उनकी रिपोर्ट हिंदूस्तान की सारी सरकारों के मुंह पर तमाचा है जो आज़ादी के बाद से देश को चला रही हैं. इसीलिए अगर एक बार देश ये फ़ैसला कर ले कि उसे दक्षिणपंथी नीतियों पर जाना है या नहीं या सांप्रदायिक रास्ते पर जाना है या नहीं, तभी विकास का रास्ता खुल पाएगा.

मुसलमान आज कांग्रेस के साथ हैं. भाजपा के कुछ नेता हैं जो मुसलमानों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर यह संभव दिखाई नहीं देता. तब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के साथ जाना मुसलमानों के लिए हितकर है. यह अवश्य हितकर साबित हो सकता है, अगर उन्हें लगता है कि 60 साल में उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है, अगर उन्हें लगता है कि 60 साल में उन्हें न्याय मिला है, अगर उन्हें लगता है कि 60 साल में उनके बच्चों को शिक्षा मिली है और वो सरकारी नौकरियों में गए हैं और वे देश के फ़ैसलों में शिरकत कर रहे हैं तो उन्हें कांग्रेस को अवश्य वोट देना चाहिए, अगर उनके नाम पर जीते कांग्रेस के नुमाइंदों ने कोई हक़ की लड़ाई लड़ी हो तो.

तब फिर आख़िर मुसलमान करें तो क्या करें. मैंने कई मुसलमानों से ये सवाल पुछा तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने ऊपर हुए अत्याचार की बात भी डर-डर कर कहते हैं, क्योंकि ऐसा न हो कि अत्याचार करने वाला अगली बार हमीं को टारगेट कर ले. सरकार हमारी हिफाजत नहीं कर सकती, सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे सकती और जो छोटे राजनीतिक दल हैं, वो सिर्फ जुबानी अंताकक्षरी कर सकते हैं. लेकिन हमें (मुसलमानों) कुछ दे नहीं सकते हैं, क्योंकि साठ साल में हमें कुछ नहीं दिया, हमें सिर्फ़ बेवकुफ बनाया है.

अगर ये सच है तो फिर जहां एक तरफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को अपनी बातें स्पष्ट तौर पर रखनी चाहिए. वहीं दूसरी तरफ़ मुसलमानों को अपने इनडिपेनडेंट ताक़त का एहसास कर इसके लिए इकट्ठा होना चाहिए. और इकट्ठा होकर उन्हें कहना चाहिए कि हम बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन लिए या दिए बिना स्वतंत्र रूप से अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और वो उम्मीदवार उस क्षेत्र के गैर मुसलमानों के समर्थन से लोकसभा चुनाव जीत जाएगा. चुनाव में कुछ भी गणित हो, लेकिन चुनाव में लोगों के वोट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं. 2014 तक चुनावों में सुधार होने नहीं जा रहा है, इसलिए यह आवश्यक है कि लोकसभा के चुनाव में मुसलमान अपनी संगठित ताक़त दिखाएं. देश की उन ताक़तों को यह भरोसा दिलाएं जो उनके हक़ों के लिए लड़ेगा उसके लिए वे हमेशा लड़ते रहेंगे.■

editor@chauthiduniya.com

आख़िर भारत में दंगे क्यों?

मेघनाद देसाई

जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी, लेकिन एक अलग राष्ट्र-राज्य के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र भारत में एक स्वायत्त उप महासंघ के रूप में. जुलाई 1946 में लगभग सभी पार्टियां इसके लिए राजी भी हो गई थीं, लेकिन दिसंबर 1946 में जब यह बात थोड़ा आगे बड़ी तो जिन्ना, सरदार पटेल और जवाहर लाल नेहरू उस समय लंदन में थे.

पिछले सप्ताह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक कमेटी रूम में पंजाब के विभाजन पर आधारित एक नई पुस्तक प्रस्तुत की गई. यह बात गौरतलब है कि हम अभी तक इस बात से अनजान हैं कि विभाजन के दौरान दोनों ही मुल्कों के लाखों लोगों की मौत हो गई, लेकिन जब भी कोई भारतीय या पाकिस्तानी एक दूसरे देश की यात्रा करता है, तो दोनों ही देशों में मिले आदर-सत्कार की कहानियां आश्चर्य चकित करती हैं.

यह भी सर्वविदित तथ्य है कि विभाजन और उससे जुड़ी यादें ही भारत में हिंदू-मुस्लिम दंगों का आधार बनीं, लेकिन अभी तक देश के सामने यह वास्तविक तस्वीर नहीं खींची कि आख़िर दोनों मुल्कों का विभाजन क्यों हुआ. कांग्रेस ने विभाजन के मसौदे पर दस्तखत किए थे, उनके लिए सबसे आसान यह होता है कि वे आसानी से इस पूरे प्रकरण के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को दोषी ठहरा देते हैं. उधर, पाकिस्तान में विभाजन का यह ठीकरा लॉर्ड माउंटबेटन के सिर फोड़ दिया जाता है. हमें बताया गया कि जिन्ना ने द्वी-राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया और इसे कांग्रेस ने कभी सहमति नहीं दी. कांग्रेस ने भारत को एक और समधर्मी बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी.

शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील करने के लिए यह एक बेहतर लाइन हो सकती है. हालांकि इसका असर नहीं हुआ, लेकिन इतिहास के एक टुकड़े के तौर पर यह अतर्कसंगत है. जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी, लेकिन एक अलग राष्ट्र-राज्य के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र भारत में एक स्वायत्त उप महासंघ के रूप में. जुलाई 1946 में लगभग सभी पार्टियां इसके लिए राजी भी हो गई थीं, लेकिन दिसंबर 1946 में जब यह बात थोड़ा आगे बढ़ी तो जिन्ना, सरदार पटेल और जवाहर लाल नेहरू उस समय लंदन में थे.

उसी दौर में लियाकत अली खान ने एक बेहद कट्टर बजट पेश किया, जिसमें युद्ध के समय मुनाफा कमाने के लिए चुंगी के व्यवसाय पर कर लगाया गया (जिन पर कर लगाया गया उनमें से ज्यादातर हिंदू थे). इस कराधान के बाद मार्च 1947 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की संधि टूट गई और ऐसे में कैबिनेट लंबे समय तक न चल सकी और माउंटबेटन ने दोनों ही पक्षों को अलग हो जाने की बात कही. इसी वर्ष अप्रैल महीने तक माउंटबेटन ने पटेल और नेहरू को बंटवारे के लिए तैयार कर लिया.

जून 1947 में माउंटबेटन ने यह घोषणा की कि कांग्रेस विभाजन के लिए राजी हो गई है. इस बीच विभाजन के ऊपर सहमति और बातचीत के लिए तकरीबन एक महीने लग गए. पंजाब और बंगाल का विभाजन उन दोनों प्रांतों के संबंधित विधानसभाओं में मत के आधार पर हुआ और कांग्रेस के सदस्यों ने इन दोनों ही राज्यों के विभाजन के पक्ष में मत दिया. दोनों ही देशों की सीमाएं 15 अगस्त, 1947 तक तय नहीं थी और जिसके परिणाम स्वरूप भीषण नरसंहार हुआ.

विभाजन सबके लिए एक असफलता ही थी. कांग्रेस के लिए भी, मुस्लिम लीग के लिए भी और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भी. हालांकि ऐसा भी नहीं था कि सबने आखें मूंद कर यह फैसला लिया था, यह हो सकता है कि इसके पीछे कारण अलग रहे हों. पता नहीं जो भी कारण रहे हों, जैसा कि नेहरू कहते हैं कि वे बूढ़े हो चले था या फिर जिन्ना की तरह जो बीमार थे. जो भी हो, लेकिन यह विभाजन किसी सिद्धांत पर नहीं, बल्कि जल्दबाजी और अवसरवादिता के आधार पर बनाया गया था. एक बात तो तय है कि हाउस ऑफ लाड्र्स की मीटिंग में एक बात तो तय हो गई थी कि विभाजन के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा होने वाली है. 17 वर्षों तक नेहरू के कार्यकाल मे कई बार हिंसा भड़की और उसके एक वर्ष जो हिंसा भड़की तो वह बदस्तूर आज तक जारी है.

उन सभी प्रमुख घटनाओं पर ध्यान दीजिए. वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे पुलिस की मदद से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा ही अंजाम दिए गए, जिसमें हजारों सिख मारे गए. उस दौरान यह बयान दिया गया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है. इसी तरह बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की तरफ से यह वादा किया गया था कि 6 दिसंबर, 1992 को पूजा के समय वहां कोई सेना नहीं रखी जाएगी और तब बीजेपी ने जो मूर्खता की उसका खामियाजा आज तक भुगत रही है.

1993 का मुस्लिम दंगा भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसका खुलासा श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट से होता है. यह दंगा भी एक बार सरकार और पुलिस की मिलीभगत से हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के किसी भी मुख्यमंत्री ने इसके लिए माफी नहीं मांगी. ऐसा ही गुजरात दंगों में हुआ, वहां अगर पुलिस तुरंत पुलिस एक्शन में आती तो दूसरे दिन जो दंगा हुआ उसे रोका जा सकता था. बाद में सेना ही इसे नियंत्रित कर सकी. इस तरह से देखा जाए तो इस देश में जो भी दंगे हुए. उन्हें सरकारों द्वारा शह दी गई और कभी भी सरकार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

उन सभी प्रमुख घटनाओं पर ध्यान दीजिए. वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे पुलिस की मदद से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा ही अंजाम दिए गए, जिसमें हजारों सिख मारे गए. उस दौरान यह बयान दिया गया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है. इसी तरह बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की तरफ से यह वादा किया गया था कि 6 दिसंबर, 1992 को पूजा के समय वहां कोई सेना नहीं रखी जाएगी और तब बीजेपी ने जो मूर्खता की उसका खामियाजा आज तक भुगत रही है.

सूचना का अधिकार चौथी दुनिया की पहल

जीने का सशक्त हथियार

चौथी दुनिया ब्यूरो

आख़िर क्या है सूचना का अधिकार क़ानून? कैसे बदल सकता है यह क़ानून आपकी ज़िंदगी? इस क़ानून के प्रयोग से आप भ्रष्ट अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कैसे सिखा सकता हैं सबक़? घबराएं नहीं, क्योंकि चौथी दुनिया अब आपको देगा एक ऐसा सशक्त हथियार, जिसका प्रयोग कर आप भ्रष्ट और निकम्मे कर्मचारियों का पसीना छुड़ा सकते हैं. इस अंक में हम आपको बताएंगे कि कैसे किया जाता है इस क़ानून का इस्तेमाल और कैसे बनाएं आरटीआई आवेदन. अगर आपको इस क़ानून के इस्तेमाल से संबंधित कोई परेशानी हो, या कोई सुझाव चाहिए, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. हम आपको देंगे सही सुझाव...

क्या है सूचना का अधिकार?

सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित एक क़ानून है, जो 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ. यह क़ानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों/रिकॉर्ड्स में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है. जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर, भारत के सभी भागों में यह अधिनियम लागू है. उल्लेखनीय है कि सरकार, सरकारी ख़र्च और अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भी हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से ही दिया जाता है. यहां तक कि एक रिक्शा चलाने वाला भी जब बाज़ार से कुछ ख़रीदता है, तो बिक्री कर, उत्पाद शुल्क इत्यादि के रूप में टैक्स देता है. इसलिए हम सभी के पास यह जानने का अधिकार है कि उस धन को किस प्रकार ख़र्च किया जा रहा है? यह हमारे मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है.

क्या और किससे सूचना मांग सकते हैं?

सभी इकाइयों/विभाग, जो संविधान, या अन्य क़ानून या किसी सरकारी अधिसूचना के अधीन बने हैं या सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त-पोषित किए जाते हों, वहां से संबंधित सूचना मांगी जा सकती है.

- सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं.
- सरकारी निर्णय की प्रति ले सकते हैं.
- सरकारी दस्तावेज़ का निरीक्षण कर सकते हैं.
- सरकारी कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं.
- सरकारी कार्य के पदार्थों के नमूने ले सकते हैं.

किससे मांगें सूचना और आवेदन शुल्क कितना है?

इस क़ानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में जन/लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के पद का प्रावधान है. आरटीआई आवेदन उनके पास जमा करना होता है. आवेदन के साथ केंद्र सरकार के विभागों के लिए 10 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ता है. हालांकि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग फीस रखी गई है. सूचना पाने के लिए 2 रुपये प्रति सूचना पृष्ठ केंद्र सरकार के विभागों के लिए देना होता है. यह विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग है. आवेदन शुल्क नक़द, डीडी या बैंकर चेक या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा कर सकते हैं. कुछ राज्यों में, आप कोर्ट फीस टिकटें ख़रीद कर अपनी अर्ज़ी पर चिपका सकते हैं. ऐसा करने पर आपकी फीस जमा मानी जाएगी. आप तब अपनी अर्ज़ी स्वयं या डाक से जमा करा सकते हैं.

आवेदन का प्रारूप क्या हो?

केंद्र सरकार के विभागों के लिए, कोई प्रारूप नहीं है. आप एक सादा काग़ज़ पर एक सामान्य अर्ज़ी की तरह ही आवेदन बना सकते हैं और इसे पीआईओ के पास स्वयं या डाक द्वारा जमा कर सकते हैं. अपने आवेदन की एक प्रति अपने पास निजी संदर्भ के लिए अवश्य रखें.

क्या सूचना प्राप्ति की कोई समय-सीमा है?

हां, यदि आवेदन पीआईओ को दे दी गई है, तो 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए, लेकिन यदि आवेदन सहायक पीआईओ को दी गई है, तो सूचना 35 दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए.

यदि सूचना न मिले?

यदि सूचना न मिले या प्राप्त सूचना से संतुष्ट न हों, तो अपीलीय अधिकारी के पास सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक अपील दायर करें. हर विभाग में प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है. सूचना प्राप्ति के 30 दिनों एवं आरटीआई अर्ज़ी दाख़िल करने के 60 दिनों के भीतर प्रथम दायर कर सकते हैं.

द्वितीय अपील क्या है?

द्वितीय अपील आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने का अंतिम विकल्प है. द्वितीय अपील सूचना आयोग के पास दायर की जा सकती है. केंद्र सरकार के विभागों संबंधित मामलों की जानकारी हासिल करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग है और राज्य सरकार के लिए राज्य सूचना आयोग है. प्रथम अपील के निष्पादन के 90 दिनों के भीतर या उस तारीख़ के 90 दिनों के भीतर, जब तक प्रथम अपील निष्पादित होनी थी, द्वितीय अपील दायर की जा सकती है. यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा, सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या हमें पत्र भी लिख सकते हैं.■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

कारगर है स्टेंट

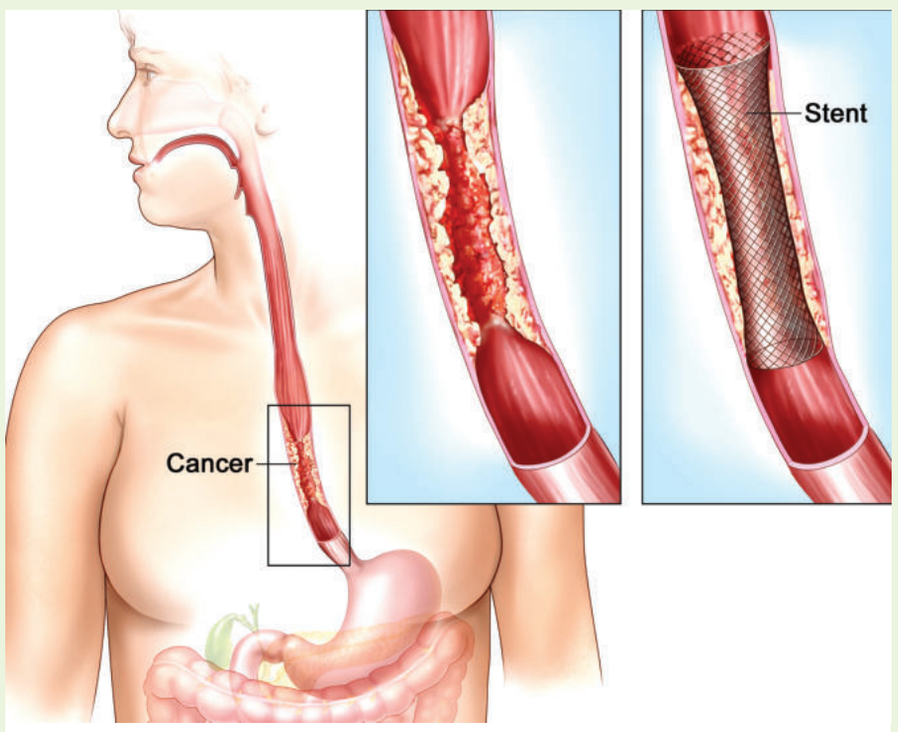

चौथी दुनिया ब्यूरो

जब ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में नहीं पहुंच पाता, तब दिल की बीमारी होती है. यदि समय रहते इसे नियंत्रित न किया जाए, तो हृदय की कोशिकाएं मरने लगती हैं. ज़्यादातर दिल का दौरा, यानी हार्ट अटैक कोरोनरी हार्ट डिजीज (सीएचडी) के कारण होते हैं. सीएचडी वह स्थिति है, जिसमें दिल की धमनियों में एक परत जम जाती है. यही धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को दिल तक पहुंचाने का काम करती हैं. जब इन धमनियों में परत जम जाती है, उस स्थिति को अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं. यह परत कई वर्षों तक धमनियों में जमा रहता है और अंततः जब यह परत फटती है, तो दिल में रक्त का थक्का जम जाता है. कई बार यह थक्का इतना बड़ा हो जाता है कि रक्त के बहाव को पूरी तरह रोक देता है. यह स्थिति आमतौर पर संयमित लाइफ स्टाइल न होने के कारण होती है.

मोटापा और तंबाकू नशीले पदार्थों के सेवन से भी यह बीमारी बढ़ती है. इस बीमारी के लक्षणों का जल्द पता नहीं चलता.

सीएचडी के अलावा कार्डियोवस्कुलर बीमारियों में सेरेब्रोवस्कुलर (दिमाग़ को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में रुकावट), पेरिफेरल आर्टियल बीमारियां (हाथ और पैरों तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में रुकावट) जैसी बीमारियां भी शामिल होती हैं. सीवीडी यानी कार्डियोवस्कुलर बीमारियां दुनिया भर में लोगों की मौत का प्रमुख कारण हैं. लगभग 12.3 मिलियन लोग कार्डियोवस्कुलर बीमारियों के कारण मरते हैं, जबकि इनमें 7.3 मिलियन कोरोनरी आरटरी बीमारी के कारण स्ट्रोक से मरते हैं. दुर्भाग्य से आनेवाले साल में यह आंकड़ा 20 मिलियन तक पहुंचने की आशंका है. इस बीमारी से बचाव का सबसे बढ़िया उपाय है संयमित जीवन शैली और समय पर जांच.

बीमारी की शुरुआत में मरीज को शल्य चिकित्सा या गैर शल्य चिकित्सा का रास्ता अपनाना पड़ता है. शल्य चिकित्सा में बाइपास सर्जरी और दिल का प्रत्यारोपण शामिल है. गैर शल्य चिकित्सा में एंजियोप्लास्टी का सहारा लिया जाता है, जिसमें स्टेंट्स का सहारा लिया जाता है. एंजियोप्लास्टी में दिल के डॉक्टर बंद पड़ी धमनी को एक छोटे से गुब्बारे यानी स्टेंट से खोलते हैं. कभी-कभार स्टेंट को एक-दो हफ्ते के लिए धमनी के भीतर ही छोड़ दिया जाता है, ताकि रक्त का बहाव सामान्य हो सके.

आजकल स्टेंट कपड़े के बनाए जाते हैं. पिछले कई वर्षों में स्टेंट में कई बदलाव आए हैं. अब तो दवाई पहुंचाने वाले स्टेंट भी आने लगे हैं. इन्हें दवा वाहक स्टेंट कहते हैं. कुछ निर्माता तो अलग-अलग बीमारियों के अनुसार स्टेंट भी बनाते हैं. जैसे कि मेडट्रॉनिक्स रेसोल्यूट इंटेग्रिटी मधुमेह के लिए स्टेंट बना सकते हैं.

पिछले कुछ वर्षों में मेटल स्टेंट के साथ-साथ दवा वाहक स्टेंट भी काफ़ी चलन में आए हैं. यूरेटर स्टेंट, जो कि किडनी में हुई पथरी के कारण यूरीन में दिक्कत आने से रोकता है. इनका इस्तेमाल किडनी से पथरी निकालने के लिए भी हो सकता है, जब मरीज को यूरीन में दिक्कत आ रही हो. हाल ही में हुए कुछ शोधों से पता चला कि स्टेंट का इस्तेमाल हरनिया के इलाज के लिए भी हो सकता है.

स्टेंट का इस्तेमाल दिल की धमनियों के साथ-साथ रक्त कोशिकाओं को खोलने में भी होता है. इनका इस्तेमाल सेरेब्रोवस्कुलर धमनियों और पेरिफेरल आर्टी के इलाज के लिए भी हो सकता है. हालांकि हाल ही में देखा गया कि स्वतः फुलने वाले स्टेंट, जो कि प्लास्टिक या धातु के बने होते हैं, यह एसफोगेल कैंसर के इलाज में भी कारगर है. साथ ही बिलियरी स्टेंट पित्त वाहिनी के रूप में सफलतापूर्वक प्रयुक्त किए गए हैं.

स्टेंट के विकास पर अभी काम जारी है. हाल ही में कोबाल्ट क्रोमियम धातु के बने स्टेंट भी अस्तित्व में आ गए हैं, जो स्वतः ही घुल जाते हैं.■

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य का कुछ ख़ास ख्याल रखें. विरोधियों पर आपका पराक्रम बनेगा. इस सप्ताह आपका ख़र्च बढ़ा रहेगा और आप आर्थिक रूप से चिंतित रहेंगे. सामाजिक रूप से किसी शुभ कार्य में आप संलग्न रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. आकस्मिक धन लाभ का योग बना रहेगा.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह आप जम कर मेहनत करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी. आर्थिक दृष्टि से आपका समय अच्छा रहेगा. कार्य स्थल पर आप अपने अधिकारी से सामंजस्य बना कर चलें. आपको अचानक किसी यात्रा पर जाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है. पूर्व से चली आ रही किसी शत्रुता का आपके ऊपर हावी होने के आसार हैं.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से आप मजबूत महसूस करेंगे. कहीं से फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है. नौकरीपेशा लोग अपने लिए आगे जाने वाले आलोचना पर नज़र रखें. पत्नी को उदास कर किसी कार्य पर न निकलें, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. पारिवारिक सदस्य से संपूर्ण सहायता मिलेगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव महसूस कर सकते हैं. आप अपनी धैर्य और उत्साह को बना कर चलें, सफलता आपकी क़दम चूमेगी. किसी जोखिम वाले बाज़ार से बच कर चलें. मित्रों और सगे संबंधियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा. व्यापारियों का नुक़सान कम होगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह नौकरीपेशा और व्यापारी कुछ हद तक पैसे को लेकर चिंतित रहेंगे. इस सप्ताह अपने व्यक्तित्व को निखारने में आपका ध्यान ज़्यादा लगा रहेगा. आपका ध्यान परिवार के प्रति भी केंद्रित रहेगा. समय परिवार में भी व्यतीत होगा. संपत्ति क्रय करने की योजना भी बन सकती है. स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
इस सप्ताह कभी भी कोई आलसी प्रवृति न रखें. आपका पैसे पर ज़्यादा ध्यान रहेगा. पारिवारिक जीवन के लिए आप कम समय निकाल पाएंगे. आपके स्थानांतरण की भी कोई योजना बन सकती है, लेकिन इसे लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. व्यवसायी अपने स्टाफ पर ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि धोखा हो सकता है. स्वास्थ्य हल्के उतार-चढ़ाव के साथ ठीक रहेगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह व्यवसायी अपने व्यापार का विस्तार करेंगे. यात्रा के वक़्त खान-पान का ध्यान रखें. वाद-विवाद से बचें. निवेश करते समय ध्यान रखें और ज़्यादा जोखिम न लें. भ्रमण से यथा संभव बचें. नौकरीपेशा लोग अपने कार्यक्षेत्र पर थोड़ा तनाव में रहेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है. अपने ख़र्चे पर नियंत्रण रखें.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों का समय अनुकूल रहेगा. अपने बॉस से बर्ताव अच्छा बना कर रखें. इस सप्ताह आप कोई नई वस्तु ख़रीदने की योजना बनाएंगे. आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा मुश्किल में फंस जाएंगे. आर्थिक दृष्टि से आप थोड़ा तंग अनुभव करेंगे. विद्यार्थी, प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस सप्ताह आप भाग्य से ज़्यादा कर्म पर ध्यान देंगे और कर्मवादी रहकर बहुत सारे अनसुलझे कार्यों को भी आसानी से करेंगे. किसी नये जगह की यात्रा की योजना बनाएंगे. लगातार काम के बोझ से मन उबेगा. आप एक कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं, इसलिए कठिन से कठिन काम आसानी से कर लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
आप इस सप्ताह सामाजिक कार्यों में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे. थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी. मानसिक संतुलन बना कर चलें. आपा न खोएं. व्यापारी, व्यापार बढ़ाने की सोचेंगे. अपनी अचल संपत्ति को बढ़ाने की तरफ़ ज़्यादा ध्यान लगाएंगे. परिवार के लोग और आपके सहयोगी आपकी मदद करेंगे

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह आपके अनुमान की शक्ति बढ़ी रहेगी, जिससे आप कुछ नए कार्य अच्छे से कर पाएंगे. दुश्मन इस सप्ताह आपसे दबे रहेंगे. इस सप्ताह आप दौड़-धुप भी ज़्यादा करेंगे. कुछ विद्वान लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी. आप अपनी जानकारी और पैसे का घमंड बिल्कुल न करें. स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
इस सप्ताह आप जिम्मेदार व्यक्तित्व की भूमिका में रहेंगे. आपके संपर्क उच्चाधिकारियों और राजनेताओ से बढ़ेंगे. कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. स्वास्थ्य हलके उतार- चढ़ाव के साथ ठीक रहेगा. भाइयों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी.

ज़रा हट के

मोटापा घटाओ, गोल्ड पाओ

लोगों को मोटापा से परहेज करनी चाहिए, लेकिन इस बात पर ध्यान कौन देता है. ऑफिस हो या सामान्य जीवन, लोग मोटापा घटाने को लेकर कतई गंभीर नहीं हैं. और रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत कम ही लोग जागरूक होते हैं, लेकिन दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने जिस तरह से मोटापा को लेकर गोल्ड स्कीम निकाला है, लगता है उससे लोगों में मोटापा घटाने को लेकर कुछ जागरुकता आएगी. वास्तव में दुबई में मोटे लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है, जिससे वहां के लोग ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था और सामान्य जीवन के लिए सही साबित नहीं हो रहा है. दुबई में म्यूनिसिपैलिटी ने तोंदू और ख़ूब मोटे हो रहे अपने निवासियों के लिए एक स्कीम निकाली है. उन्होंने मोटापे से ग्रस्त अपने निवासियों को स्लिम होने का प्रलोभन दिया है कि जो जितना स्लिम होगा, बदले में उतना ही सोना ले जा सकता है. लोगों को वजन घटाने का यह तरीक़ा काफी पसंद आ रहा है. इस वजन कम करने वाली योजना में हिस्सा लेने वालों को कम से कम दो किलो वजन कम करना होगा, तभी सोना मिलेगा. इसके अलावा, लकी ड्रॉ में निकाले गए पहले तीन विजेताओं को 20 हज़ार दिरहम (क़रीब 5445 डॉलर) की क़ीमत का सोने का सिक्का इनाम में दिया जाएगा. ■

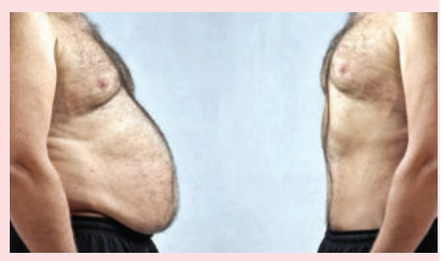

ट्यूनिशिया

ट्यूनिश हबीब बोर्किया के बाद 23 साल तक ज़ैनुल आबिदीन की तानाशाही में रहने के कारण अरब क्रांति के नतीजे में आज़ाद हुआ. इस आज़ादी ने जनता को एक सुनहरा अवसर दिया कि वह अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजें. अंतत: 2011 में आम चुनाव हुए. इन चुनावों में जनता ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और 217 सीटों में से 90 सीटें अलनहज़ा पार्टी को देकर संसद में भेजा. चूंकि आम चुनावों में अलनेहज़ा को सबसे अधिक सीटें मिली थीं, इसलिए इसी को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया गया, लेकिन 90 सीटों के बल पर, जो कुल मतदान का 41.47 प्रतिशत था, सरकार नहीं बनाई जा सकती थी, जब तक कि किसी अन्य पार्टी से समर्थन लेकर बहुमत सिद्ध न कर दिया जाए.

क्या गठबंधन सरकार को कोई ख़तरा है?

ट्यूनिशिया को मिस्र न समझा जाए

मिस्र में मुर्सी के विरुद्ध जो शक्तियां काम कर रही थीं, कुछ हद तक वही विदेशी शक्तियां ट्यूनिशिया में भी काम कर रही हैं. हालांकि ट्यूनिशिया में उन शक्तियों को अपनी सफलता दूर तक नज़र नहीं आ रही है. दूसरी तरफ यह भी ध्यान देने लायक है कि ट्यूनिशिया की सेना राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप से बच रही है, जबकि मिस्र में ऐसा नहीं था, इसलिए ट्यूनिशिया को मिस्र न समझा जाए

वसीम अहमद

ट्यूनिशिया में सरकार के ख़िलाफ़ धरना-प्रदर्शन का दौर जारी है, जिसे मिस्र की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. ख़ासकर मिस्र में मुर्सी के अपदस्थ होने का असर ट्यूनिशिया की राजनीति पर कितना पड़ सकता है, इस पर सियासी पंडितों की राय अलग-अलग है. ट्यूनिशिया की सत्ताधारी पार्टी अलनेहजा मुर्सी के तख़्ता पलट को देश के लिए अपशगुन बता रही है, तो वहीं विपक्षी दल इसे एक सकारात्मक प्रतीक मान रहे हैं. यहां तक कि कुछ राजनीतिक दल तो मिस्र की तर्ज़ पर ट्यूनिशिया में भी संसद भंग किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या ट्यूनिशिया में जारी धरना-प्रदर्शन मुनसिफ अल मर्ज़ूक़ी की सरकार को मिस्र में मोहम्मद मुर्सी की सरकार की तरह उखाड़ फेकेंगे या तुर्की में तकसीम स्कवायर की तरह असफल होकर आने वाले कुछ दिनों में अपना महत्व खो देंगे, जिस प्रकार कर्नल गद्दाफ़ी की हत्या के बाद लीबिया में नूरी अबु सहमीन की कठपुतली सरकार क़ायम है. इस पूरे घटनाचक्र को समझने के लिए हमें ट्यूनिशिया की राजनीतिक हलचल पर एक नज़र डालनी होगी.

ट्यूनिश हबीब बोर्किया के बाद 23 साल तक ज़ैनुल आबिदीन की तानाशाही में रहने के कारण अरब क्रांति के नतीजे में आज़ाद हुआ. इस आज़ादी ने जनता को एक सुनहरा अवसर दिया कि वह अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजें. अंतत: 2011 में आम चुनाव हुए. इन चुनावों में जनता ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और 217 सीटों में से 90 सीटें अलनेहज़ा पार्टी को देकर संसद में भेजा. चूंकि आम चुनावों में अलनेहज़ा को सबसे अधिक सीटें मिली थीं, इसलिए इसी को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया गया, लेकिन 90 सीटों के बल पर, जो कुल मतदान का 41.47 प्रतिशत था, सरकार नहीं बनाई जा सकती थी, जब तक कि किसी अन्य पार्टी से समर्थन लेकर बहुमत सिद्ध न कर दिया जाए. लिहाज़ा, ट्यूनिशियन कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई गई. कांग्रेस ने चुनाव में 13.82 प्रतिशत वोट प्राप्त किए थे. इसके बाद कांग्रेस के मुनसिफ़ अलमर्ज़ूक़ राष्ट्रपति और अलनेहज़ा के अली लारीज़ प्रधानमंत्री बने. सरकार बनने के बाद भविष्यवाणी की जा रही है कि अब ट्यूनिशिया में शांति बहाल होगी और जैनुलआबिदीन की तानशाही व्यवस्था के अंत के बाद जनता चैन से सांस ले सकेगी, लेकिन दो साल बीतने के बाद भी ट्यूनिशिया की सत्ता शासकों के लिए कांटों भरा ताज साबित हो रही है. देश के विभिन्न हिस्सों में अशांति फैली है, जिससे विकास कार्य ठप पड़े हैं. शांति व सुरक्षा का मामला भी कमज़ोर बना हुआ है. हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि एक राजनीतिक पार्टी तमारूद ने संसद को भंग करने की मांग कर दी है. कुछ राजनीतिक दल, जिनमें टीपीपी शामिल है, दावा कर रही है कि मुर्सी की ही तरह यहां के शासकों को भी सत्ता त्यागनी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री लारीज़ ने इन सभी दलों को यह कहकर ख़ामोश करने की कोशिश की है कि न तो संसद भंग होगी और न ही अलनेहज़ा सरकार से बेदख़ल होगी. जहां तक सरकार गिराने के लिए राजनीतिक पार्टियों के दुष्प्रचार की बात है, तो ये पार्टियां तरह-तरह के वादे करती हैं. तरह-तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है. अगर हालात को नज़दीक से देखें, तो राजनीतिक दल इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विकास दर की यह स्थिति 2011 से नहीं, बल्कि पहले से ही है और जब से अलनेहज़ा ट्यूनिशियन कांग्रेस से गठबंधन करके सत्ता में आई है, तब से कई क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बढ़ी है. जिन क्षेत्रों में रणनीति से आय में बढ़ोत्तरी की जा सकती थी, उनमें सरकार ने उचित प्रगति की है. जैसा कि पर्यटन क्षेत्र में पिछले विकास दर के मुक़ाबले अब स्थिति बेहतर है और इस समय इसके विकास दर में 1.8 प्रतिशत और खनन क्षेत्र में 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है. विपक्ष सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता में भ्रम पैदा कर रहा है.

प्रधानमंत्री ने जिस विश्वास के साथ अपने विचार रखे, उससे स्पष्ट होता है कि ट्यूनिशिया की राजनीति पर मिस्र में मुर्सी के तख़्तापलट होने से किसी नकारात्मक प्रभाव की शंका नहीं है और न ही धरना-प्रदर्शनों के दम पर अलनेहज़ा को इख़्वान की तरह सत्ता से बेदख़ल करना आसान होगा. दरअसल, ट्यूनिशिया की परिस्थितियां मिस्र से बिल्कुल अलग हैं. इसकी वजह यह है कि ट्यूनिशिया की सेना राजनीतिक हस्तक्षेप से बिल्कुल बाहर है और मुर्सी

की निर्वाचित सरकार का तख़्तापलट किए जाने के कारण अफ़्रीक़ी यूनियन ने मिस्र का बहिष्कार कर दिया था. इन स्थितियों का सामना ट्यूनिशिया को भी करना पड़ सकता है, जबकि ट्यूनिशिया की जनता अफ़्रीक़ी यूनियन से अलग-थलग होकर रहना पसंद नहीं करती है, क्योंकि ट्यूनिशियाई जनता इस बात से भलि-भांति परिचित है कि अफ़्रीक़ी यूनियन से अलग होने का मतलब है कि देश को आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे ले जाना और यह भार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था फिलहाल नहीं सह सकती है. जहां तक ट्यूनिशिया में हो रही अफरातफरी की बात है, तो इसके बारे में राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह वैसे ही हंगामे हैं, जैसे तुर्की के तकसीम चौक पर हुए थे और इन हंगामों की अगुवाई करने वाले वे लोग थे, जो नग्नता और पश्चिमी संस्कृति के अगुवा थे और उनके पास कोई गंभीर मुद्दा नहीं था. लिहाज़ा, कुछ दिनों में ही इन धरना-प्रदर्शनों का अंत हो गया और उर्दगान सत्ता में बने रहे. इसी प्रकार जो अशांति ट्यूनिशिया में फैली है, उसमें भी विरोधियों के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है. वह सरकार को बदनाम करने के लिए पिछले दो सालो से नये-नये मुद्दों को दुष्प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. कभी अर्थव्यवस्था को, तो कभी शांति व सुरक्षा की समस्या को लेकर, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें डर है, तो केवल अलनेहज़ा के सुधार कार्यों से, जिनको संविधान में कुछ संशोधन करके लागू करने के बारे में विचार-मंथन हो रहा है.

दरअसल, अलनेहज़ा पार्टी सत्ता में आने के बाद कुछ सुधार कार्य करना चाहती थी. देश में नग्नता पर प्रतिबंध और अपराध की सज़ा में कुछ सख़्त क़दम उठाना चाहती थी, जो वहां के पश्चिमी संस्कृति के समर्थकों को स्वीकार नहीं था. इसीलिए उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ राजनीतिक दलों ने भी उनका साथ दिया. हद तो तब हो गई, जब संसद के हालिया सत्र में सुधार कार्यों को लेकर अधिवेशन प्रस्तुत किया जा रहा था, तो कुछ सदस्यों ने अलनेहज़ा के सदस्यों के साथ संसद के अंदर ही अभद्रता शुरू कर दी.

इन दलों के आक्रामक तेवरों से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे सुधार कार्यों को रोकने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और यही वे लोग हैं, जो संसद से बाहर आने के बाद जनता को अलनेहज़ा के विरुद्ध भड़काते हैं, बल्कि ट्यूनिशिया में विपक्ष की महत्वपूर्ण पार्टी निदाय टयूनिशिया ने तो अलनेहज़ा की सरकार के तख़्तापलट के बाद वहां तत्काल रूप से कार्यवाहक सरकार के गठन और संविधान निर्माण के लिए नया रेखाचित्र भी जारी करने की मांग तक कर दी है. मंत्रिमंडल से कई मंत्रियों के इस्तीफे की वजह से सत्ताधारी अलनेहज़ा के लिए अधिक कठिनाइयां पैदा हो रही हैं. दरअसल, जब से मर्जूक़ी राष्ट्रपति बने हैं, देश के विभिन्न शहरों में सरकार के विरुद्ध धरना-प्रदर्शनों का दौर जारी है. पूर्व प्रधानमंत्री अलबाजी क़ायद अलबसी की पार्टी का कहना है कि देश में संसदीय चुनाव पुन: कराने के लिए तत्काल और स्पष्ट रोडमैप की अधिक आवश्यकता है. निदा-ए-ट्यूनिशिया का कहना है कि नये संविधान निर्माण के लिए संविधान आयोग का गठन किया जाए. निदा-ए-ट्यूनिशिया, जो वर्तमान सरकार की धुर विरोधी पार्टी है, का आरोप है कि अलनेहज़ा देश की न्यायपालिका, प्रशासन और अन्य राज्यों के संस्थानों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप की दोषी है. इसी प्रकार नेशनल डेमोक्रेट्स पार्टी ने एक बयान में सरकार की कुछ नीतियों पर कड़ी चेतावनी दी है. डेमोक्रेट्स पार्टी के एक बयान में कहा गया है कि हमें मिस्र के इतिहास से सीख लेनी चाहिए और देश को वर्तमान संकट से निकालने के लिए प्रयास तेज़ करने चाहिए.

अब अगर हम सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों के बयान पर नज़र डालते हैं, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ट्यूनिशिया और मिस्र अफ़्रीक़ा के दो ऐसे देश हैं, जिनका एक-दूसरे की राजनीति पर असर पड़े या न पड़े, लेकिन यहां की घटनाएं इन दोनों देशों की जनता के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं. उल्लेखनीय है कि ट्यूनिशियन जनता ने आर्थिक बदहाली, बेरोज़गारी और मंहगाई को दूर करने के लिए जैनुल आबिदीन का तख़्ता पलटा था और बलिदानों के बाद देश में लोकतंत्र बहाल हुआ था, तो फिर अब इसी लोकतंत्र और निर्वाचित सरकार के विरुद्ध वे सड़कों पर क्यों उतर आये हैं, क्या उन्होंने मिस्र में लोकतंत्र की हत्या से सीख नहीं ली है?

दरअसल, कुछ विदेशी शक्तियां यहां काम कर रही हैं, जो मिस्र में मुर्सी के विरुद्ध काम कर रही थीं. हालांकि ट्यूनिशिया में उन शक्तियों को अपनी सफलता दूर तक नज़र नहीं आ रही है. ट्यूनिशिया की सेना राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप से बच रही है. अर्थात वह शक्तियां उन छोटी-छोटी राजनीतिक पार्टियों को मोहरा बनाकर अपना काम करना चाहती हैं और साथ ही कोशिश कर रही हैं कि अलनेहज़ा को अलइख़्वान की साख मशहूर कर दी जाए, जिससे अलइख़्वान के ख़िलाफ़ मिस्र में हंगामा हो. इसी प्रकार की परिस्थितियां ट्यूनिशिया में भी पैदा कर दी जाएं. हालांकि अलनेहज़ा अलइख़्वान की शाखा नहीं है और इससे बहुत पहले अस्तित्व में आई है. अर्थात् दोनों ही धार्मिक उदारवादी पार्टियां हैं और दोनों के विचार मिलते-जुलते हैं. दोनों ही राजनीति और धर्म को उदारवाद के साथ लेकर चलने में विश्वास करती हैं. हालांकि जिस प्रकार मोहम्मद मुर्सी ने देश में उदारवाद के साथ इस्लाम लागू करने का इशारा किया था और कुछ मामलों में उन्होंने इस्लामी क़ानून को संतुलन और उदारता के साथ लागू भी किया था, इसी प्रकार ट्यूनिशिया में मुनसिफ़ अलमर्ज़ूकी ने कुछ हद तक इस्लामी क़ानून को लागू करने की बात कही थी. बस यहीं से विपक्ष व अन्य राजनीतिक दलों को अवसर मिला और उन्होंने वर्तमान सरकार के विरुद्ध झंडा बुलंद कर दिया, लेकिन इन दलों के इस व्यवहार से यह बात साफ़ है कि ट्यूनिशिया के हालात की मिस्र से नहीं, बल्कि तुर्की से तुलना की जानी चाहिए, क्योंकि तुर्की में भी सुधार कार्यों के कारण ही तकसीम चौक पर लोग जमा हुए थे और ट्यूनिशिया में भी क़ानून में कुछ सुधारों को लेकर लोग सरकार, ख़ासकर अलनेहज़ा से आपत्ति जता रहे थे. अब सरकार के लिए आर्थिक क्षेत्र में प्रभावी भूमिका न निभाना कमज़ोर कड़ी बनता जा रहा है. दो सालों में अब तक आर्थिक रूप से कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, जिससे यह समझा जाए कि देश विकास कर रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सरकार के सामने बड़ी समस्या सुरक्षा और शांति बनाए रखने की होती है. जब राजनीतिक दल हंगामे नहीं रोक रहे हैं, तो दूसरी ओर ध्यान कैसे दिया जाए. इस ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री अली लारीज़ कहते हैं कि देश में आर्थिक पतन का कारण राजनीतिक पार्टियों के हंगामे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई

आस्था

दरअसल

> सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और सद्भाव कायम करने के लिए भारत में समय–समय पर संतों ने हमेशा ही योगदान दिया. उन सतों में रविदास का नाम अग्रणी है. वह संत कबीर के गुरुभाई थे. उनके गुरु स्वामी रामानंद थे. महान संत रविदास चाहते थे कि लोग एक कुटुंब की तरह रहें.

साई तेरे हजारों नाम

चौथी दुनिया ब्यूरो

श्री साई बाबा सबको प्यारे थे. उनके आदर्शों का अनुकरण कर लोग दूसरा जन्म पा लेते थे. उनके लिए सभी बराबर थे. वह कलयुग के महान अवतार थे. जाति और धर्म का उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि कोई नहीं बता सकता है कि उन्होंने किस जाति, धर्म, परिवार और कुल में जन्म लिया. कोई नहीं जानता कि उनके पूर्वज कौन थे. उनके माता–पिता कौन थे.

बहुत लोगों ने साई बाबा से उनके जीवन के विषय में जानने की इच्छा प्रगट की थी, पर उन्हें बाबा जी से कोई जानकारी नहीं मिल सकी. बाबा ने किसी को भी अपने विषय में नहीं बताया था. एक बार जब बाबा म्हालसापति के साथ एकांत में बैठे थे, तो उन्होंने अपनी जन्म तिथि बताई. उन्होंने काग़ज़ के एक पुर्जे पर बाबा की जन्मतिथि लिख कर रख दी. काग़ज़ का पुर्जा हेमातपंड के हाथ लग गया. फिर क्या था, इसी पुर्जे के आधार पर हेमातपंड बाबा की जीवनी लिखने लगे. पुर्जे के आधार पर बाबा का जन्म 27 सितंबर, 1838 ईस्वी को हुआ था, लेकिन इसके आधार पर बाबा के जन्म का अनुमान लगाना सही नहीं कहा जा सकता. सच्चाई तो यह है कि बाबा के जीवन की वास्तविकता कोई नहीं बता सकता.

शिरडी गांव की वृद्धा, जो नाना चोपदार की मां थी, उसके अनुसार एक युवा जो एक नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा, अल्पायु में बालक को कठोर तपस्या में लीन देख कर लोग आश्चर्यचकित थे. तपस्या में लीन बालक को सर्दी–गर्मी व वर्षा की जरा भी चिंता न थी. आत्मसंयमी बालक के दर्शन के लिए अपार जनसमूह उमड़ने लगा.

इस बालक की दिनचर्या भी अजीब थी. जहां लोग हर काम में दूसरों की संगत ढूंढते हैं, वहीं यह अद्भुत बालक दिन में किसी का साथ नहीं करता था. लोगों को रात्रि पहर में जहां भय सताता है, वहीं उस बालक को रात्रि के सुनसान वातावरण में कोई भय नहीं सताता था. यह बालक कहां से आया था, यह प्रश्न सबको व्याकुल कर देता था. दिखने में वह बालक बहुत सुंदर था, जो उसे एक बार देख लेता, उसे बार–बार देखने की इच्छा होती. लोग इस बात से हैरान थे कि यह सुंदर, रूपवान बालक दिन–रात खुले आकाश के नीचे कैसे रहता है. वह प्रेम और वैराग्य की साक्षात मूर्ति दिखाई पड़ते थे. उन्हें अपने मान–अपमान की कभी चिंता नहीं सताती थी. वह साधारण मनुष्यों के साथ मिलकर रहते थे, नृत्य देखते, गजल व कव्वाली सुनते हुए अपना सिर हिलाकर उनकी प्रशंसा भी करते. इतना सब कुछ होते हुए भी उनकी समाधि भंग न होती. जब दुनिया जागती थी, तब वह सोते थे, जब दुनिया सोती थी, तब वह जागते थे. बाबा ने स्वयं को कभी भगवान नहीं माना. वह प्रत्येक चमत्कार को भगवान का वरदान मानते. सुख–दुःख उन पर कोई प्रभाव न डालते थे. संतो का कार्य करने का ढंग अलग ही होता है. कहने को साई बाबा एक जगह निवास करते थे, पर वह विश्वव्यापी थे.■

feedback@chauthiduniya.com

श्री साई वंदना

अब सौंप दिया सारा जीवन, साईनाथ तुम्हारे चरणों में!
अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में!! अब सौंप दिया....

मैं जग में रहूं, तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे!
मेरे अवगुण-दोष समर्पित है, साई नाथ तुम्हारे चरणों में!! अब सौंप दिया....

मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हे पा जाऊं मैं!
अर्पित कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे चरणों में!! अब सौंप दिया....

जब-जब मुझे मानव का जन्म मिले, तब-तब तेरी चरणों का पुजारी बनूं!
इस सेवक की एक-एक रग का, हो तार तुम्हारे हाथों में !! अब सौंप दिया...

हम में-तुम में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो!
मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में!! अब सौंप दिया..

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

आस्था

सोमनाथ मंदिर

मन्नतें हो जाती हैं पूरी

इस मंदिर की सुंदरता अपने आप में ख़ास है. यहां श्रद्धालु बहुत दूर–दूर से आते हैं. चूंकि भगवान सोमनाथ से लोगों की भावनाएं गहराई से जुड़ी है, इसलिए भगवान भी अपने दर से किसी को ख़ाली नहीं लौटने देते हैं...

कैफी रज़ा

यह वही मंदिर है, जो सिर्फ़ अपनी ख़ूबसूरती ही नहीं, बल्कि अपनी संपदा के लिए भी कभी मशहूर था. इतना मशहूर कि विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया और मंदिर में जड़े सोने–चांदी, हीरे–जवाहरात सब लूट कर ले गया. हालांकि आज भी यह मंदिर अपने यश और महत्ता के लिए श्रद्धालुओं में प्रसिद्ध है. विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर की ख़ूबसूरती की मिसाल भक्त आज भी देते हैं. इस मंदिर का हिंदू धर्म में अपना एक अलग स्थान है. धर्मग्रंथों के अनुसार, शाप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने यहां भगवान शिव की आराधना की थी, इसलिए चंद्रमा यानी सोम के नाम पर ही इस मंदिर का नाम पड़ा सोमनाथ. गुजरात के सौराष्ट्र से होकर प्रभास क्षेत्र में प्रवेश करते ही आप को दूर से ही हज़ारों वर्षों से भगवान सोमनाथ की आराधना में यशगान करते हुए वह ध्वज लहराता हुआ दिखाई देगा. आसमान को स्पर्श करता मंदिर का शिखर भगवान की ख्याति का एहसास कराता है. मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर एक अलग ही एहसास होता है. जिधर भी निगाहें जाती हैं, भगवान शिव का चमत्कार ही दिखाई पड़ता है. हर किसी के मन में यही इच्छा होती है कि ज़िंदगी में एक बार सोमनाथ मंदिर के दर्शन करूं. यही कारण है कि भगवान सोमनाथ से लोगों की भावनाएं गहरी रूप से जुड़ी हैं. भगवान भी अपने दर से किसी को ख़ाली लौटने नहीं देते हैं.

सोमनाथ मंदिर

कैसे बना यहां मंदिर

शिवभक्त चंद्रमा ने निरोग होने के लिए कठोर तपस्या की. इसलिए खुश होकर महादेव ने उसे श्राप से मुक्त कर दिया. इससे चंद्रदेव काफ़ी उत्साहित हुए और यहां पर शिव मंदिर बनवाया. इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ और उसका नाम चंद्रमा के स्वामी यानी सोमनाथ पड़ गया.

दर्शनीय स्थल

ज्योतिर्लिंग

कहा जाता है कि भारत में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में यह पहला है. अगर लोग सच्चे दिल से इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, तो उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं. यहां श्रद्धालु इस अटूट विश्वास के साथ आते हैं कि उनकी सारी मुसीबतों का अंत हो जाएगा. कोई अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, तो कोई सुहाग की लंबी आयु की मन्नत लिए यहां आता है.

भालका तीर्थ

भालका तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि यहां पर भगवान कृष्ण को एक शिकारी ने अपने तीर से घायल किया था. जब श्रीकृष्ण ध्यान मुद्रा में थे, तभी शिकारी ने ग़लत से उनके पैर को हिरण का पैर समझ कर तीर चला दिया था. शिकारी के बाण से जहां ख़ून बहा, उस स्थान पर भालका तीर्थ के नाम से मंदिर की स्थापना की गई.

बाणगंगा

इस स्थान पर समुद्र के अंदर दो शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, जिसे देखने से लगता है कि समुद्र की लहरें शिवलिंग का अभिषेक कर रही हैं. हालांकि देखने से लगता है कि शिवलिंग प्राकृतिक नहीं है, लेकिन दृश्य सचमुच बड़ा ही मनोहारी लगता है.

गीता मंदिर

यह कृष्ण मंदिर है, जिसे 3 पवित्र नदियों के संगम पर बनाया गया है. इस मंदिर को बिड़ला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. यह मंदिर पूरी तरह से संगमरमर से बना है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है. मंदिर परिसर में ही बलराम गुफा, लक्ष्मीनारायण मंदिर, देहोत्सर्ग स्थल, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, महाप्रभुजी की बैठक आदि स्थित है.

सूरज मंदिर

इस मंदिर को सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. यह काफ़ी पुराना मंदिर है, जो सोमनाथ मंदिर के समय का है. इस मंदिर का निर्माण भगवान सूर्य की पूजा–अर्चना करने के लिए निर्मित किया गया था.

पांच पांडव गुफा

इसके नाम से इसके बारे में मंदिर न होने का भ्रम पैदा हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह मंदिर है, जो सोमनाथ में लाल घाटी के पास स्थित है. यह मंदिर पांच पांडव भाइयों को समर्पित है.

साउंड एंड लाइट शो

यहां पर आए भक्तों को सोमनाथ मंदिर के इतिहास को साउंड एंड लाइट शो के माध्यम से रूबरू कराया जाता है. यह मंदिर के प्रांगण में रात साढ़े सात बजे से आठ बजे तक चलता है, जिसमें मंदिर के इतिहास को बड़े सुंदर तरीक़े से बताया जाता है. लोग मनोरंजन के साथ–साथ ज्ञान भी प्राप्त करते हैं. लोक कथा के अनुसार, यहीं श्री कृष्ण ने देहत्याग किया था. इस कारण इन क्षेत्रों का महत्व बढ़ गया. यह तमाम जानकारी बड़ी ही आसानी से आप यहां आकर प्राप्त कर सकते हैं.

कब जाएं

चैत्र, भाद्र, कार्तिक माह में यहां के दर्शन करने का विशेष महत्व माना गया है. इन तीन महीनों में यहां श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगती है.

कैसे पहुंचें

अहमदाबाद से सोमनाथ की दूरी 400 किलोमीटर है. यहां से सड़क, रेल या निजी वाहन या वायु मार्ग से भी सोमनाथ जा सकते हैं. सोमनाथ पहुंचने के बाद आप टैक्सी या निजी वाहन से सोमनाथ मंदिर के अलावा अन्य तीर्थ स्थलों का भी भ्रमण कर सकते है. ■

feedback@chauthiduniya.com

दरअसल

महान संत रविदास

संत रैदास यानी संत रविदास का जन्म काशी (उत्तर प्रदेश) में हुआ था. वह सामान्य जीवन जीने में विश्वास करते थे. आज जब समाज जाति और धर्म के टुकड़ों में बंटा है, ऐसे में संत रविदास का महत्व और भी बढ़ जाता है. वह बचपन से समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहे. उनके जीवन की छोटी–छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके अनेक गुणों का पता चलता है.

सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और सद्भाव कायम करने के लिए भारत में समय–समय पर संतों ने हमेशा ही योगदान दिया. उन सतों में रविदास का नाम अग्रणी है. वह संत कबीर के गुरुभाई थे. उनके गुरु स्वामी रामानंद थे. महान संत रविदास चाहते थे कि लोग एक कुटुंब की तरह रहें. कभी किसी का किसी से विवाद न हो और न ही लोग आपस में झगड़ें. कवि रविदास ने लोगों के बीच भाईचारा और लगाव कायम रखने के लिए अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. लोकवाणी उनकी रचनाओं की विशेषता थी. संत रविदास का मानना था कि सादा जीवन, उच्च विचार से ही ख़ुद का और समाज का भला हो सकता है. वह कहते थे कि व्यक्ति बेवजह भौतिकता के चक्कर में पड़कर परेशानी मोल लेता है. उन्होंने समाज में फैली छुआछूत, ऊंच–नीच और अन्य कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की.

ऐसे थे रविदास

चारों तरफ पर्व का उल्लास था. पड़ोस के लोग गंगा–स्नान के लिए जा रहे थे. रविदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया, तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, लेकिन एक व्यक्ति को जूते बनाकर आज ही देने का वचन मैंने दे दिया है. यदि मैं उसे आज जूते नहीं दे सका, तो मेरा वचन भंग हो जाएगा. गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहां लगा रहेगा, तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा? मेरा मानना है कि जिस काम को करने के लिए अंत:करण तैयार हों, वही काम करना उचित है. अगर मन सही है, तो इस कठौते के जल में ही गंगास्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है.

संत रविदास की भक्ति से प्रभावित भक्तों की एक लंबी श्रृंखला है. रविदास के आदर्शों और उपदेशों को मानने वाले रैदास पंथी कहलाते हैं. मन चंगा तो कठौती में गंगा, उन्हीं की पंक्तियां हैं, जिसने भटके मानव को रास्ता दिखाया. उनकी सीख मनुष्य को बहुत कुछ सीखने का अवसर प्रदान करती है. रविदास के पद नारद भक्ति सूत्र और रविदास की बानी उनके प्रमुख संग्रह हैं. ■

समीक्षा

दुष्यंत की इस किताब में छोटी–छोटी 16 कहानियां हैं. लेखक जोखिम भरी निडरता के साथ हिंदी के समकालीन कथा लेखन के सामने अनुभव, स्थापत्य, भाषा और शैली की नई खिड़कियां खोलने की कोशिश करते हैं.

कविता

विचारधारा की बेड़ियों से उनमुक्त एक लेखिका

सुजाता शिवेन अनुवाद के क्षेत्र में तो अहम काम कर ही रही हैं, उन्होंने अपनी कविता संग्रह के माध्यम से अपने लेखक व्यक्तित्व के एक और पहलू को भी सामने रखा है. सुजाता की कविताएं मानवीय सरोकार के बंधन में बंधी हैं और विचारधारा की बेड़ियों में जकड़ी हुई नहीं हैं. इस वजह से यह पाठकों के मन के क़रीब है.

अनंत विजय

ठीक से याद नहीं है कि मैं लेखिका और अनुवादक के तौर पर हिंदी और उड़िया में ख्याति अर्जित कर चुकी सुजाता शिवेन से कब मिला, लेकिन अगर मेरी स्मृति मेरा साथ दे रही है, तो तक़रीबन पंद्रह साल पहले उनसे दिल्ली के उनके लक्ष्मीनगर के घर पर मुलाकात हुई थी. उनके पति जयप्रकाश पांडे हमारे मित्र हैं. उस वक्त हमलोग एक ही संस्थान में काम करते थे, लिहाजा दोस्ती रोज–रोज के साथ दफ्तर आने–जाने की भी थी. बहुधा जयप्रकाश जी, जिनको मैं शरारतपूर्वक पंडित जी कहकर बुलाता था, के घर हमारी बैठकी हुआ करती थी. उस वक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पत्रिका यंग इंडिया के संपादक अनिल अत्रि भी हमारी बैठकी में शामिल होते थे, बल्कि शायद वह पंडित जी के साथ ही रहते थे. अनिल अत्रि से मेरा परिचय भी वहीं हुआ था. हमलोग पंडित जी के घर पर जमकर विमर्श करते थे. बात शुरू होती थी राजनीति और समकालीन विषयों पर, लेकिन कई बार साहित्य तक भी जा पहुंचती थी. इन बहसों के बीच सुजाता जी स्नेहपूर्वक हमें लगातार चाय–पानी मुहैया करवाती रहती थीं. कई बार बहसों के दौरान कुछ टिप्पणियां भी कर देती थीं. यह सिलसिला कई सालों तक चला. बाद में सुजाता जी और पंडित जी के दिल्ली के द्वारका और मेरे मयूर विहार से इंदिरापुरम इलाके में शिफ्ट हो जाने की वजह से यह सिलसिला टूट गया, लेकिन इस बीच सुजाता जी ने अनुवाद का प्रचुर काम किया और एक अनुवादक के तौर पर अपने को स्थापित कर लिया. उन्होंने हिंदी रचनाओं का उड़िया में अनुवाद किया, जो उड़ीसा की महत्वपूर्ण पत्र–पत्रिकाओं में छपीं. सुजाता जी ने चित्रा मुद्गल, विश्वनाथ तिवारी, राजेंद्र अवस्थी जैसे वरिष्ठ लेखकों की रचनाओं का तो अनुवाद किया ही, साथ ही नए लेखकों में से सूर्यनाथ सिंह और ब्रजेंद्र त्रिपाठी की रचनाओं से उड़िया पाठकों का परिचय करवाया. सुजाता शिवेन ने साथ ही उड़िया के अहम लेखकों की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया. सुजाता जी की एक अनुवादक के रूप में छिपी प्रतिभा का पता मुझे बहुत बाद में चला. वह एक बेहतरीन अनुवादक हैं. उन्होंने हिंदी के पाठकों को उड़िया साहित्य के एक बड़े लेखक वर्ग और उनकी रचनाओं से परिचय कराया है. उनकी अब तक अनुवाद की तक़रीबन दर्जन भर किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और पांच किताबें प्रकाशनाधीन हैं. उनकी किताबें हिंदी के लगभग सभी शीर्ष प्रकाशकों के यहां से छप चुकी हैं. उन्होंने मनोज दास की कई

रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया, जो पुस्तकाकार प्रकाशित हैं. इसके अलावा, सीताकांत महापात्र, रमाकांत रथ, प्रतिभा राय, जेपी दास, बिपिन बिहारी मिश्र से लेकर इंदुलता मोहंती और महेंद्र के मिश्र जैसे उड़िया के बड़े लेखकों की कृतियों का भी अनुवाद किया. उन्हें हिंदी में एक अनुवादक के रूप में पर्याप्त ख्याति मिल चुकी है. सुजाता जी की हिंदी से उड़िया और उड़िया से हिंदी में आवाजाही से दोनों भाषा के पाठकों को लाभ मिलता है. उनके द्वारा उड़िया से हिंदी में अनुदित कई कृतियों को मैंने पढ़ा है, जो अनुवाद के बेहतर उदाहरण के तौर पर पेश किए जा सकते हैं. किसी एक कृति का नाम लेना अन्य कृतियों के साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि उड़िया और हिंदी, दोनों भाषाओं के स्थानीय शब्दों का ज्ञान होने की वजह से अनुवाद का प्रवाह बना रहता है, भाषा की रवानगी बाधित नहीं होती है और पाठकों को अपनी ही भाषा में पढ़ने का आस्वाद मिलता है.

मुझे सुजाता जी के अनुवाद के क्षेत्र में काम का अंदाजा था, लेकिन उनके कवि होने का इल्म मुझे नहीं था. यह मेरी अज्ञानता थी, क्योंकि बाद में पता चला कि उनकी हिंदी में लिखी कविताएं कई प्रतिष्ठित पत्र–पत्रिकाओं में छप चुकी थीं. मेरी नज़र तो तब पड़ी, जब एक दिन मैं शिल्पायन प्रकाशन के दफ्तर गया था. वहां मुझे ताजा–ताजा छपकर आई किताब कुछ और सच दिखा, जिसकी लेखिका सुजाता शिवेन थीं. मैंने किताब को पलटा, तो पता चला कि ये सुजाता की कविताओं का संग्रह था. मैं उनकी कविता संग्रह अपने साथ ले आया. घर लौटकर जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे सुजाता जी के अंदर छिपी एक कवि प्रतिभा का पता चला. कुछ और सच में सुजाता शिवेन की छोटी–बड़ी छियानवे कविताएं प्रकाशित हैं. हिंदी में किताबों के ब्लर्ब किसी मशहूर लेखक से लिखवाने या फिर बगैर नाम के ख़ुद ही लिख देने की परंपरा रही है, लेकिन सुजाता शिवेन ने अपने कविता संग्रह का ब्लर्ब ख़ुद से ही लिखा और उसमें बताया कि–इनमें खुशियां भी हैं, सपने और उम्मीदें भी. जाहिर है, जीवन संघर्ष तो इसमें होगा ही, हर नारी के जीवन में शायद यह किसी भी पुरुष से ज़्यादा जो होता है. इस एक वाक्य से सुजाता की कविताओं के बारे में पाठकों को अंदाज़ा हो जाता है. अपनी कविता जाने क्यों, में सुजाता कहती हैं– यूं ही क्या कम था/गम ज़िंदगी में/फसाना जाने क्यों/बना के लोग/जख्म बना देते हैं/क्यों हुए बेआबरू हम/पूछने की फुर्सत किसे/जाने क्यों कानाफूसी करने की लोग/जहमत उठा लेते हैं. इन पंक्तियों से कवयित्री के अंदर का जो भाव निकल कर आता है, वह हमारे समाज की मानसिकता पर, हमारे आसपास के लोगों की महिलाओं को लेकर सोच का पता देती है. इसी कविता की अंतिम लाइनें हैं– ज़िंदगी ने जब भी /पिलाया कड़वा घूंट/ हमने छक कर पी /जाने क्यों लोग/ बस अमृत/ पीना चाहते हैं. इन पंक्तियों से कवयित्री का एक तरीक़े से मोहभंग और समाज को लेकर एक उपेक्षा भाव, दोनों सामने आती है.

एक और कविता अलगाव में सुजाता शिवेन ने नारी मन की व्यथा को वाणी देते हुए बताती हैं कि किस तरह से एक महिला ख़ुद में सिमटने लगती है, जब वह किसी के बिछोह में होती है. सुजाता शिवेन की कविताओं का रेंज सिर्फ़ घर–परिवार समाज ही नहीं, बल्कि उससे भी आगे जाता है, लेकिन उनकी कविता का मूल स्वर नारी की संवेदना और नारीमन के विश्लेषण के अलग–अलग शेड्स लिए हुए है. इन कविताओं से गुजरते हुए पाठक बहुधा उससे एक रागात्मक संबंध बनाते हैं, जो सुजाता शिवेन की कविता की ताक़त है. भावना प्रधान कविताओं में मिलने की खुशी है, तो बिछड़ने का गम भी है, दर्द को पी जाने का जज्बा भी. कुल मिलाकर सुजाता शिवेन की कविताएं आज के दौर में विचारधारा विशेष के प्रभाव में लिखी जानेवाली नारेबाज कविता से अलग हटकर है, जो पाठकों को सुकून देती है. सुजाता की कविताएं मानवीय सरोकार के बंधन में बंधी हैं और विचारधारा की बेड़ियों में जकड़ी हुई नहीं है. इस वजह से यह पाठकों के मन के क़रीब है. कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि सुजाता शिवेन अनुवाद के क्षेत्र में तो अहम काम कर ही रही हैं, उन्होंने अपनी कविता संग्रह के माध्यम से अपने लेखक व्यक्तित्व के एक और पहलू को सामने रखा है. मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी के पाठक सुजाता जी की कविताओं को भी उसी तरह से पसंद करेंगे, जैसे उन्होंने उनके द्वारा अनुदित रचनाओं का स्वागत किया है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

कविता

ऐ धरा

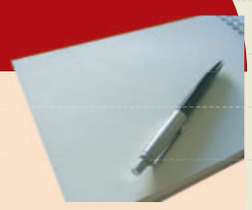

राजीव रंजन

ऐ धरा
क्या यौवन था तेरा
क्या समृद्धि, क्या हरियाली थी
जब पहनी तूने हरी साड़ी थी
पर, आज तू निर्वस्त्र है

ऐ धरा
पता है, कौन है तेरा दु:शासन
कोई नहीं, तेरे ही अपने जन
अपने दानवी कृत्यों से
तेरे शृंगार को कर दिए हैं सूना

ऐ धरा
तू मां है
अपने पुत्रों को सद्बुद्धि दे
कम से कम वे मुझे तो बख्शें
मेरे नीले वस्त्र को न खींचें

ऐ धरा
मेरे स्वाभिमान को न छेड़ें
मैं गिर जाऊंगा
हां, वज्रपात बनकर
तेरे जनों के ऊपर

ऐ धरा
तेरे सुपुत्र अपनी मौत को लेकर
तेरे आंगन में नाचेंगे
नहीं देख पाएगी तू
समझा उन्हें, नहीं तो पछताएंगे
ऐ धरा

किताब मिली

पुस्तक	लेखक
भारत एक तस्वीर	पैट्रिक फ्रेंच
प्रकाशक	**मूल्य**
पेंगुइन बुक्स	350

इस पुस्तक में भारत को बदलावों, तीखे विभाजनों और अनगिनत पहचानों वाला देश बताया गया है, जो धरती का सबसे बड़ा लोकतंत्र है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई-मेल: feedback@chauthiduniya.com

समीक्षा

दुष्यंत का प्रेम

चौथी दुनिया ब्यूरो

दुष्यंत की कहानियां इस अर्थ में विशिष्ट नहीं हैं कि वे हिंदी कहानियों की प्रचलित परंपरा से छिटकती हुई, अब तक प्रतिबंधित या वर्जित इलाक़ों में अद्भुत पठनीयता, भावुकता और उत्तेजना के साथ प्रवेश करती हैं, बल्कि वे इस अर्थ में विशिष्ट हैं कि जातीय, सामुदायिक और यौनिक टकराहटों को रोचकता और वैचारिक तर्कों के साथ पेश करती हैं. प्रेम की उप कथा में उन्होंने जिस किस्म के अनुभव बांटे हैं, वह अद्भुत, अजीब, लेकिन मर्मस्पर्शी हैं. लेखक एक जगह वर्णन करते हैं कि अकेले फिल्म देखना भी अजीब किस्म का अनुभव और शगल है, मगर बारह से तीन के शो में अकेले फिल्म देखना कभी–कभी मजबूरी भी हो सकती है. दुष्यंत शायद यही कहना चाहते होंगे कि एक नौकरीपेशा युवा संडे को ही बिना बॉस की डाट के इस शो में फिल्म देख सकता है. शायद इसलिए भी, क्योंकि एक नौकरी छूटने और दूसरी के लिए भाग–दौड़ के बीच हम पूरी तरह अकेले और असहाय सा होते हैं, तमाम एडवेंचर्स और अनुभवों के साथ. कहानी की व्याख्या करेंगे, तो हम पाएंगे कि कभी–कभार कोई दोस्त भले ही साथ हो ले, लेकिन जीवन रूपी गाड़ी हमें अकेले ही ढोनी पड़ती है.

सच तो यह है कि फिल्म देखना भी कितनी प्यारी सी चीज है, क्योंकि तीन घंटे तक आप अपनी दुनिया से निहायत दूर कल्पनालोक में विचरते हैं, तमाम व्यक्तिगत पीड़ाओं से अलग कुछ वक्त, जहां कुंठाओं का निवारण होता है और आप अपने आपको फैंटेसी में व्यस्त कर देते हैं.

दुष्यंत की इस किताब में छोटी–छोटी 16 कहानियां हैं. लेखक जोखिम भरी निडरता के साथ हिंदी के समकालीन कथा लेखन के सामने अनुभव, स्थापत्य, भाषा और शैली की नई खिड़कियां खोलने की कोशिश करते हैं. दरअसल, दुष्यंत का मानना है कि इस दौरान फिल्म ठीक एक दर्द निवारक गोली की तरह काम करती है और सारे दुख और पीड़ाओं को हर लेती है, चाहे कुछ वक्त के लिए ही सही. उन्होंने एक और कहानी लिखी है, ये भी समय है. लेखक का मानना है कि समय निर्मम है. वह प्रेम में व्यस्त है. एक नौकरी है, एक घर है, क्रेडिट कार्ड है, एक लोन है, रिश्ता है, सपना है, मंदी है, अमेरिका है, ओबामा है, खुशी है, उल्लास है और स्टार प्लस से कलर्स तक चमचमाता भारत है. यानी लेखक हमें इस सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं कि समय बेहतर है, इसलिए हम जिंदा हैं. समय उत्तम है कि सांसें अभी आ रही हैं और उसकी किश्तें नहीं देनी पड़ती. वह लिखते हैं कि मैं खुश हूं कि

दुष्यंत अपनी कहानियों में आज के समय और यथार्थ पर मार्मिक और तीखी टिप्पणी भर नहीं करते, बल्कि किसी किस्सागो के जादुई हुनर में पाठकों को बांध लेने वाली कहानियां, अपूर्व युवा वयस्कता के साथ प्रस्तुत करते हैं.

मेरा वजूद अभी है. समय अभी हमारा है, कल हो न हो.

एक और छोटी सी कहानी है. डायरी: जुलाई की एक रात. इस कहानी को पढ़कर ऐसा लगेगा, जैसे इसके सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं. अपनी छाती पर एक बड़ा सा पत्थर महसूस किया लेखक ने और जैसे ही लेखक की नींद खुली, ख़ुद को पसीने से तर पाया. यह एक सच्ची कहानी है. इसका संबंध दुनिया के किसी भी इलाक़े के, किसी भी व्यक्ति से हो सकता है.

ताला चाबी दरवाजा और संदूक, कहानी में महानगर के एक रेस्त्रा की चर्चा की गई है, जहां दोनों प्रेमी बैठे हैं और किसी की निगाह उन पर नहीं पड़ रही है. इस कहानी में एक संवाद है. कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें गालियां निकालो, भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ. ये छोटी–छोटी बातें पाठकों को बांध कर रखती हैं.

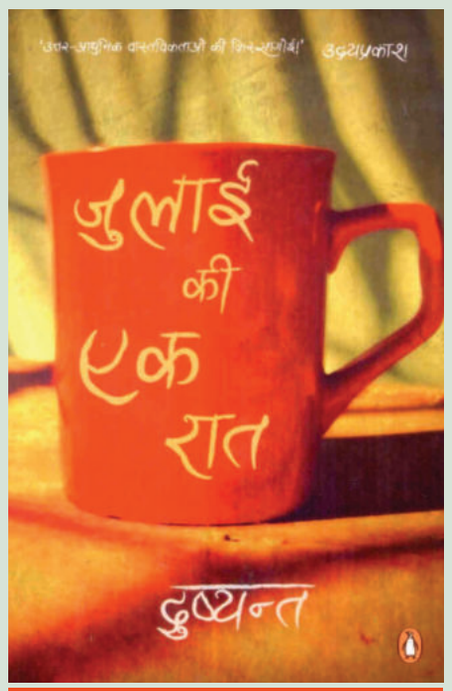

समीक्ष्य कृति : जुलाई की एक रात
लेखक : दुष्यंत
प्रकाशक : पेंगुइन बुक्स
क़ीमत : 125 रुपये

अधिकांशत: शहरी जीवन के इर्द–गिर्द मंडराती उनकी कथावस्तु हमारे समक्ष आधुनिक जीवन के तनावों, अंतर्विरोधों और मानसिक वैचारिक टकराव को खंगालती है. इन चीजों की छाया कहानी की भाषा में भी देखी जा सकती है. इस किताब में दुष्यंत ने शॉपिंग मॉल वाला नया हिंदुस्तान भी देखा है और गली मोहल्लों में धड़कने वाला अपना पुराना हिंदुस्तान भी. एक और कहानी का वर्णन दुष्यंत ने बड़े रोमांटिक मूड में किया है. सामने वाली टेबल पर एक लड़की को देखा, तो उन्हें ऐसा लगा, जैसे वक्त थम सा गया है. लेखक बहुत देर तक उस लड़की को निहारता है. बहुत देर तक इसलिए भी निहारता है, क्योंकि उस लड़की को उसके निहारते से कोई आपत्ति नहीं थी. उस प्यारी सी सूरत को देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे ईश्वर ने फुर्सत से उस लड़की को बनाया है और लेखक उस लड़की की सुनहरी यादों में खो जाता है...

दुष्यंत अपनी कहानियों में आज के समय और यथार्थ पर मार्मिक और तीखी टिप्पणी भर नहीं करते, बल्कि किसी किस्सागो के जादुई हुनर में पाठकों को बांध लेने वाली कहानियां, अपूर्व युवा वयस्कता के साथ प्रस्तुत करते हैं. यह एक पठनीय किताब है, क्योंकि इसमें छोटी–छोटी दिलचस्प और मार्मिक कहानियां हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

साइकिल का अस्तित्व 19वीं सदी से आया. इसे बाईसिकिल, बाइक, पुश बाइक, पैडल बाइक, पैडल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है. अभी भी दुनिया में साइकिल कई जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य माध्यम है. सबसे पहली साइकिल को जर्मनी के बैरोन वान ड्रेस ने तैयार की थी.

बजाज की शानदार बाइक

बजाज ने डिस्कवर का अपग्रेडेड मॉडल डिस्कवर 125टी उतारा है. इसकी क़ीमत 52,500 रुपये (एक्स शोरूम-दिल्ली) रखी गई है. डिस्कवर 125टी में कंपनी ने 125 सीसी की क्षमता का 4 स्ट्रोक इंजन इस्तेमाल किया है, जो इसे 12.5 पीएस की पावर देता है.

बाइक बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में टू व्हीलर रेंज का विस्तार करते हुए अपनी लोकप्रिय बाइक डिस्कवर का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने अपनी बाइक डिस्कवर का अपग्रेडेड मॉडल डिस्कवर 125टी उतारा है. इसकी क़ीमत 52,500 रुपये (एक्स शोरूम-दिल्ली) रखी गई है. डिस्कवर 125टी में कंपनी ने 125 सीसी की क्षमता का 4 स्ट्रोक इंजन इस्तेमाल किया है, जो इसे 12.5 पीएस की पावर देता है. कंपनी ने नई डिस्कवर 125टी में 5 स्पीड स्टैंडर्ड गियर बॉक्स का प्रयोग किया है, जो बजाज की पुरानी बाइक की तरह ही है.

नई बजाज डिस्कवर 125टी में कंपनी ने डीटीएसआई तकनीक का प्रयोग किया है, जो बाइक का माइलेज शानदार बनाती है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक 77 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी. बजाज डिस्कवर 125टी की अधिकतम स्पीड 105 किलो मीटर प्रति घंटा होगी.

इस स्पोर्टी बाइक में एलॉय व्हील का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी की ओर से इस बाइक में ड्रम ब्रेक की जगह पर डिस्क ब्रेक लगाने की भी सुविधा दी गई है, लेकिन उससे बाइक की क़ीमत बढ़कर लगभग 55,500 रुपये हो जाएगी. ■

निसान की नई सनसनी

निसान मोटर के प्रमुख एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॉर्लस गोस्न ने बताया है कि डैटसन ब्रांड की हैचबैक कार में 1.2 लीटर का इंजन होगी और इसकी क़ीमत चार लाख रुपये से कम होगी.

जापानी कार निर्माता कंपनी निसान ने अगले वर्ष की प्रथम तिमाही में भारतीय बाजार में डैटसन ब्रांड की छोटी कारों को पेश करने की घोषणा करते हुए अपनी पहली कार डैटसन लॉन्च कर दी है. निसान मोटर के प्रमुख एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॉर्लस गोस्न ने इस मौक़े पर बताया कि डैटसन ब्रांड की इस हैचबैक कार में 1.2 लीटर का इंजन होगी और इसकी क़ीमत चार लाख रुपये से कम होगी. उन्होंने बताया कि इस कार को अगले वर्ष के प्रारंभ में पेश करने की तैयारी चल रही है. निसान मोटर वर्ष 2016 तक भारतीय बाज़ार में कारों के 10 नये मॉडल पेश करेगी. कंपनी की योजना भारतीय कार बाज़ार में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की है और अधिकारियों को विश्वास है कि डैटसन के बल पर वे ये आंकड़े छू सकेंगे. वहीं निसान डैटसन के कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट विन्सेंट कोबी का कहना है कि डैटसन की कामयाबी में भारतीय बाज़ार एक बड़ा रोल अदा करेगा. उन्होंने आगे कहा कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारतीय बाज़ार में बहुत प्रतिस्पर्धा है. यहां काम चुनौतीपूर्ण होगा. कंपनी भारत के साथ-साथ इंडोनेशिया और रूस में एक साथ इस कार को पेश करेगी. डैटसन कारों का निर्माण निसान के भारतीय संयंत्र में होगा और इसमें स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया जाएगा. डैटसन का लॉन्च होना मारुति और हुंडई के लिए ख़तरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि छोटी कारों के बाज़ार में इन दोनों कंपनियों की दो तिहाई हिस्सेदारी है. उम्मीद जताई जा रही है कि इसके लॉन्चिंग के बाद छोटी कार बाज़ार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी. ■

आईबॉल का लाजवाब स्मार्टफोन

अगर आप एक सस्ता एंड्रॉयड फोन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी ख़बर है. मोबाइल और कंप्यूटर एसेसरीज बनाने वाली भारतीय कंपनी आईबॉल ने एक बेहद सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है. आईबॉल एंडी 3.5 केकेई नाम के इस फोन की क़ीमत सिर्फ़ 3,399 रुपये है. ड्यूल सिम वाले इस फोन में 3.5 ईंच का डिस्प्ले है. इस फोन में 3.2 मेगापिक्सल ऑटो फोकस रियर और वीजीए फ्रंट कैमरा लगा हुआ है. इस फोन में 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर और 2.3 जिंजरब्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो काफ़ी पुराना है. एंडी 3.5 में 256 एमबी का रैम और 512 एमबी की इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे 32जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इस फोन में कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, ब्लूटूथ, ऐज, जीपीआरएस और जीपीएस की सुविधा के साथ ही 1,450 एमएच की बैटरी है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

जोश का नया धमाका

8 एमपी रियर एवं 3 एमपी फ्रंट कैमरा से युक्त फॉर्च्यून एचडी उनके लिए काफ़ी यूजफुल है, जो फोटोग्राफी के शौकिन हैं. फॉर्च्यून एचडी के वीडियो कॉलिंग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है.

जोश मोबाइल ने अपना नया फोन फॉर्च्यून एचडी लॉन्च कर अपनी स्मार्टफोन श्रृंखला को और अधिक सशक्त बना दिया है. फॉर्च्यून एचडी का यह हाई डेफिनेशन स्मार्टफोन है. 5.3 ईंच हाई डेफिनेशन स्क्रीन के साथ प्रारंभ होने वाली इस श्रृंखला के फोन शानदार ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया अनुभव के साथ देखने में काफ़ी आकर्षक है. इसके 960-540 के स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ कलर वीडियो का आनंद उपभोक्ता उठा सकते हैं. 8 एमपी रियर एवं 3 एमपी फ्रंट कैमरा युक्त फॉर्च्यून एचडी उनके लिए काफ़ी यूजफुल है, जो फोटोग्राफी के शौकिन हैं. फॉर्च्यून एचडी के वीडियो कॉलिंग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है.

आइसक्रीम सैंडविच ऑपरेटिंग सिस्टम 4.0.4 पर संचालित फॉर्च्यून एचडी को 1.2 जीएचजेड ड्यूल कोर प्रोसेसर का समर्थन प्राप्त है, जिसकी वजह से यह उपकरण मल्टी टास्किंग के लिए बेहद उपयुक्त है. असीमित गाने डाउनलोड किए जा सकते हैं. 2 जीबी की मेमोरी विद्यमान है, जिसे 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. साथ ही उपकरण में 2400 एमएएच की बैटरी भी लगी हुई है, जो उपभोक्ताओं को अपने फॉर्च्यून एचडी के साथ लंबी अवधि तक कार्य करने और साथ ही गेमिंग का अवसर प्रदान करती है. ड्यूल सिम ख़ूबी के साथ ही इसमें जीपीएस एवं ए-जीपीएस भी हैं, जो रास्ते भटक जाने पर आपको आपके गंतव्य तक पहुंचने में मदद करेंगे. अन्य ख़ूबियों में जी-सेंसर्स, प्रॉक्जिमिटी सेंसर्स एवं अन्य तकनीक विद्यमान हैं, जो इसे सभी के लिए आदर्श फोन के रूप में स्थापित करते हैं. जोश मोबाइल्स के निर्देशक दीपक कुमार कहते हैं कि फॉर्च्यून एचडी कई ख़ूबियों से भरपूर है और इसकी हाई डेफिनेशन स्क्रीन उपभोक्ताओं को उच्च स्तरीय व्यूइंग अनुभव प्रदान करेगी. फॉर्च्यून एचडी की क़ीमत 11,999 रुपये है. ■

शान की सवारी, स्वास्थ्य भी रखे ठीक

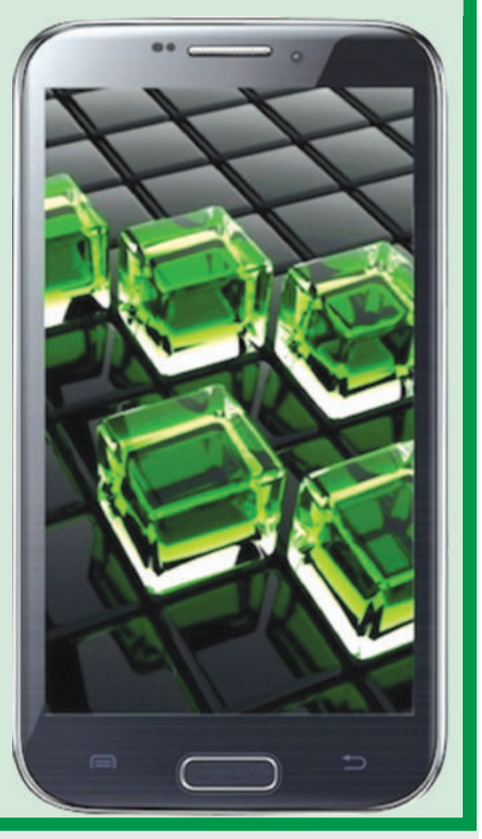

प्रियंका प्रियम तिवारी

एक समय था, जब साइकिल की सवारी सभी को पसंद आती थी, लेकिन बदलते परिवेश में साइकिलें तो बड़े शहरों से बिल्कुल ही ग़ायब हो गईं, लेकिन एक बार फिर सड़कों पर साइकिलें अपने अलग अंदाज में रफ्तार भरती नज़र आएंगी. जी हां, साइकिलों में वक्त और ज़रूरतों के अनुसार, कुछ ख़ास बदलाव की गई हैं. जहां पहले की साइकिलें सिर्फ एक सीधे डंडे और पारंपरिक स्टील की हैंडल के साथ होती थीं, वहीं आज की साइकिलों में मोटरसाइकिलों से भी अधिक गियर दिए गए हैं. हैंडल को पहले से ज़्यादा ख़ूबसूरती दी गई है. इसके साथ ही इसे काफ़ी आरामदायक भी बनाया गया है. आज भी लोग साइकिल की सवारी काफ़ी पसंद करते हैं, अगर सुबह-सवेरे दिल्ली में राजघाट या फिर इंडिया गेट पर जाकर देखें, तो पता चलेगा कि साइकिलों की दीवानगी किस क़दर लोगों में है. आइए जानते हैं कि आज की साइकिलों में क्या ख़ास बदलाव किए गए हैं.

साइकिल का अस्तित्व 19वीं सदी में आया है. इसे बाईसिकिल, बाइक, पुश बाइक, पैडल बाइक, पैडल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है. अभी भी दुनिया में साइकिल कई जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य माध्यम है. सबसे पहली साइकिल को जर्मनी के बैरोन वान ड्रेस ने तैयार की थी. यह साइकिल लकड़ी से बनाई गई. साइकिल में रबर का टायर 1842 में लगा. भारत की बात करें, तो सबसे पहली साइकिल 1890 में देखी गई और भारत में इसका आयात 1905 में शुरू हुआ और यह अनवरत 50 सालों तक जारी रहा, लेकिन भारत सरकार ने साइकिलों के आयात पर 1953 में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और इसके बाद देश में साइकिलें बननी शुरू हुईं. भारत में 1890 में आयातित साइकिलों की क़ीमत 45 रुपये थी, जो 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद काफ़ी बढ़ गई.

चलन क्यों बढ़ा

ज़िंदगी के आरामदायक होते जाने से जब लोगों की फिजिकल एक्टीविटी कम होने लगी, तो उनकी ज़िंदगी में तरह-तरह की बीमारियों ने घर करना शुरू कर दिया. इन बीमारियों से दूर रहने के लिए जब लोगों ने विकल्प ढूंढना शुरू किया, तो उन्हें साइकिल सबसे बेहतरीन टूल लगा, जिससे उनके ट्रैवलिंग का मकसद भी पूरा हो रहा था और व्यायाम भी. छोटे शहरों में जहां यह इसे ज़रूरत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वहीं बड़े शहरों में एडवेंचर के तौर पर अत्याधुनिक साइकिलों का इन दिनों ख़ूब इस्तेमाल हो रहा है.

वर्तमान में साइकिलों के कई मॉडल देखने को मिलेंगे, जिनमें ख़ास है फुल सस्पेंशन, हार्ड ट्रेल, रोड, हाइब्रिड, क्रूजर, बीएमएक्स, किड्स, ट्रैक्स, गैरी फिशर और टर्न. ये साइकिलें काफ़ी मशहूर हैं. इन कैटेगरी में कई तरह की साइकिलें हैं, जिनमें बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग साइकिलें हैं. गति को बेहतरीन रखने के लिए इसमें कंपनियां बहुत सारे गियर देती हैं, जिसे आप सुविधानुसार बदल सकते हैं. ये बेहद हल्की होती हैं. पावर टू वेट रेशियो बेहतरीन होने से ये चलने में सहज रहती हैं.

क्या कहते हैं साइकिल निर्माता

फायर फॉक्स के डिप्टी जनरल मैनेजर मार्केटिंग अजीत गांधी कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत के साइकिल बाज़ार में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुई है. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, लोगों का हेल्थ कॉन्शस होना. हर कोई आजकल हेल्दी रहना चाहता है और साइकिल के रूप में उसे व्यायाम का बेहतरीन जरिया मिल गया है. यह रोमांचक भी है और शरीर की कैलोरीज बर्न करके मोटापे को दूर भी करता है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

> ताजा रैंकिंग पाकिस्तान और टी–20 विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की शृंखला से पहले जारी की गई. गौरतलब है कि जून में लंदन में आईसीसी बोर्ड की बैठक के दौरान टी–20 रैंकिंग की अवधि तीन की बजाय चार साल करने पर सहमति बनी थी.

इंडियन बैडमिंटन लीग

क्या बदलेगी भारतीय बैडमिंटन की तस्वीर

इंडियन बैडमिंटन लीग के आयोजन की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं. टीमों के साथ साथ खिलाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. प्रशंसकों को लीग के आगाज़ का इंतज़ार है. लोगों के ज़हन में लीग के आयोजन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लीग की सफलता और असफलता को लेकर उठ रहे हैं. आईबीएल से देश में बैडमिंटन के चरित्र को बदलने की आशा की जा रही है क्या आईबीएल भारत में बैडमिंटन की चाल, चरित्र और चेहरा बदलने में कामयाब होगा या फिर आईबीएल भी एक औद्योगिक घरानों की एक ऐसी यूनिट बनकर रह जाएगी. जहां पैसा ही सब कुछ है...

फ्रेंचाइजी

दिल्ली	दिल्ली स्मैशर्स,	कृष ग्रुप
हैदराबाद	हैदराबाद हॉटशॉट्स	पीवीपी ग्रुप
बेंगलूरु	बांगा बीट्स	बीओपी ग्रुप
लखनऊ	लखनऊ वॉरियर्स	सहारा
पुणे	पुणे पिस्टंस	बर्मन परिवार
मुंबई	मुंबई मास्टर्स	नागार्जुन, सुनील गावस्कर व चामुंडेश्वरनाथ

नवीन चौहान

हमारे देश में खेल व्यापार बनता जा रहा है. देश के अधिकांश खेल प्राधिकरण आईपीएल की तर्ज पर लीग आयोजित करने की दिशा में काम कर रहे हैं. अब इंडियन बैडमिंटन लीग(आईबीएल) के रूप में बैडमिंटन का एक नया रूप जनता के सामने आया है. 10 लाख डॉलर इनामी राशि वाली आईबीएल का आयोजन 14 से 31 अगस्त के बीच देश के छह शहरों में होगा. विश्व के सबसे धनी बैडमिंटन लीग में दुनिया भर के शीर्ष–50 खिलाड़ी शिरकत करते नज़र आएंगे. आईपीएल की तर्ज पर पैसे और शोहरत की चाह में शुरू हो रही आईबीएल के लिए फ्रेंचाइजियों और खिलाड़ियों की बिक्री की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई. इसके साथ ही टीमों और खिलाड़ियों की नीलामी को लेकर कई महीनों से लगाई जा रही अटकलों पर भी विराम लग गया है. एक तरफ़ मास्टर–ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर द्वारा महीनों से आईबीएल टीम ख़रीदे जाने की बात हो रही थी, जो ग़लत साबित हुई, लेकिन उनकी जगह अप्रत्याशित रूप से सुनील गावस्कर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मुंबई की टीम ख़रीद ली.

दुनिया भर के 150 से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ियों को ख़रीदने के लिए 6 टीमों ने बोली लगाई. छह खिलाड़ियों को आइकॉन खिलाड़ियों के रूप में शामिल किया गया. हर टीम केवल एक आईकॉन खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल कर सकती थी. आईबीएल में छह आइकॉन खिलाड़ियों में शामिल भारत की नंबर एक महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल को हैदराबाद हॉटशॉट्स ने 1.2 लाख अमेरिकी डॉलर(70 लाख रुपये) में ख़रीदा है. उनका बेस प्राइस 50 हज़ार डॉलर था. वहीं, पुरुषों में मलेशिया के लेई चोंग वेई को मुंबई मास्टर्स ने 1.35 लाख डॉलर में ख़रीदा है. वहीं भारतीय बैडमिंटन की ग्लैमर गर्ल ज्वाला गुट्टा और उनकी जोड़ीदार अश्विनी पुनप्पा के हाथ निराशा लगी है. दोनों ही आइकॉन खिलाड़ियों के लिए उम्मीद से कम बोली लगी. इन दोनों युगल विशेषज्ञ खिलाड़ियों के लिए आधार कीमत 50 हजार डॉलर तय की गई थी. चूंकि आईबीएल में कोई युगल मैच नहीं है, लिहाजा फ्रेंचाइजी टीमों ने टूर्नामेंट की कार्यकारिणी से इन दो आइकॉन खिलाड़ियों की आधार क़ीमत 50 हज़ार से घटाकर 25 हज़ार डॉलर करने की मांग की थी. कार्यकारिणी ने उनकी इस मांग को मान लिया और दोनों खिलाड़ियों का बेस प्राइस घटाकर 25 हज़ार डॉलर कर दिया. प्रत्येक फ्रेंचाइजी 11 खिलाड़ी ख़रीदने के लिए सिर्फ़ डेढ़ करोड़ रुपये ही ख़र्च कर सकती थी. इसके साथ ही हर टीम के लिए टीम में अधिकतम चार विदेशी और अपने क्षेत्र के एक अंडर–19 खिलाड़ी को टीम में रखना भी अनिवार्य किया गया था. लीग में राउंड रॉबिन और नॉक आउट आधार पर मैच खेले जाएंगे. दो टीमों के बीच मैच दो में चरण में घरेलू(होम) और बाहरी मैच(अवे) के रूप में खेले जाएंगे. लीग के एडमिनिस्ट्रेटर भारतीय बैडमिंटन संघ ने चोटी के खिलाड़ियों का लीग में भाग लेना अनिवार्य कर दिया है.

आईबीएल में नई स्कोरिंग प्रणाली लागू की गई है, जिसे सभी टीम के कोचों ने दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण बताया है. नई स्कोरिंग प्रणाली के अनुसार, पहले दो गेम में 7वें और 14वें प्वॉइंट के बाद 60 सेकेंड के दो ब्रेक होंगे. यदि गेम तीसरे सेट तक पहुंचता है, तो यह ब्रेक 6वें अंक के बाद होगा. इसके अलावा, पहले दो गेम स्टैंडर्ड दो अंकों के अंत के बिना 21 प्वॉइंट पर ख़त्म होंगे, लेकिन तीसरे और निर्णायक सेट में जो खिलाड़ी पहले 11वें अंक तक पहुंचेगा, वह मैच का विजेता बनेगा. इस नई स्कोरिंग प्रणाली की वजह से मैच प्रतिस्पर्धी होते दिख रहे हैं. इस नए स्कोरिंग पैटर्न की वजह से ऊंचे पायदान के खिलाड़ियों को हराने में निचली रैंकिंग के खिलाड़ी भी सफल हो सकते हैं. नई स्कोरिंग प्रणाली का फ़ायदा आक्रामक खेलने वाले खिलाड़ियों को ज़्यादा मिलेगा. ब्रेक खिलाड़ियों की लय बिगाड़ सकते हैं. अन्य स्टैंडर्ड स्कोरिंग प्रणाली के नियम पहले की तरह ही रहेंगे, जिसमें पहले और तीसरे गेम के पहले खिलाड़ियों को दो–दो मिनट का ब्रेक मिलेगा, जबकि निर्णायक गेम के 6वें अंक पर खिलाड़ी अपने सर्विस कोर्ट बदलेंगे. मैचों के प्रारूप में भी थोड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि इसमें पांच मैचों में दो पुरुष एकल, एक महिला एकल, एक पुरुष युगल और मिश्रित युगल मुक़ाबला होगा. जो टीम ज़्यादा मुक़ाबलों में जीत दर्ज करेगी, वही टीम विजेता बनेगी. इस लीग से सभी को बड़ी आशाएं हैं, साथ ही सभी के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं. जैसे कि क्या यह लीग नये विश्वस्तरीय खिलाड़ी बना पाएगी, जो ओलंपिक पदक और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन जैसे खिताब जीतकर भारत को गौरवान्वित करेंगे. इस बात की क्या गारंटी है कि आईबीएल केवल औद्योगिक या व्यावसायिक लीग बनकर नहीं रह जाएगी. क्या यह बैडमिंटन को भारत में क्रिकेट की तरह घर–घर तक पहुंचा पाएगा, जिससे कि देश में सायना नेहवाल और पुलेला गोपीचंद जैसे नये खिलाड़ी उभर सकें. कहीं ऐसा न हो कि लीग का दायरा महानगरों तक ही सीमित रह जाए और छोटे शहरों के खिलाड़ियों को इसका फ़ायदा न मिल सके.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि लीग से खिलाड़ियों को फाइनांशियल स्टेबिलिटी तो मिलेगी ही, साथ ही उनकी सरकारी महकमों पर छोटी–छोटी जरूरतों के लिए निर्भरता कम होगी. इसके साथ ही घरेलू खिलाड़ियों को एक घरेलू प्रतियोगिता में अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिल सकेगा, जो कि उनके खेल करियर में एक मील का पत्थर साबित होगा. आईबीएल में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर भी सवाल खड़ा होता है. लीग के पहले सीजन में कुल 90 मैच खेले जाने हैं. बड़ा सवाल यह है कि लीग में भाग लेने की अनिवार्यता की वजह से कहीं खिलाड़ियों की फिटनेस जवाब न दे जाए और उनके अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर सवालियां निशान न खड़ा हो जाए, जिससे कि ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत दर्ज करने की भारतीय संभावनाओं को धक्का लगे. जिस तरह सायना पिछले सीजन लंदन ओलंपिक के बाद चोट से जूझती रही हैं, पहले से ही व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के बीच आईबीएल का आयोजन खिलाड़ियों के लिए थकान भरा साबित हो सकता है. खेल के नए स्कोरिंग पैटर्न की वजह से भी खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुक़सान हो सकता है, क्योंकि नए पैटर्न में जिस तरह के बदलाव किए गए हैं, उसका खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा. आईबीएल से देश में बैडमिंटन के चरित्र को बदलने की आशा की जा रही है. आईबीएल भारत में बैडमिंटन की चाल, चरित्र और चेहरा बदलने में कामयाब होगा या नहीं, यह एक यक्ष प्रश्न है, जिसके जवाब के लिए हमें अभी लंबा इंतज़ार रहेगा.■

navinchauhan@chauthiduniya.com

आइकॉन खिलाड़ी

ली चोंग वेई (मलेशिया)
सायना नेहवाल (भारत)
ज्वाला गुट्टा (भारत)
अश्विनी पोनप्पा (भारत)
पीवी सिंधु (भारत)
पी कश्यप (भारत)

पाक क्रिकेटर आसिफ ने फिक्सिंग स्वीकारी

क्रिकेट की पूरी दुनिया बेइंतहा दिवानी है, लेकिन इस खेल के साथ काफ़ी पहले से एक कलंक साथ चला आ रहा है. वह कलंक है स्पॉट फिक्सिंग का. हालांकि क्रिकेट के लिए यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि विवादों से क्रिकेट का चोली–दामन का साथ रहा है. मामला भले ही पुराना हो, लेकिन बोतल से फिक्सिंग का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है. ताजा मामले में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ ने स्वीकार किया है कि उन्होंने 2010 में स्पॉट फिक्सिंग की थी. उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्य संचालन अधिकारी सुभान अहमद के सामने यह क़बूल किया. पीसीबी के शीर्ष सूत्रों ने कहा है कि आसिफ ने अहमद से मुलाकात के दौरान कबूल किया है कि वह इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 2010 में लार्ड्स में खेले गए चौथे टेस्ट मैच के दौरान स्पॉट फिक्सिंग में लिप्त थे. सूत्र ने पिछले दिनों कहा कि आसिफ अपने किए पर शर्मिंदा हैं. वह काफ़ी दिनों से चाहते थे कि अपनी ग़लती स्वीकारें, लेकिन वह सच्चाई बयां करने से डर रहे थे.

गौरतलब है कि आसिफ के अलावा, सलमान बट और मोहम्मद आमिर को स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों में 2011 के शुरू में सिर्फ पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था. ■

आईसीसी टी–20 रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर बरक़रार

खेल में जीत से ज़्यादा ज़रूरी है, पिछली जीत से हासिल स्थान को बरक़रार रखना. इस जुमले को एक बार फिर भारत ने साबित कर दिया है. भारत आईसीसी द्वारा जारी ताजा टी–20 रैंकिंग में आज भी तीसरे स्थान पर बना हुआ है. श्रीलंका ने नंबर वन के ताज पर क़ब्ज़ा बरक़रार रखा है. ताजा रैंकिंग पाकिस्तान और टी–20 विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की शृंखला से पहले जारी की गई. गौरतलब है कि जून में लंदन में आईसीसी बोर्ड की बैठक के दौरान टी–20 रैंकिंग की अवधि तीन की बजाय चार साल करने पर सहमति बनी थी. आईसीसी बोर्ड ने टेस्ट, वन–डे और टी–20 की सालाना रैंकिंग 1 अगस्त की बजाय 1 मई को जारी करने का भी फ़ैसला किया. इस बदलाव को लागू भी कर दिया गया है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

जगमगदुनिया

05 अगस्त–11 अगस्त 2013

सोनम कपूर की लूटेरा, फरहान स्टारर भाग मिल्खा भाग और रामइया वस्तावइया एक साथ रीलीज हुई. इन फिल्मों में शुरुआत में लूटेरा औसत रही, जबकि भाग मिल्खा भाग जुलाई की बड़ी हिट रही. वहीं प्रभुदेवा की निर्देशन में बनी फिल्म रामइया वस्तावइया की पटकथा कुछ नई नहीं है, लेकिन इस फिल्म को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया.

बॉलीवुड के लिए सुखद रहा यह साल

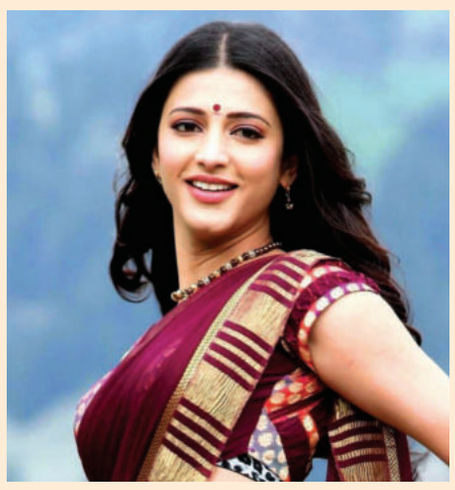

एक दौर था, जब फिल्मों का भविष्य पारिवारिक, मसाला और एक्शन फिल्मों के शौकीन दर्शक तय करते थे, लेकिन आज की फिल्मों का भविष्य यंगस्टर्स तय करते हैं, तो ऐसे में फिल्म मेकर कम बजट में युवाओं को ध्यान में रखकर फिल्में बनाने लगे हैं और ये फिल्में हिट भी हो रही हैं. इस साल अब तक रीलिज हुई फिल्मों में लगभग 20 फिल्मों ने अच्छी कमाई की, जबकि बाकी फिल्में फ्लॉप रहीं. ये फिल्में युवाओं पर आधारित फिल्में थीं. आपको बता दें कि हर साल औसतन दस से पंद्रह फीसद फिल्में ही लागत वसूलने के बाद अच्छी कमाई कर पाती हैं, लेकिन इस साल आठवें महीने तक लगभग 20 फिल्मों की कामयाबी से इंडस्ट्री में खुशी की लहर है.

पूरे साल में 15 फिल्में हिट हो जाती हैं, तो वह साल व्यवसायिक दृष्टि से सफल माना जाता है. ऐसे में, सिर्फ छमाही में हिट हुईं कई फिल्मों ने तमाम फ्लॉप फिल्मों के बावजूद, बॉलीवुड के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, जबकि 200 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही ये जवानी है दीवानी, और कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपये का कलेक्शन इस छमाही का सबसे बड़ा अचीवमेंट है. वहीं खिलाड़ी मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म भाग मिल्खा भाग देश ही नहीं, विदेशों में भी खूब धूम मचा रही है. अमेरिका में रिलीज के पहले तीन दिनों में फिल्म ने 3.19 करोड़ का कारोबार किया, जबकि भारत में इस फिल्म ने छह दिनों के भीतर 60 करोड़ के करीब बिजनेस किया है. अभी यह अमेरिका के 140 सिनेमाघरों में चल रही है. फिल्म का अब तक का घरेलू बाजार 48 करोड़ का और ओवरसीज में कारोबार 10 करोड़ से अधिक हुआ है. जल्द ही यह 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी. वहीं फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी फिल्म फुकरे का रिस्पॉन्स भी मिला-जुला रहा. हालांकि फिल्म की रिलीज के शुरुआती दो दिनों में फिल्म ने 5.72 करोड़ का बिजनेस किया है. वहीं अतुल सभरवाल की फिल्म औरंगजेब को दिल्ली और उसके आसपास के दर्शकों ने अधिक पसंद किया. उत्तर भारत के अन्य शहरों में भी इसे मुंबई और पश्चिम भारत की तुलना में अधिक दर्शक मिले. औरंगजेब का कलेक्शन 13 करोड़ के लगभग रहा. सैफ अली खान और कुणाल की फिल्म गो गोवा गॉन ने अपने जबरदस्त प्रमोशन के चलते ओपनिंग वीक एंड में 12.5 करोड़ का आंकड़ा छू लिया. वहीं संजय गुप्ता की फिल्म शूटआउट एट वडाला ने रिलीज के पहले दो दिन में लगभग 20 करोड़ रुपये की कमाई की है. संजय गुप्ता की इस मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म ने 10.1 करोड़ रुपये की कमाई की.

ऐसा माना जाता है कि साल भर में अगर 15 के करीब फिल्में हिट हो जाएं, तो उसे हिट साल माना जाता है. इस लिहाज से अगर देखा जाए, तो अभी आठ महीने में ही 20 के लगभग फिल्में हिट हो चुकी हैं. कुछ ने अपनी लागत से ज्यादा वसूल की, तो कुछ फिल्मों ने बहुत ज्यादा कमाई की. हालांकि अभी अगले महीने शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रितिक रोशन, रणवीर कपूर और आमिर खान जैसे बड़े सितारों की फिल्में रिलीज होनी बाकी ही हैं.

पहले महीने की हिट 2013 की पहली छमाही की शुरुआत राजधानी एक्सप्रेस, देहरादून डायरी और टेबल नंबर 21 जैसी सुपर फ्लॉप फिल्मों से हुई. वैसे तो, जनवरी में सात-आठ दूसरी फिल्में भी रिलीज हुईं, लेकिन ट्रेड की निगाहें मेगा बजट फिल्मों मटरू की बिजली का मंडोला और रेस 2 पर टिकी थीं. करीब 48 करोड़ के बजट में बनी मटरू की बिजली का मंडोला, ढाई हजार से ज्यादा सिनेमाघरों में

रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म की नाकामयाबी ने पूरे ट्रेड जगत को झकझोर कर रख दिया. मुनाफा कमाना तो दूर, यह फिल्म अपनी लागत तक नहीं निकाल पाई. हालांकि रेस 2 की जबर्दस्त कामयाबी ने इस गम को खुशी में बदल दिया. करीब 69 रुपये की बजट में बनी इस फिल्म ने देश-विदेश में 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर इंडस्ट्री को नये साल में जश्न मनाने का मौका दे दिया. दूसरे महीने, यानी फरवरी में लीक से हटकर बनी कुल 11 फिल्में रिलीज हुईं. इनमें लो बजट की फिल्म कोई पो चे ने पहले हफ्ते में ही 30 करोड़ का आंकड़ा छुआ. वहीं, जिला गाजियाबाद का प्रदर्शन सिनेमाघरों में कमजोर रहा, लेकिन यह फिल्म यूपी और कई दूसरे राज्यों के छोटे शहरों में पसंद की गई. इसी बीच अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 ने 80 करोड़ कमाये, तो प्रभुदेवा की ऑफबीट फिल्म एबीसीडी भी मुनाफे में रही. बाकी बची फिल्में, कमाना तो दूर, अपनी लागत भी नहीं वसूल पाईं.

मार्च में रिलीज हुई कुल 12 फिल्मों में साहिब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स, जॉली एलएलबी और मेरे डैड की मारुति जैसी ऑफबीट फिल्मों ने औसत कमाई की. वहीं, अजय देवगन स्टारर हिम्मतवाला के अलावा आत्मा, रंगरेज, आई मी और हम, 3जी, दि अटैक ऑफ 26/11 की जबर्दस्त नाकामी ने सिनेमा मालिकों और वितरकों को निराश कर दिया. खासकर हिम्मतवाला का फ्लॉप होना दुखद रहा.

अप्रैल में आदित्य कपूर और शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर की आशिकी2 हिट रही.

लो बजट की यह फिल्म नए कलाकारों को लेकर बनाई गई थी. महज 8 करोड़ के बजट में बनी आशिकी2 की जबर्दस्त कामयाबी से बालीवुड ट्रेड जगत में खुशी की लहर दौड़ गई. इसी महीने डेविड धवन की नई स्टार कास्ट को लेकर बनी चश्मेबद्दूर भी हिट रही. इसी महीने दो और बहुचर्चित फिल्में रीलिज हुईं. उनमें से एक थी, एकता कपूर कैंप की, एक थी डायन और दूसरी आयुष्मान खुराना स्टारर नौटंकी साला, पर ये दोनों ही फिल्में इंडस्ट्री की उम्मीदों पर पानी फेर गईं.

मई में 11 फिल्में रीलिज हुईं. इनमें से, ये जवानी है दीवानी, पहले वीकेंड में ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. फिलहाल, 200 करोड़ की कमाई करने की कोशिश में लगी यह फिल्म ट्रेड को साल की पहली सुपरहिट का जश्न मनाने का मौका दिया. वहीं, प्रीति जिंटा की इश्क इन पेरिस और सैफ अली खान की गो गोवा गोन सहित बाकी बची फिल्मों को दर्शकों ने पहले ही दिन ठुकरा दिया.

जून में यमला पगला दिवाना, फूकरे, अंकुर अरोडा मर्डर केस, एनमी, शॉर्टकट रोमियो, रांझना और घनचक्कर रिलीज हुई. सन्नी देओल के होम प्रोडक्शन में बनी फिल्म यमला पगला दिवाना ने जहां निराश किया, वहीं फूकरे यंगस्टर्स को खूब भाई. डॉक्टरों की लापरवाही पर बनी फिल्म अंकुर अरोड़ा मर्डर केस को एक खास वर्ग के दर्शकों द्वारा ही पसंद किया गया. विद्या बालन और इमरान हाशमी की फिल्म घनचक्कर ने दर्शकों को काफी निराश किया. वहीं सोनम कपूर के होम प्रोडक्शन की फिल्म रांझना इस महीने की बड़ी हिट रहीं. सोनम और धनूष की अभिनय की भी काफी तारीफ हुई.

जुलाई में सोनम कपूर की लूटेरा, भाग मिल्खा भाग और रामइया वस्तावइया रिलीज हुई. इनमें शुरुआत में लूटेरा औसत रही, जबकि भाग मिल्खा भाग इस महीने की बड़ी हिट रही. वहीं प्रभुदेवा की निर्देशन में बनी फिल्म रामइया वस्तावइया की पटकथा कुछ नई नहीं है, लेकिन इस फिल्म को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया.

रोमांटिक और कॉमेडी फिल्मों ने मारी बाजी

आशिकी 2 और ये जवानी है दीवानी की जबर्दस्त सफलता के बाद लगातार तीसरे महीने में रोमांटिक फिल्मों का जादू बॉलीवुड के सिर चढ़कर बोला. रांझना में कोलावरी डी फेम धनुष और सोनम कपूर के रोमांस को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. यह फिल्म अब तक 60 करोड़ बटोर चुकी है. वहीं नई स्टार कास्ट के साथ बनीं एक्सपेरिमेंट फिल्म फुकरे भी दर्शकों को खूब पसंद आई. करीब 7 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म 33 करोड़ कमाने के बाद भी कई थिएटरों में जमी है. वहीं, विद्या बालन और इमरान हाशमी की फिल्म घनचक्कर को बहुत ही ठंडा रेस्पॉन्स मिला, जबकि भाग मिल्खा भाग तेजी से दौड़ रही है. वहीं रामइया वस्तावइया भी धीरे-धीरे ही सही, लेकिन दर्शकों को पसंद आ रही है. सुपरहिट ये जवानी है दीवानी और आशिकी2 के अलावा कुछ और फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुईं, वे हैं रेस2, स्पेशल 26, काई पो चे, साहिब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स, रांझना, फुकरे सेमी हिट जिला गाजियाबाद , एबीसीडी, चश्मेबद्दूर, शूट आउट ऐट वडाला, मेरे डैड की मारुति.

कुछ फिल्में, जो उम्मीद के विपरीत बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी. उन्में थमटरू की बिजली का मंडोला, हिम्मतवाला, यमला पगला दीवाना2, जयंती भाई की लव स्टोरी, इश्क इन पेरिस, एक थी डायन.■

सोप ओपेरा से विश्व सिनेमा का सफर

32 वा फिल्म निर्देशक आंनद गांधी को हिंदी सिनेमा में नई लहर की तरह देखा जा रहा है. शेखर कपूर ने इसे अब तक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड फिल्म करार देते हुए कहा कि यह फिल्म बॉलीवुड को विश्व सिनेमा में एक अलग पहचान दिलाएगी. चर्चित फिल्म निर्देशक दीपा मेहता और अनुराग कश्यप ने भी इसे बेहतरीन फिल्म करार दिया है. फिल्म के निर्देशक 32 साल के आंनद गांधी कहते हैं कि मेरे लिए शिप ऑफ थीसस एक खोज की तरह है. इसकी हर कहानी सवालों से जुड़कर बनी है. सिनेमा में सवाल का होना बेहद महत्वपूर्ण है. यह अलग तरह की सिनेमा को दर्शकों तक पहुंचाने की इच्छा का परिणाम है. सिनेमा के दर्शकों के लिए यह एक ऐसी फिल्म है, जिसमें केवल कहानी ही आगे नहीं बढ़ती, बल्कि इसमें जिंदगी के अहम सवालों के जवाब भी टटोलने की कोशिश की गई है. मुझे लगता है कि इसकी पटकथा, सिनेमैटोग्राफी और कलाकारों का शानदार अभिनय दर्शकों को पसंद आएगा. आनंद मात्र 19 साल की उम्र में क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर-घर की, जैसे धारावाहिकों के स्क्रिप्ट लिखकर चर्चा में आ चुके हैं, लेकिन अब बड़े पर्दे पर वह शिप ऑफ थीसस जैसी गंभीर और दार्शनिक फिल्म के साथ आ रहे हैं. वह कहते हैं कि मात्र 13 साल की उम्र से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई थी. मैंने कुछ ऐसे नाटक भी लिखे, जो प्रश्नों और विचारों के साथ अपनी कहानियां कहते थे. इसके बाद 17 साल की उम्र में हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों के साथ ही श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकारों की फिल्में भी देखीं. ये नितांत नये तरह के सिनेमाई दर्शन की बात करती थीं. इन सबके बीच 1997 में ईरानी और फ्रेंच फिल्मों को देखना मेरे लिए एकदम नया अनुभव था. यहीं से मेरे भीतर कुछ बदलाव आया, जिसने मुझे सिखाया कि इस प्रकार का एक सिनेमा भी संभव है, जिसमें मनोरंजन के साथ विचार भी हों.■

टैटू को स्प्रिचुअल टच देंगे प्रतीक

किसी के प्यार में उसके नाम की टैटू बनवाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन किसी के नाम का टैटू बनवाना कितना भारी पड़ सकता है, अब यह बात दीपिका पादुकोण के बाद प्रतीक बब्बर भी समझ गए होंगे. दरअसल, एक दीवाना था की शूटिंग के दौरान वह ब्रिटिश ऐक्ट्रेस ऐमी जैकसन पर इस कदर फिदा हुए कि उन्होंने अपनी बाजू पर मेरा प्यार मेरी ऐमी बनवा लिया. तब ऐमी पर भी इस प्यार का खुमार था और उन्होंने भी मेरा प्यार मेरा प्रतीक टैटू बनवाया था, लेकिन फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया और प्यार की यह कहानी यहीं खत्म हो गई.अब यह टैटू उन्हें खासा परेशान कर रहा है. पहले प्रतीक ने इसे हटवाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर इस प्रोसेस में होने वाली तकलीफ को सोचकर रुक गए. बहरहाल, अब उन्होंने इसका तरीका खोज लिया है. प्रतीक अपने इस टैटू डिजाइन को थोड़ा चेंज करवाकर इसे स्प्रिचुअल टच दे रहे हैं. प्रतीक ने बताया कि मैं अपने इस टैटू को नया लुक दूंगा. यह स्प्रिचुअल होगा और इसमें भगवान से मेरे रिलेशनशिप की झलक मिलेगी. तो क्या अब वह प्यार-व्यार वाली फीलिंग से बाहर निकल आए हैं? इस पर उनका कहना है कि उन्हें कभी किसी रिलेशन में होने का दुख नहीं है और यह जिंदगी का जरूरी हिस्सा है. हालांकि अब वह किसी को लाइफ में लाने का एफर्ट नहीं करेंगे. वह कहते हैं कि जिससे भी रिश्ता बनना होगा, वक्त के साथ खुद ही बन जाएगा.■

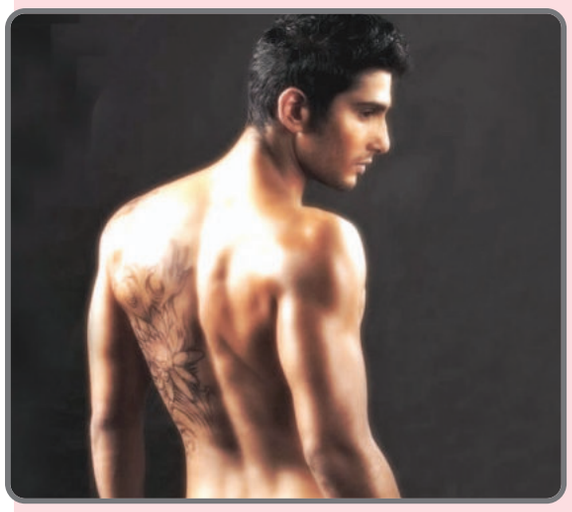

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

05 अगस्त–11 अगस्त 2013

बिहार–झारखंड

प्रिमियम ऑफिसेस एक सर्वोत्तम उच्च स्तरीय सुसज्जित ऑफिस

- बेहतरीन लोकेशन पर तैयार और फर्निश्ड ऑफिस स्पेस
- कर्मचारियों तथा आगंतुकों के लिए सीधी पहुंच
- कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, ईट आउट जोन के साथ रिटेल स्पेस
- बेहतरीन लोकेशन पर होने की वजह से बेहतर रिटर्न
- 24 घंटे जलापूर्ति, दोहरा बेसमेन्ट, कार पार्किंग स्पेस
- आगन्तुकों एवं सर्विस के लिए अलग लिफ्ट की व्यवस्था
- एयर कंडीशनर्स
- इंटेल कोर प्रोसेसर युक्त लैपटॉप
- स्टाफ के लिए खास डिजाइन की गई कुर्सियां
- वाल पेन्टिंग्स
- स्पेस के उत्तम उपयोग के लिए कार्यकुशल ऑफिस स्पेस तथा हाई फ्लोर-टू फ्लोर क्लीयरेंस के साथ प्रीमियम डिजाइन

Earth Infrastructures Ltd.
EARTH INFRASTRUCTURES LTD. innovation beyond imagination

4th Floor, Bhagwati Dwarika Acrade
Exhibition Road, Patna - 800001

Ph : 8084889203, 0612-6500643

राजगीर

उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश हटाओ प्लान

नालंदा जिला के राजगीर के कन्वेंशन हॉल में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तीन दिवसीय चिंतन सह प्रशिक्षण शिविर में नीतीश कुमार की सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया...

सुनील सौरभ

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तीन दिवसीय शिविर में समता पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के निशाने पर नीतीश सरकार के सरकारी महकमे में फैला भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा रहा. शिविर में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेताओं ने कहा कि नीतीश सरकार आज भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी हुई है और सरकार का पूरा महकमा भी भ्रष्टाचार में लिप्त है. पटना का 1 अणे मार्ग इस भ्रष्टाचार तथा लूट तंत्र का संचालन केंद्र बना हुआ है. नेताओं ने कहा कि नीतीश सरकार सभी मोर्चे पर विफल है. चाहे वह किसानों की हित की बात हो या बेरोजगारी की समस्या. त्रिदिवसीय कार्यकर्ता शिविर के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमने बिहार में संघर्ष कर राजा तो बदल डाला, लेकिन पुराना राज अब तक नहीं बदला है. आज हम पुन: पुराने चौराहे पर खड़े हैं. जिस सपने के साथ हम आगे चले थे, वे सपने साकार नहीं हो सके. उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में किसानों को कुछ भी हासिल नहीं हो सका. न तो उन्हें किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई और न ही खाद-बीज ही उपलब्ध कराया गया. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने किसानों के हितों की दिशा में काम करने का निर्णय लिया है और जय जवान, जय किसान का नारा दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार में आज भय पैदा करके लोगों की आवाजों को दबाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे और लक्ष्य को लेकर अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे. कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी और यह मूल रूप से कार्यकर्ताओं की पार्टी होगी, जिसमें कार्यकर्ताओं की बात को सुन कर ही नीतिगत फैसले लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी आगे की जो भी रणनीति बनाएगी, उसमें कार्यकर्ताओं की इच्छा का पूरा ख्याल रखा जाएगा. उन्होंने शिविर में कहा कि नीतीश अल्पसंख्यकों के हितैषी होने की बात करते हैं, लेकिन उनके हित की बात नहीं करते. आज तक फारबिसगंज गोलीकांड की जांच रिपोर्ट नहीं आ सकी. इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होता है. इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब रेलमंत्री थे, तब उन्होंने रेलवे में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की थी, लेकिन जब वह मुख्यमंत्री बने, तो शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए डिग्री लाओ, नौकरी पाओ के तर्ज पर काम किया. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि राज्य आज खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है. मिड-डे मिल में छिपकली मरी हुई मिली, घटिया भोजन की बात तो पहले भी सामने आती रही है. मिड-डे मिल के नाम पर मौत परोसा जा रहा है. सरकार के मंत्री गलती मानने की बजाय राजनीति करने में व्यस्त हैं. बिहार के गरीबों के साथ यह क्रूर मजाक है. उन्होंने कहा कि हमने राजनीति को संवेदनशील बनाने का निर्णय लिया है. महज कुर्सी के लिए राजनीति न हो, बल्कि हमें मिली अमानत को भी व्यवस्थित करना है. सम्मेलन के अंतिम दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सुशासन के तमाम विकास के आंकड़ों को कागजी और झूठ का पुलिंदा करार दिया. उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा, शिक्षक छात्र का भविष्य अंधकारमय है. बिहार में व्यापारी एक बार फिर धमकी, फिरौती और लूट से परेशान हैं. उद्योग और निवेश के नाम पर सरकार बिहार की जनता को ठग रही है. किसान और कृषि बदहाल है. स्वास्थ्य क्षेत्र के दावे फर्जी हैं. ऐसी स्थिति में बिहार की निरंकुश, बर्बर, हिंसक और अराजक सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है. उन्होंने छपरा में हुए मिड-डे मील की घटना पर दु:ख व्यक्त करते हुए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया और श्वेत पत्र जारी करने की मांग की. इस घटना के विरोध में आगामी 24 जुलाई को हर जिला मुख्यालय पर धरना देने का भी निर्णय लिया गया. प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के राज में बिहार में भ्रष्टाचार का बोल-बाला चरम पर है.

– शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

दल तोड़ने का मंत्र

लगता है बिहार के नेताओं ने दल तोड़ने का मंत्र हासिल कर लिया है. अगर यह सच भी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक जमीनी राजनीतिक समीकरण नहीं बदलते, तब तक कोई भी मंत्र काम नहीं कर सकता. तब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए किया जा रहा है.

सरोज सिंह

बिहार में लगता है इन दिनों हर दल के कुछ नेताओं ने दल तोड़ने का मंत्र हासिल कर लिया है. कोई दूसरे दल का पचास विधायक तोड़ रहा है, तो कोई पच्चीस, कोई दस, तो कोई पांच. मतलब जो मन में आ रहा है, बोल देना है, कोई रोक-टोक नहीं है. अब इन दावों की सच्चाई कौन परखने बैठा है, क्योंकि हवा में किए गए दावे से बस सनसनी फैलाई जा सकती है. जमीन के राजनीतिक समीकरण नहीं बदले जा सकते. इसलिए हर दल यह मान कर बैठा है कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही होगा या फिर इस प्रकिया के दौरान होगा, लेकिन यह तय है कि बिहार की राजनीति को इस दौर से गुजरना है, लेकिन सच तो यह है कि इसके लिए उचित राजनीतिक परिस्थितियां जिम्मेदार होगी, न कि दल तोड़ने का मंत्र. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस तरह के दावों के पीछे बस दबाव बनाने की राजनीति और अपने विधायकों और नेताओं को एकजुट रखने की कवायद है. भाजपा और जदयू का गठबंधन टूटने के बाद विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी जातीय ताना-बाना भी टूट गया है. पिछले 17 सालों की दोस्ती ने बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के लिए एक जातीय ताना-बाना बुन दिया था. यह ऐसा ताना-बाना था, जिसमें ज्यादातर उम्मीदवार अपनी जीत का चेहरा चुनाव के पहले ही देख लेते थे, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद तो यह जातीय तानाबाना ही टूट गया. अब सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जातीय समीकरणों की नये सिरे से समीक्षा में जुट गए हैं. यही समीक्षा विधायकों के पाला बदल का आधार बन रहा है. जदयू के आधार जातीय वोट अगर किसी उम्मीदवार को जीत के रास्ते पर जाने की गारंटी दे रहा है, तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र में अगर भाजपा का उम्मीदवार अभी जीता है, तो उसका मन डोलने लगा है. ठीक वही स्थिति भाजपा के आधार जातीय वोट वाले विधानसभा क्षेत्रों में है. अगर जदयू के किसी विधायक को लग रहा है कि भाजपा का आधार वोट बैंक उसकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो स्वाभाविक है वह भाजपा में जाने से नहीं हिचकेगा. इसलिए यह समय भाजपा व जदयू के विधायकों के लिए चुनावी समीकरण की समीक्षा का है. दल तोड़ने का मंत्र इसलिए कुछ नेताओं द्वारा फुंका जा रहा है कि इस तरह की समीक्षा की प्रकिया धीमी हो और विधायक भ्रम की स्थिति में रहें. उन्हें यह अहसास हो कि हवा उनके दल के पक्ष में ही चल रही है, इसलिए दूसरे दल के विधायक उनके पाले में आ रहे हैं. हां, इसमें दो मत नहीं है कि बिहार में अभी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है. विधानसभा सत्र के बाद राजनीतिक उठा-पटक का एक और दौर शुरू होगा.

भाजपा चाहती है कि सरकार की कमियों को जोर-शोर से जनता के बीच ले जाया जाए और इस सरकार का चेहरा और गंदा किया जाए. भाजपा सर्तक है, पर सरकार को गिराने के किसी भी अभियान में वह शामिल नहीं है. भाजपा नीतीश सरकार को मुद्दों के आधार पर बदनाम करना चाहती है. पार्टी नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत के लिए हुंकार रैली को ऐतिहासिक बनाना चाहती है. भाजपा अपनी पूरी ताकत इन्हीं दो मुद्दों पर लगा रही है. जहां तक जदयू का सवाल है, वह बाहरी व आंतरिक दोनों ही तरह की चुनौतियों से जुझ रही है. मीड डे मिल पर शरद यादव के बयान से साफ हो गया है कि पार्टी में शीर्ष स्तर पर कहीं न कहीं एकतरफा है. शिवानंद तिवारी की उपेक्षा भी अच्छा संकेत नहीं दे रही है. इसके अलावा, नीतीश कुमार पर मंत्रिमंडल विस्तार और मनोनयन कोटे की सीटें भरने का जबरदस्त दबाव है. पार्टी नेता और विधायक इंतजार खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. नीतीश कुमार किसे चुनते हैं, इस पर पक्ष व विपक्ष दोनों की नजर है. सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से राजद ने राहत की सांस ली है. राजद को लग रहा है कि भाजपा व जदयू की लड़ाई में आखिरकार फायदा उसे ही होने जा रहा है. राजद की सोच है कि माहौल सरकार के खिलाफ है, अगर सही उम्मीदवारों का चयन हो गया और चुनाव प्रचार सलीके से चला, तो लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहेगा. राजद सांसद रामकृपाल यादव कहते हैं कि दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा होता ही है. बिहार की जनता जदयू व भाजपा की नूराकुश्ती में फंसने वाली नहीं है और इस बार राजद को पूरी ताकत के साथ दिल्ली भेजेगी. उन्होंने पार्टी में किसी तरह की टूट से भी साफ इंकार किया. देखा जाए, तो भाजपा जदयू और राजद जैसे तीनों बड़े दल, दल तोड़ने संबंधी बयान देकर बस वाटर टेस्ट कर रहे हैं. असलियत में जो होना है, उसमें अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन कुछ इधर उधर होना है, यह तो तय ही है.■

अगर जदयू के किसी विधायक को लग रहा है कि भाजपा का आधार वोट बैंक, उसकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो स्वाभाविक है कि वह भाजपा में जाने से नहीं हिचकेगा. इसलिए यह समय भाजपा व जदयू के विधायकों के लिए चुनावी समीकरण की समीक्षा का है.

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

» एक नज़र «

रामाश्रय बने महासचिव

बिहार प्रदेश जदयू किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं पूर्व परिवहन मंत्री आरएन सिंह ने गया जिले के वरिष्ठ जदयू नेता रामाश्रय शर्मा को जदयू किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव तथा गया जिला का प्रभारी नियुक्त किया है. जिले के परैया प्रखंड के सरवदीपुर निवासी रामाश्रय शर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई है कि किसानों के हित में कार्य करते हुए जल्द ही जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय कमेटी का गठन करें. प्रदेश अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की है कि शर्मा के उक्त पद पर मनोनयन से किसान प्रकोष्ठ मजबूत और धारदार होगा. शर्मा के प्रदेश महासचिव बनने पर प्रो. अश्विनी कुमार समेत अनेक लोगों ने बधाई देते हुए हर्ष व्यक्त किया है और कहा है कि इससे किसानों के हित की बात सुनी जाएगी.

– *सुनील सौरभ*

मोतियाबिंद ऑपरेशन का लक्ष्य

मोतियाबिंद ऑपरेशन 2009 में खगड़िया जिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है. राष्ट्रीय अंधापन निवारण योजना के तहत खगड़िया जिला को पुरस्कृत किया गया है. शहीद प्रभुनारायण अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विवेकानंद ने बताया कि बीच के कालखंड में जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आवश्यक सहयोग नहीं मिलने के कारण यह रिकॉर्ड कायम नहीं रह सका, लेकिन वर्तमान सिविल सर्जन ने यह लक्ष्य निर्धारित किया कि वर्ष 2013–14 में एक बार फिर राज्य में मोतियाबिंद का नि:शुल्क ऑपरेशन कर खगड़िया जिला पुन: प्रथम स्थान प्राप्त करने जा रहा है. सिविल सर्जन एवं अस्पताल प्रबंधक की बैठक के बाद सिविल सर्जन कार्यालय से एक आदेश जारी कर यथाशीघ्र कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है.

छात्र समागम की बैठक

छात्र समागम का स्थापना समारोह 11 अगस्त को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया जाएगा. उक्त बातें छात्र जदयू के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार ने बैठक के दौरान कही. वहीं छात्र समागम के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रंजन कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद संगठन का विधिवत नाम बदल गया है. छात्र जदयू 5 जुलाई से ही छात्र समागम के नाम से जाना जा रहा है. उन्होंने कहा कि छात्र समागम में छात्र–छात्रा के अलावा शिक्षक, शिक्षेत्तर कर्मचारी एवं शिक्षाविद् को भी सदस्य बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह समाजवादी विचारों पर आधारित धर्मनिरपेक्ष संगठन के रूप में काम करेगा तथा समता मूलक समाज और मानव गरिमा के स्थापना के लिए कृतसंकल्प रहेगा. सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया. इस अवसर पर पवन पटेल, पंकज कुमार सिंह, मनोज कुमार, नवीन कुमार एवं उमाकांत सिंह सहित दर्जनों छात्र नेता उपस्थित थे.

मुखिया संघ की बैठक

पंचायत के विभिन्न समस्याओं एवं निदान को लेकर खगड़िया जिला मुखिया संघ की बैठक रेडक्रॉस भवन में संघ के अध्यक्ष सह अमनी पंचायत के मुखिया प्रमोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं एपीएल, बीपीएल, इंदिरा आवास, सड़क योजना एवं मनरेगा समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर व्यापक रूप से चर्चा की गई. बैठक में प्रदेश मुखिया संघ के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष सह चैता पंचायत मोतीहारी के मुखिया का निधन एवं मध्याह्न भोजन खाने से हुए 23 बच्चों की मौत पर शोक व्यक्त किया गया. इस अवसर पर परबत्ता प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत के मुखिया राम बालक सिंह, बंदेहरा के संजीव कुमार, राजकिशोर यादव, मनोज कुमार, पार्वती देवी एवं दुर्गा देवी समेत दर्जनों मुखिया उपस्थित थे.

सरकारी भवन पर कब्जा

सरकारी भवन पर अनधिकृत कब्जा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जल्द निर्माणाधीन सामुदायिक भवन को खाली नहीं किया गया, तो प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा. उक्त बातें सदर बीडीओ सुनील कुमार ने रहीमपुर मध्य पंचायत के दुर्गापुर शर्मा टोला में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन में अवैध रूप से शिवलिंग की स्थापना किए जाने पर कही. उन्होंने कहा कि सरकारी भवन को मंदिर का रूप देना सहन नहीं किया जाएगा. ज्ञात हो कि दलित युवा संग्राम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व समाजसेवी राकेश पासवान शास्त्री ने बीते दिनों आवेदन देकर डीएम से समुदायिक भवन को खाली कराने तथा यथाशीघ्र भवन को पूर्ण कराने की मांग की थी. जिलाधिकारी ने आवेदन पर कार्रवाई करते हुए सदर बीडीओ सुनील कुमार को जांच का जिम्मा सौंपा था.

– *नंदकिशोर शर्मा*

चंपारण मिड-डे-मील

राजनीतिक घमासान तेज

इंतखाब हक

पिछले दिनों मिड-डे-मील खाकर बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी. सभी दलों का कहना है कि नीतीश सरकार इस घटना के लिए सीधे जिम्मेदार है. लापरवाही के कारण ही बच्चों की जानें गईं. इस घटना के कारण नीतीश सरकार इन दिनों सभी दलों के निशाने पर आ गई है.

सारण जिला के मशरख प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय में बीते दिनों मिड-डे-मील खाने से हुई छात्रों की मौत पर चंपारण में राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है. [illegible]

... कर रही है. हाल ही में समाहरणालय के सामने आयोजित राजद का धरना इसका ताजा उदाहरण है. धरना में मौजूद राजद जिलाध्यक्ष बच्चा प्रसाद यादव, पूर्व विधायक हरिशंकर यादव, लक्ष्मी [illegible]

... चंपारण में राजीतिक घमासान तेज हो गई है और सभी दलों के नेता सुशासन बाबू नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगलने लगे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

विधायक के आगे एसपी लाचार

प्रमोद प्रभाकर

समस्तीपुर जिले के मोरवा के जदयू विधायक बैद्यनाथ सहनी की दबंगई के कारण पुलिस अधीक्षक भी उनके सामने बौने नजर आ रहे हैं. यहां विधायक जी का राज चलता है, अधिकारियों की पोस्टिंग तक विधायक जी इशारे पर होता है.

अशोक कुमार गुप्ता

बैद्यनाथ सहनी

एसपी बरुण कुमार

आमतौर पर नीतीश सरकार के बारे में कहा जाता है कि [illegible]

... नीतीश कुमार के पास पहुंच चुकी है. इसके पूर्व मोरवा विधान सभा क्षेत्र में नकली शराब और नकली रुपये के कारोबारी को पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया. इस पर विधायक बैद्यनाथ साहनी एवं उनके आदमियों ने सड़क जाम कर एसपी पर दबाव बनाकर कई थाना प्रभारियों को हटा दिया. अब मोरवा विधान [illegible]

... है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई गलत काम होगा, तो मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते जरूर विरोध करूंगा. बंगरा में गलत आदमी को भेज दिया गया था, तो मैंने विरोध किया. साहनी का कहना है कि जनता की सेवा मेरा पहला धर्म है. मैं केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूं. इस काम से अगर किसी को परेशानी हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूं. वैसे मैं साफ कर दूं कि अपने क्षेत्र में मैं न तो कोई गलत काम करता हूं और न किसी को ऐसा करने की इजाजत दे सकता हूं. गलत लोगों के खिलाफ और गलत फैसलों के खिलाफ मैं आवाज उठाता रहूंगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

इंदिरा आवास योजना में दलाली

केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना की राशि को 45000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दी है, जिसमें केंद्र सरकार 75 प्रतिशत और राज्य सरकार 25 प्रतिशत रकम देती है. सवाल यह है कि आखिर सरकार द्वारा गरीबों के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का हुआ क्या? जानकारों का कहना है कि निष्पक्षता से अगर इस योजना की जांच हुई, तो अनेक घोटाले उजागर होंगे.

अवधेश कुमार शर्मा

पश्चिम चंपारण जिले में इंदिरा आवास योजना लूट की योजना बनकर रह गई है. इस योजना पर पूरी तरह से दलालों और प्रखंड के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों का कब्जा है. एक तरफ दलाल जहां पंचायतों में घूम-घूम कर लाभार्थियों से अवैध उगाही कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रखंडों में तैनात अधिकारी और कर्मचारी भी लाभार्थियों का शोषण करने में लगे हुए हैं. बीते पांच वर्षों में आवंटित राशि इसका ज्वलंत उदाहरण है. जानकार बताते हैं कि आवंटित राशि का सदुपयोग कर घर बनाने वाले लाभुकों की संख्या महज 10 प्रतिशत ही है, जबकि शेष 90 प्रतिशत लाभुकों को दी गई राशि का पता नहीं चल पाता. यह राशि अधिकारियों और दलालों के लिए दुधारु गाय साबित हो रही है. केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास की राशि को 45000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दी है, जिसमें केंद्र सरकार 75 प्रतिशत और राज्य सरकार 25 प्रतिशत रकम देती है. यहां के लोगों का सवाल है कि आखिर सरकार द्वारा गरीबों के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का हुआ क्या? जानकारों का कहना है कि निष्पक्षता से अगर इस योजना की जांच हुई, तो अनेक घोटाले उजागर होंगे. एपीएल–बीपीएल सूची में सुधार न होने के कारण वास्तविक लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है. प्राय: सभी प्रखंडों की स्थिति यही है. लाभार्थियों का जमकर दोहन हो रहा है. हालांकि इसकी शिकायतें भी जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंच रही है, लेकिन जांच के नाम पर मामले उलझ कर रह जाते हैं. किसी पंचायत में पंचायत सचिव खुलेआम लाभार्थियों से रिश्वत की मांग कर रहे हैं, तो कहीं विकास मित्र भी लाभार्थियों को ठगने में लगे हुए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

शराब बिक्री में मनमानी

सीमांचल में नकली शराब के कारोबार का भांडाफोड़ होने लगा है. यहां मनमाने दाम पर शराब बेची जा रही है, लेकिन सिंडिकेट के दबाव के कारण कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है.

नीरज/ कुलभूषण

शराब व्यवसाय में पारदर्शिता लाने के लिए और शराब के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए जदयू और भाजपा की गठबंधन सरकार ने अपने प्रथम कार्यकाल में शराब दुकानों के आवंटन में लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई थी, ताकी राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और व्यक्तिगत रूप से दुकान का आवंटन भी हो सके, लेकिन नियमों में लचीले रुख के चलते एक बार पुन: शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं. सीमांचल में अवैध शराब के कई मामले सामने आए हैं. सीमांचल के चारों ज़िलों में अलग-अलग ढंग से सिंडेकेट शराब व्यवसाय का कब्जा है. सीमांचल के कटिहार, अररिया और किशनगंज ज़िले की तुलना में पूर्णिया में शराब की खपत सबसे अधिक है. पूर्णिया ज़िले में सरकार और प्रशासनिक महकमों के चलते शराब सिंडीकेट की मनमानी चलती है और सरकारी अधिकतम खुदरा मूल्य की तुलना में प्रति ब्रांड अधिक रुपये वसूले जाते हैं. पूर्णिया के मो. अजीम, राजेश जायसवाल प्रमोद, मो. शमीम बब्लू, आनंद राज, राकेश कुमार और चितरंजन यादव ने अधिकतम खुदरा मूल्य दिखाते हुए जानकारी दी कि नंबर वन निप्स का प्रिंट रेट 95है, जबकि ग्राहकों से 110 रुपये वसूला जाता है, नंबर वन प्लेटिना का प्रिंट रेट 110 है, और ग्राहकों से 120 रुपये लिया जाता है, रॉयल स्टेग का प्रिंट रेट 123 और 140 में बेचा जाता है. रॉयल चैलेंज का प्रिंट रेट 128 है, जबकि 140 में बेंचा जाता है, ब्लैंडर प्राईड का प्रिंट रेट 155 तो 180 में और सिग्नेचर का प्रिंट रेट 169 है, जबकि 190 में बेचा जाता है. इसके अलावा, हाफ और फुल शराब पर 30 से 50 रुपये तक अधिक वसूल किया जाता है. यहां के लोगों का कहना है कि पूर्णिया ज़िले में जितनी भी शराब के दुकान हैं, किसी पर भी अनुज्ञप्ति धारक का नाम नहीं लिखा गया है और न ही किसी भी दुकान पर दाम का लिस्ट चिपकाया गया है. पूर्णिया में प्रतिदिन नकली और अवैध शराब के मामले उजागर हो रहे हैं. जहरीली शराब से लोगों को स्वास्थ्य और जान का खतरा है.

मालूम हो कि पूर्णिया के बियाडा क्षेत्र में पिछले दिनों अवैध शराब के फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था और प्राय: बंगाल से आने वाले अवैध शराब का भंडाफोड़ भी होता रहता है. सात जुलाई को पूर्णिया सदर थाना प्रभारी महुज आलम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एएसआई उपेंद्र यादव ने दवा के कागजात पर बंगाल से आ रहे एक ही ब्रांड के एसार च्वाइस नामक अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा था, जिस पर 190 कार्टून में 180 एमएल एसार च्वाइस की कुल 9120 बोतलें थीं. थाना प्रभारी महुज आलम ने जानकारी दी की दवा का चालान जलपाईगुड़ी के एक केमिकल फैक्ट्री का था. इस मामले में ड्राइवर समेत स्थानीय तीन व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया. पूर्णिया पुलिस अधीक्षक किम शर्मा का कहना है कि इस शराब को पूर्णिया में ही खपाए जाने का मामला दिखाई देता है. वहीं ट्रक ड्राइवर नवीन सिंह का कहना था कि ट्रक पटना से सरकारी दवाइयां लेकर पूर्णिया आया और भाड़े के लिए गुलाब बाग ज़ीरो माईल में था. तभी नसीम नामक ट्रांसपोर्टर ने भाड़े का सौदा तय कराया. किशनगंज ज़िला शराब के मामले में सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि इसका अधिकतर भू-भाग बंगाल से सटा हुआ है और पांजीपाड़ा एवं दालकोला अवैध शराब के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है. किशनगंज के गयालाल, महादेव रिजाबुल, मो. सिकंदर आदि का कहना है कि असली शराब की कोई गारंटी नहीं है. किसी भी दुकान पर प्राइस लिस्ट लटका नहीं रहता है. यहां बंगाल निर्मित नकली ब्रांड का शराब भी खूब बिकता है. अररिया में भी शराब रिटेल प्राईस से महंगे में बिकता है. अधिकतर शराब अवैध दुकानदारों के द्वारा बेचा जाता है. कटिहार में विभिन्न शराब सिंडिकेट के कारण प्रतिस्पर्धा में शराब रिटेल प्राइस से नीचे में बिकता है. यहां के बलरामपुर और बारसोई आदि जगहों में बंगाल निर्मित अवैध शराब का प्रभाव ज़्यादा है. पूर्णिया के उत्पाद अधीक्षक भगवान राय का कहना है कि सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों को दाम की पर्ची लटकाने का निर्देश दिया गया है. अवैध शराब की सूचना मिलने पर फौरन कार्रवाई होती है. कुल मिलाकर सीमांचल में सरकार का नहीं, बल्कि सिंडिकेट का राज चलता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

» एक नज़र «

जदयू का विधानसभा सम्मेलन

प्रतिष्ठा से बड़ा काई पद नहीं होता है. 17 वर्ष पूर्व एनडीए गठबंधन के साथ जो समझौता हुआ था, उसमें भाजपा भटक गई. वर्षों से चली आ रही गठबंधन को तोड़ना पड़ा. उक्त बातें जेएनकेटी इंटर विद्यालय में आयोजित खगड़िया विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री श्याम रजक ने कही. विधायक पूनम देवी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चौतरफा विकास हुआ है. इसका मुख्य कारण मुख्यमंत्री की सकारात्मक सोच है. सम्मेलन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष साधना देवी एवं मंच का संचालन प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार ने की. इस अवसर पर अलौली विधायक रामचंद्र सदा, जिला प्रवक्ता अरविंद मोहन, कृष्णा देवी यादव, पूर्व विधायक रणवीर यादव, नईम अख्तर, प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी ललित चौधरी, उपाध्यक्ष बब्लू मंडल, राज कुमार फोगला, पूर्व मुखिया अशोक सिंह, गौतम कुमार, सुबोध पटेल, अरुण शर्मा, पुरुषोत्तम अग्रवाल, सोनेलाल मेहता समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे.

– *नंदकिशोर शर्मा*

रेडियो का वितरण

गोगरी प्रखंड कार्यालय परिसर में तीन दिवसीय शिविर लगाकर महादलित परिवारों के बीच 4583 रेडियो का वितरण किया गया. रेडियो वितरण के लिए पूर्व प्रखंड के 24 पंचायतों एवं 20 नगर पंचायतों के महादलित परिवारों के बीच कूपन का वितरण किया गया. बीडीओ नौशाद आलम ने बताया कि महादलित विकास मिशन योजना के तहत सभी महादलित परिवारों के बीच रेडियो का वितरण किया गया है. इस अवसर पर जीपीएस शिवराज मल्लिक, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सीताराम सिंह, बीएसओ अरविंद सिंह, सुरेश रजक, वीर प्रकाश रजक, प्रमोद रजक, भोला मंडल, ओम प्रकाश चौधरी, विनोद पासवान समेत दर्जनों महादलित उपस्थित थे.

– *उधव कुमार*

जनहित में है खाद्य सुरक्षा अध्यादेश

केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अध्यादेश की घोषणा पर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रसन्नता व्यक्त की है. सीतामढ़ी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विमल शुक्ला ने केंद्र सरकार के इस फैसले से आम–आवाम को अवगत कराने को लेकर बड़ा अभियान शुरू कर दिया है. इसके तहत शुक्ला ने जगह–जगह योजना से संबंधित जानकारी का कट आउट लगाने का काम शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि योजना के तहत अब देश के 120 करोड़ में से करीब 31 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा. महिलाओं को भी लाभ दिलाने का पर्याप्त प्रयास किया गया है. योजना का कार्यान्वयन कराने में कोताही अब किसी भी अधिकारी को महंगा पड़ सकता है. शुक्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र प्रायोजित योजना के प्रचार–प्रसार में लगने की अपील की है.

राजद का धरना

सारण के मशरख प्रखंड के एक स्कूल में पिछले दिनों मीड डे मील से हुई बच्चों की मौत को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिला राजद के तत्वावधान में आयोजित धरना की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मो. शफीक खां ने की. कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारा लगाकर रोष का इजहार किया. वक्ताओं ने घटना की जांच सीबीआई से कराने, मृतक के परिजनों को 10–10 लाख रुपये का मुआवजा देने के साथ कई और मांग की. कहा कि अब बिहार के मुख्यमंत्री को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. पार्टी का एक शिष्टमंडल अपर समाहर्ता को पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा. शिष्टमंडल में दिलीप कुमार यादव, चंद्रजीत प्रसाद यादव, गणेश गुप्ता, हरिओम शरण नारायण, शाहीन परवीन, शशिप्रभा, अजमत अंसारी व महेंद्र राम शामिल थे. कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सूर्यदेव राय, तारकेश्वर प्रसाद यादव, शिवशंकर यादव, नीलम यादव, सुरेंद्र प्रसाद यादव, सुनील यादव व राम नरेश मंडल समेत अन्य थे.

– *ब्रजेश*

भाजपा की बैठक

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत डॉ. जय विनोद गुप्ता के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई. मंडल अध्यक्ष युगल किशोर गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अहंकार गठबंधन वध के रूप में सामने आया है, जो आम–आवाम के साथ विश्वासघात है. बैठक में मध्या न भोजन से उपजे मामले पर कार्यकर्ताओं ने सीएम से इस्तीफे की मांग की. मौके पर निर्णय लिया गया कि जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में रुन्नीसैदपुर प्रखंड के सभी पंचायतों में दौरा किया जाएगा. बैठक में जिलाध्यक्ष मनोज कुमार, उपेंद्र शुक्ल, राधेश्याम सिंह, उमाशंकर सिंह, अमरेश कुमार सिंह, अंबुज कुमार, शशि रंजन, विकास शर्मा, मनोज कुमार, राम दिनेश प्रसाद, रंजन कुमार, सुधीर रंजन वर्मा, जितेंद्र कुमार समेत दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता थे.

– *विभा*

भाजपा–जदयू साथ रहे

ariskon Pharma Pvt.Ltd.

डॉ. मिथलेश प्रसाद

भाजपा–जदयू साथ रहे जाने माने चिकित्सक डॉ. मिथिलेश प्रसाद भाजपा व जदयू गठबंधन के टूटने को सही नहीं मानते। वह कहते हैं कि हमने सुना था कि भाई–भाई से अलग होता है लेकिन हमेशा सुनने में आया कि दोस्त कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। कभी एक दूसरे पर फब्तियां नहीं कसते। फिर आज यह क्या हो गया है कि हमेशा एक दूसरे पर मर मिटने वाले भाजपा–जदयू एक दूसरे की सत्ता गिराने में लगे हैं। एक दूसरे पर फब्तियां कसते नजर आ रहे हैं। दोनो मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने में लगे थे आज ये कैसे हो गया कि एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। बिहार की जनता ने दोनों को वोट दिया था। बिहार की जनता को दोनों पार्टियों से आशा थी फिर दोनों अलग कैसे हो गये।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुदा क्यों हो गये क्या उन्हें भाजपा से अलग होना चाहिए थाा क्या उन्होंने बिहार की जनता के दिल को दुखाया। हम और हमारे बिहार की जनता आग्रह करती है कि ये दो पार्टियां फिर से एक हो जाय।

ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol
Serratiopeplidase Tab.
ECTALOPAM
Escilalopram oxalate
& Clonazepam Tablets
SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

प्रस्तुति: शिवानी

उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश हटाओ प्लान

...पृष्ठ 17 का शेष...

पदाधिकारी से लेकर राजनेता तक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर गए हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बिहार में ही है. पार्टी के वरिष्ठ नेता रामबिहारी सिंह ने कहा कि अब यह काफिला ठहरने वाला नहीं है और राजगीर का संदेश पूरे बिहार में जाएगा, जो एक नया बिहार बनाने में सहायक होगा.

पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि आज पूरा बिहार उपेंद्र कुशवाहा और अरुण कुमार की तरफ देख रहा है. राजगीर में पार्टी ने जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए दल का एक–एक कार्यकर्ता अपना सब कुछ लगा देगा. अमरेंद्र सिंह ने कहा कि रालोसपा ही बिहार में अब एक मात्र विकल्प है, इसलिए बड़ी संख्या में नेता विधायक मंत्री और कार्यकर्ता रालोसपा की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं.

तीन दिवसीय सम्मेलन में गया शिक्षक क्षेत्र के विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह, शंकर झा आजाद, राजेश यादव, द्वारका प्रसाद दांगी, शंभू कुशवाहा, नूर हसन आजाद, सुमन पटेल, मनोज यादव, राजेश यादव, जयंती शुक्ला, यशोदा कुशवाहा, पंकज मालवीय, ओम प्रकाश कुमार, भरत प्रसाद सिंह, विद्यानंद राय, संजय वर्मा, सुजाता कुशवाहा, महेंद्र प्रसाद, अनोज यादव समेत पार्टी के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

रुन्नीसैदपुर को अनुमंडल बनाने की मांग तेज

सीतामढ़ी जिला के रुन्नीसैदपुर प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा देने की मांग एक बार फिर जोरों पर है. इससे पूर्व वर्ष 1994 में भी इसे अनुमंडल का दर्जा देने के लिए आंदोलन हुआ था...

विभा सिन्हा

रुन्नीसैदपुर को अनुमंडल बनाने के समर्थन में 5 अक्टूबर, 1994 को अभियान समिति के चार नेताओं ने आमरण अनशन किया था. तब राज्य सरकार के तत्कालीन मद्य निषेध मंत्री सूर्यदेव राय ने आंदोलनकारियों को आश्वासन की घूंटी पिलाकर अनशन समाप्त कराया था, लेकिन समय गुजरने के साथ ही आंदोलनकारी, मंत्री और सरकार तक इधर-उधर हो गए. नतीजतन रुन्नीसैदपुर को अनुमंडल का दर्जा दिलाने का सपना सपना ही रह गया, लेकिन अब एक बार फिर लोगों ने पुरानी मांग को नई धार देने का मन बनाया है. प्रखंड सह अंचल कार्यालय में धरना-प्रदर्शन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है. बताते चलें कि वर्ष 1952 में रुन्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र की विधिवत घोषणा कर दी गई थी. बतौर निर्दलीय प्रत्याशी महंत विवेकानंद गिरी को क्षेत्र का पहला प्रतिनिधि निर्वाचित होने का गौरव प्राप्त हुआ.

वर्ष 1958 में रुन्नीसैदपुर को प्रखंड का दर्जा देकर बतौर प्रखंड विकास पदाधिकारी एस परैशा की पदस्थापना कराई गई थी. वर्ष 1995 में पंचायत पुन: गठन के बाद प्रखंड अंतर्गत पंचायतों की संख्या बढ़ा कर 33 कर दी गई. 2010 की जनगणना के अनुसार, 26315.25 हेक्टेयर में फैले प्रखंड की कुल जनसंख्या 3 लाख, 71 हजार, 525 को पार कर चुकी है. सूबे में बड़े प्रखंडों की सूचि में दूसरे स्थान पर मौजूद रुन्नीसैदपुर प्रखंड में एक थाना और दो पुलिस शिविर के माध्यम से अपराध नियंत्रण की जा रही है. यहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा 5 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र भी कार्यरत हैं. हाल ही में विद्युत विभाग द्वारा प्रखंड मुख्यालय के आसपास के क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित कर उपभोक्ताओं से शहरी क्षेत्र का शुल्क लिया जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में रोष है. लोगों का कहना है कि अनुमंडल की दर्जा के बाद ही इस बिंदू पर विचार संभव है. प्रखंड पंचायत समिति सदस्य डॉली देवी ने विभागीय कार्रवाई को उपभोक्ताओं का शोषण करार दिया है. प्रखंड को विभाजित कर मानिक चौक और महिंदवारा को प्रखंड का दर्जा दिए जाने और रुन्नीसैदपुर को अनुमंडल की दर्जा की मांग पर पंचायत समिति सदस्य का कहना है कि पूर्व में कई बार मांग को पंचायत समिति से पारित कर सरकार को भेजी जा चुकी है. भाजपा अध्यक्ष युगल किशोर गुप्ता ने भी अनुमंडल की दर्जा की मांग को लेकर आंदोलन की घोषणा की है.

युवा राजद के प्रदेश महासचिव दिलीप राय ने रुन्नीसैदपुर प्रखंड को विभाजित कर दो नए प्रखंडों का सृजन किए जाने और अनुमंडल की दर्जा की मांग पर आंदोलन का संकल्प व्यक्त किया है. प्रखंड राजद अध्यक्ष सह जिला पार्षद संजीत कुमार छोटू को पिछले दिनों स्थानीय खादी भंडार परिसर में संपन्न बैठक में संघर्ष समिति का संयोजक बनाया गया. प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मणि भूषण कुमार, माकपा के अंचल सचिव देवेंद्र प्रसाद यादव, राकांपा के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला महासचिव मनोज कुमार गुप्ता, संगठन सचिव अर्जुन प्रसाद यादव, भाकपा के अंचल सचिव रामाशीष सिंह, लोजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव राजेंद्र प्रसाद साह, प्रखंड अध्यक्ष गंगा झा, युवा राजद के प्रदेश महासचिव दिलीप राय, श्यामनंदन किशोर, जिला पार्षद सुदामा देवी और दुर्गा देवी समेत कई लोगों ने आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया. रुन्नीसैदपुर को प्रखंड से अनुमंडल का दर्जा दिलाने को लेकर प्रस्तावित आंदोलन का परिणाम क्या होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस आंदोलन से स्थानीय राजनीति का तापमान जरूर बढ़ जाएगा. ■

रीना देवी, डॉली देवी, दिलीप राय

मणि भूषण कुमार, संजीत कुमार छोटू, युगल किशोर गुप्ता

feedback@chauthiduniya.com

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY शर्तें लागू।
Contact : 9386595926, 9334115955

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

05 अगस्त–11 अगस्त 2013

आरएमपी चिकित्सक मनोज रविदास की मौत भी मलेरिया से हो गई. कुछ समय पहले जेपी के सर्वोदय आश्रम सोखोदेवरा के अधिकांश कार्यकर्ता भी मलेरिया से पीड़ित थे. उस समय कौआकोल के आसपास के गांवों से लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन हो गया था.

इंटरव्यू

नीतीश ने मुसलमानों को ठगा : मंगल पांडेय

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. गठबंधन की सरकार में तो मौका नहीं मिला, लेकिन अब वह यह दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ मुसलमानों को सपने दिखाने का काम कर रहे हैं. अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं में बेहतर तरीक़े से काम होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं. लोकसभा में भाजपा की बड़ी जीत की उम्मीद पाले मंगल पांडेय कहते हैं कि जनता जनादेश के साथ धोखा करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगी. पिछले दिनों चौथी दुनिया के वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह से उन्होंने बातचीत की. प्रस्तुत है कुछ ख़ास अंश...

■ **आप यह मानते हैं कि भाजपा और जनादेश के साथ धोखा हुआ है?**

जनता ने जंगलराज के खिलाफ और विकास के लिए जनादेश दिया था. सब ठीक चल रहा था, लेकिन किसी व्यक्ति की अति महत्वाकांक्षा ने सब चौपट कर दिया. जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है. भाजपा ने हर संभव कोशिश की कि विकास की गाड़ी पटरी से न उतरे, लेकिन नीतीश कुमार और शरद यादव ने एक नहीं सुनी. अब भाजपा इस विश्वासघात को जनता के बीच ले जा रही है और जनता से भाजपा को व्यापक समर्थन मिल रहा है.

■ **आपकी पार्टी खुद सत्ता में भागीदार थी, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि मुसलमानों को केवल नीतीश कुमार ने ठगा है!**

मैं यह कह रहा हूं कि मुसलमानों के कल्याण की योजनाओं का और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सकता था. इन योजनाओं से जुड़े विभाग भी जदयू के खाते में हैं. इसलिए भाजपा को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. भाजपा का तो बस यही कहना है कि झूठे सपने दिखाने का काम बंद होना चाहिए और सही नीयत व नीति से विकास का रास्ता खोलना चाहिए.

■ **गठबंधन टूटने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार बहुत कमजोर हो गई है और फैसले नहीं ले पा रही है.**

बिल्कुल सही बात है. यह भाजपा की ही ताकत थी कि इतने दिनों तक सरकार अच्छी तरह से चली और यह सूबा विकास

मंगल पांडेय

के रास्ते पर आगे बढ़ा, लेकिन जदयू के लोग केवल नीतीश कुमार का चेहरा आगे करते रहे. अब उन्हें खुद एहसास हो रहा है कि इस सरकार में भाजपा की कितनी वैल्यू थी. भाजपा के हटते ही सरकार का इकबाल खत्म हो गया है. कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है. बच्चे मर रहे हैं, अपराध चरम पर है और विकास के सारे काम ठप पड़ गए हैं. आखिर यह सरकार किस मुंह से जनता के बीच जाएगी.

■ **लोकसभा चुनाव के लिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है? क्या दूसरे दलों से गठबंधन भी करेंगे?**

भाजपा सूबे की सभी चालीस सीटों पर जीत हासिल करने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है. पार्टी के कार्यकर्ता जोश में हैं और विश्वासघात का बदला लेने के मूड में हैं. बूथ लेवल पर पार्टी सक्रिय है. हुंकार रैली को लेकर पूरे बिहार में जबरदस्त माहौल बनता जा रहा है. नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. जहां तक गठबंधन का सवाल है, तो भाजपा का स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए हम सभी का साथ लेंगे, पर यह भाजपा कार्यकर्ताओं के हक व सम्मान की कीमत पर नहीं होगा. कई दलों के विधायक और नेता भाजपा के संपर्क में हैं. समय आने पर नीतीश कुमार और जदयू को जबरदस्त पटकनी दी जाएगी.

■ **भाजपा में अंदरुनी खींचतान दिखती है. ऐसे में आप नीतीश सरकार को बेदखल कैसे करेंगे?**

भाजपा में कोई खींचतान नहीं है. पूरी पार्टी एकजुट है. हम बेहतर तालमेल और अचूक रणनीति के साथ कूद पड़े हैं. पूरे सूबे में नीतीश कुमार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है. जनता भाजपा को हाथों हाथ ले रही है. आगामी चुनाव में भाजपा यहां से रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेगी. आप देख ही रहे हैं कि भाजपा को रोकने के लिए हमारे विधायकों को मंत्री बनाने और पैसे तक का प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा सिद्धांतों वाली पार्टी है और इस तरह का लोभ–लालच भाजपाइयों को डिगा नहीं सकता है. ऐसे लोगों का भ्रम जल्द ही टूट जाएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

बदहाली का शिकार है गौशाला

करोड़ों की संपत्ति का मालिक होने के बाद भी चितरंजन दास गोशाला बदहाली का शिकार है. गौशाला के नाम पर कमेटी तो गठित की गई, लेकिन वह काम कर पाने में असमर्थ है. दूसरी ओर गौशाला की जमीन पर लोग कब्जा भी करने लगे हैं. मुख्यमंत्री दरबार में इसकी शिकायत की गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा.

मंगल पांडेयगोशाला में बंधी गाय

गोविंद कुमार

सीतामढ़ी ज़िले के पुपरी अनुमंडल मुख्यालय में आज़ादी से पूर्व गौशाला की स्थापना की गई, लेकिन सही रख–रखाव नहीं होने के कारण इसकी दशा दयनीय होने लगी है. तक़रीबन 22 एकड़, 42 डिसमिल ज़मीन पर स्थापित चितरंजन दास गौशाला करोड़ों की संपत्ति का मालिक होने के बाद भी आज बदहाली का शिकार है. इसका मुख्य कारण यह है कि जिस गौशाला के नाम पर कमिटी गठित की गई, वह काम कर पाने में अब तक असमर्थ साबित हुआ है. गौरतलब है कि इस गौशाला की क़ीमती ज़मीन पर कुछ लोगों की निगाह है. आश्चर्य की बात तो यह है कि यज्ञ के बहाने गौशाला के क़रीब साढ़े तीन एकड़ ज़मीन पर एक बाबा ने कब्जा जमा लिया है. कब्जा को हटाने को लेकर कई बार मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी गुहार लगाई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. अंग्रेजी हुकूमत के समय ही स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास के नाम पर गौशाला की आधारशिला रखी गई. शुरुआती दिनों में लोग दान स्वरूप गौशाला में गाय और बछिया देते थे. नतीजतन गौशाला में पशुधन पर्याप्त हो गया, लेकिन समय गुज़रने के साथ ही उनकी स्थिति दयनीय होती गई. तक़रीबन ढ़ाई दशक से गौशाला में बतौर प्रबंधक कार्यरत नित्यानंद झा और नव गठित कमिटी के सचिव गोविंद केजरीवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्तमान में गौशाला में 29 पशु हैं, जबकि क़रीब दो दशक पूर्व तक इस गोशाला में पशुओं की संख्या पांच दर्जन से भी अधिक हुआ करती थी. प्रबंधक की मानें, तो गोशाला की भूमि का वार्षिक मालगुजारी 425 रुपये जमा किया जाता है और लगभग 7 एकड़ ज़मीन में धान और गेहूं समेत अन्य फसल उपजाई जाती है. प्रतिदिन होने वाले 21 लीटर दूध से क़रीब साढ़े छह सौ रुपये की आमदनी होती है. सचिव केजरीवाल के अनुसार, दो एकड़ ज़मीन रेफरल अस्पताल के नाम निबंधित करा लिया गया है. ऐसे में कुल मिलाकर साढ़े पांच एकड़ ज़मीन गोशाला से बेदख़ल हो गया है. ऐतिहासिक गोशाला के अस्तित्व रक्षा को लेकर अब लोगों में चर्चा जोर पकड़ने लगी है. यहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि समय रहते अगर इस गोशाला के विकास की दिशा में आवश्यक पहल नहीं की गई, तो प्राचीन गोशाला महज एक दिखावा बन कर रह जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

कौआकोल में मलेरिया का तांडव

सैकड़ों लोगों की हुई मौत

आजादी के दशकों बाद भी समुचित स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया है...

सुनील सौरभ

झारखंड के गिरिडीह और बिहार के जमुई जिले की सीमा से लगे नवादा जिले का अति पिछड़ा कौआकोल प्रखंड के करीब 40 गांव मलेरिया से आक्रांत हैं. प्रत्येक गांव में हर दूसरे परिवार में कोई न कोई व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है. सबसे बड़ी बात यह है कि मलेरिया से आक्रांत लोगों की संख्या दिन–पर–दिन बढ़ती ही जा रही है. घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे इन गांवों में स्वास्थ्य सेवा की कोई व्यवस्था नहीं है. गौरतलब है कि पिछले एक दशक में इन गांवों में मलेरिया से मरने वालों की संख्या दो सौ से अधिक हो चुकी है. 2006 में तो कौआकोल के इन गांवों में मलेरिया की स्थिति काफी भयावह हो गई थी. कौआकोल में मलेरिया की भयावहता का अंदाजा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौआकोल से मिले आंकड़ों से लगाया जा सकता है. जनवरी 2013 में पूरे प्रखंड में 59 मरीज मलेरिया के पाए गए थे. फरवरी में यह संख्या 101 हो गई. मार्च में 146, अप्रैल में 111, मई में 180 और जून 2013 में 294 मरीज मलेरिया के पाए गए. मलेरिया के इन मरीजों में दोनों तरह के पीवी तथा पीएफ के मरीज हैं. कहा जाए, तो इन दिनों कौआकोल में मलेरिया महामारी का रूप ले चुका है. बावजूद इसके, स्वास्थ्य विभाग की ओर से मलेरिया की रोक–थाम के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है.

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौआकोल में पिछले छह महीने से मलेरिया की दवा ही नहीं है. यह कहना गलत नहीं होगा कि कौआकोल का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही मलेरिया से पीड़ित है. यहां चिकित्सकों के स्वीकृत 19 पदों में से 16 पद खाली हैं. चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के सातों पद रिक्त हैं. नर्स के 24 स्वीकृत पदों में से 17 पदों पर ही लोग कार्यरत हैं. गौरतलब है कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फुलडीह, बरौन और बड़राजी भी आता है. इन केंद्रों पर बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं. यहां एंबुलेंस की सुविधा भी नहीं है. कौआकोल में एक रेफरल अस्पताल भी है, लेकिन इसमें लंबे समय से सीआरपीएफ के जवानों का कब्जा है. यहां पदस्थापित सभी चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी दूसरे स्थानों पर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं या घर बैठे वेतन उठा रहे हैं. क्षेत्र की मलेरिया जैसी बीमारी की गंभीर समस्या पर न तो स्वास्थ्य विभाग और न ही जिला प्रशासन का ध्यान है. गौरतलब है कि कुछ वर्ष पूर्व एक बस के खलासी की मौत मलेरिया से हो जाने के कारण नवादा से बसों का आना–जाना बंद हो गया था.

बड़ी बात तो यह है कि एक आरएमपी चिकित्सक मनोज रविदास की मौत भी मलेरिया से हो गई थी. जेपी के सर्वोदय आश्रम सोखोवरा के अधिकांश कार्यकर्ता भी तब मलेरिया से पीड़ित हो गए थे. तब कौआकोल के आस–पास के गांवों से लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन हो गया था. जमुई जिले की सीमा से लगे नवादा जिले के कौआकोल का अंतिम गांव है झिलार, जो आदिवासी बहुल है और जंगलों से घिरा है. मलेरिया की भयावहता का अंदाजा इसी एक गांव के पीड़ितों से लगाया जा सकता है. यहां के तालों किस्को (45 वर्ष), नीतीश हैम्ब्रम (2 वर्ष), सुनीता हैम्ब्रम (1 वर्ष), नन्हक सोरेन (55 वर्ष), ढीनी हैम्ब्रम (52 वर्ष), बड़की सोरेन (55 वर्ष), कर्मी टुड्डू (50 वर्ष) लंबे समय से मलेरिया से पीड़ित हैं. मलेरिया की जानकारी मिलने के बाद एक–दो बार ही इन लोगों को दवा मिल पाई है.

इस गांव में वर्षों से डीडीटी का छिड़काव नहीं हुआ है. गरीबी में जीवन बसर करने वाले इन आदिवासियों को इलाज के लिए 10 से 15 किलामीटर दूर प्रखंड मुख्यालय आना पड़ता है. यहां आने पर कभी चिकित्सक नहीं मिलते हैं, तो कभी दवा नहीं मिल पाती है. जंगल और पहाड़ों से आच्छादित कौआकोल प्रखंड का भोरमबाग, चोंगवा, महुडर, झिलार, बरौन, बाजितपुर, दुधपनियां, नेठला, मंझिला, रानी–गहर, झरनवां, फरकी पत्थर, दनियां, महुलिय टांड़ आदि दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग आज भी मलेरिया से आक्रांत हैं. बरसात का मौसम आते ही इन गांवों में मलेरिया पीड़ितों की संख्या बढ़ने लगती है. इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण और शिक्षा का अभाव होने के कारण ग्रामीण मलेरिया की बीमारी का इलाज भी झाड़–फुंक से कराने को विवश हैं. इस दौरान कई लोगों की मौत भी हो जाती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

05 अगस्त–11 अगस्त 2013

उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड

ख़ूनी सियासत के मोहरे

उत्तर प्रदेश की राजनीति रंगबाजी-दगाबाजी और दबंगई के कारण हमेशा सुर्खियों में रही है. हमारे माननीय, विरोधियों को निपटाने के लिए बुलेट तक का सहारा लेते रहे हैं. बलात्कार, डकैती, गैंगवार, ठेकों पर कब्जा, लूटपाट और विरोधियों को झूठे मुकदमों में फंसाने जैसे आपराधिक कृत्यों में उनका हाथ रहा है.

अजय कुमार

आजमगढ़ के कस्बा जीयनपुर में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू और उसके अंगरक्षक की पिछले दिनों हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद सूबे की सियासत एक बार फिर खून से नहा गई है. इस घटना ने पुराने जख्मों को भी ताजा कर दिया है. बसपा के पूर्व विधायक सर्वेश कुमार सिंह उर्फ सीपू की हत्या राजनीति में बढ़ते अपराध का हिस्सा है. सर्वेश पहले ऐसे नेता नहीं हैं, जिन्हें विरोधियों की गोली का शिकार होना पड़ा है. इससे पहले भी वर्चस्व की लड़ाई में करीब दो दर्जन माननीयों को जान से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन हत्यारों को उनके किए की सजा शायद ही कभी मिले. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट सियासत से अपराधीकरण दूर करना चाहता है, लेकिन हमारे नेताओं को अपराध और राजनीति की जुगलबंदी काफी रास आती है, इसीलिए वह इसे अपनी मूक सहमति देते रहते हैं.

प्रदेश की राजनीति का अपराध से पुराना नाता है. इसकी शुरुआत 1962 में कांग्रेस ने की थी. तब कांग्रेस की एक महिला नेत्री विद्यावती राठौर ने दस्यु मान सिंह के भाई तहसीलदार सिंह को जेल से पैरोल पर छुड़ाकर अपने चुनाव प्रचार अभियान में लगाया था. तहसीलदार को ठाकुरों को लुभाने के लिए आगे किया गया था. इसका फायदा महिला नेत्री को मिला. वह चुनाव जीत कर दोबारा मंत्री बन गईं. जहां तक बात खूनी जंग की है, तो आज से करीब चार दशक पूर्व वर्ष 1978 में पहली बार इसकी दस्तक सुनाई दी थी. तब विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए लखनऊ आ रहे कौड़ीराम क्षेत्र के विधायक रवींद्र सिंह को उनके विरोधियों ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर गोलियों से भून दिया था. इस हत्या ने बाद पूर्वांचल में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा. कई छात्र नेताओं ने अपना दबदबा कायम करने, छात्र राजनीति को चमकाने और विरोधियों को निपटाने के लिए दबंगों का सहारा लिया. जातीय आधार पर भी कई गैंग पनपे. खूनी जंग में अनेक निर्दोषों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी. 1988 में देवरिया में गौरी बाजार के विधायक रणजीत सिंह की हत्या कर दी गई. उसकी हत्या आपसी दुश्मनी और पट्टीदारी की लड़ाई का नतीजा थी. 1991 में गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्र के शारदा प्रसाद रावत भी रंजिश में गोलियों के शिकार हो गए. इसी दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधायक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या कर दी गई.

यह वह दौर था, जब अपराधियों ने सियासत में पांव जमा लिए थे और ठेके–पट्टे के लिए खून बहाया जा रहा था. पश्चिमी और पूर्वी यूपी के अपराधियों ने मिलकर सियासी गठजोड़ में अपनी साझेदारी निभाई. 1996 में गोरखपुर के मानीराम क्षेत्र के विधायक ओमप्रकाश पासवान पर बांसगांव में एक जनसभा के दौरान बम से हमला हुआ, जिसमें पासवान समेत दर्जनों लोग मारे गए. इस घटना के साल भर बाद ही बाहुबली और पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही की लखनऊ में हत्या कर दी गई. उधर, फर्रूखाबाद में वर्ष 1998 में पूर्व मंत्री व भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी का भी सियासी रंजिश में कत्ल कर दिया गया. सुल्तानपुर के उसौली से विधायक इंद्रभद्र सिंह भी अपराधियों की गोली का निशाना बने थे. इनमें कई हत्याओं की वजह सियासी रंजिश थी, लेकिन इसके पीछे जमीन का भी मसला छिपा हुआ था. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंत्री लक्ष्मीशंकर यादव की हत्या राजधानी में एक तत्कालीन मंत्री द्वारा जमीन हड़पने के लिए ही कराई गई. जुलाई 2001 में मिर्जापुर की सांसद फुलन देवी की हत्या, जून 2005 में पूर्व सांसद लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी की हत्या और नवंबर 2010 में मेरठ में पूर्व सांसद अमरपाल सिंह की हत्या ने भी यह साबित किया कि सियासत में अपराधियों की जड़ें काफी गहरी हैं. इलाहाबाद विधायक राजू पाल और गाजीपुर विधायक कृष्णानंद राय की हत्या ने सियासी आपराधिक गठजोड़ की नई कहानी लिखी. सहारनपुर में सरसांवा के विधायक निर्भयपाल शर्मा, राजधानी में विधायक मंजूर अहमद, मऊ में पूर्व विलायती राम कात्याल, गाजीपुर में सादात के पूर्व विधायक बीजू पटनायक, एमएलसी भगवान बख्श सिंह, इलाहाबाद में विधायक जवाहर सिंह यादव उर्फ जवाहर पंडित,

शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

खूनी राजनीति के शिकार माननीय

19.7.2013	सर्वेश सिंह उर्फ सीपू	पूर्व विधायक	आजमगढ़	सपा
4.07.2010	कपिलदेव यादव	पूर्व विधायक	मऊ	बसपा
12.12.2006	बीजू नटनायक	पूर्व विधायक	गाजीपुर	सपा
17.8.2006	रामदेव मिश्र	पूर्व विधायक	गोंडा	सपा
20.3.2006	मलखान सिंह यादव	पूर्व विधायक	अलीगढ़	सपा
7.01.2006	हरदेव रावत	पूर्व विधायक	बाराबंकी	सपा
19.6.2005	लक्ष्मीमणि त्रिपाठी	पूर्व एमपी	लखनऊ	सपा
29.11.2005	कृष्णानंद राय	विधायक	गाजीपुर	सपा
25.01.2005	राजूपाल	विधायक	इलाहाबाद	सपा
3.11.2004	अजीत सिंह	एमएलसी	उन्नाव	सपा
12.10.2001	संतोष शुक्ला	राज्यमंत्री	दर्जा कानपुर	भाजपा
6.3.2002	मंजूर अहमद	विधायक	लखनऊ	राष्ट्रपति शासन
6.7.2000	निर्भयपाल सिंह	विधायक	सहारनपुर	भाजपा
21.1.1999	इंद्रभद्र सिंह	विधायक	सुल्तानपुर	भाजपा
8.9.1999	भगवान बख्श सिंह	एमएलसी	लखनऊ	भाजपा
31.3.1997	वीरेंद्र प्रताप शाही	पूर्व विधायक	लखनऊ	बसपा
10.2.1997	बमदत्त द्विवेदी	विधायक	फर्रूखाबाद	राष्ट्रपति शासन
13.8.96	जवाहर सिंह यादव	विधायक	इलाहाबाद	राष्ट्रपति शासन
25.3.1996	ओमप्रकाश पासवान	विधायक	गोरखपुर	सपा
20.10.95	लक्ष्मीशंकर यादव	विधायक	लखनऊ	राष्ट्रपति शासन
3.3.1995	चंद्रशेखर सिंह	पूर्व एमपी	वाराणसी	सपा
11.6.1994	कैलाश प्रसाद	पूर्व विधायक	वाराणसी	सपा-बसपा
23.10.1994	सुरेंद्र प्रताप सिंह	पूर्व विधायक	गोंडा	सपा-बसपा
13.9.1992	महेंद्र सिंह भाटी	विधायक	गाजियाबाद	भाजपा
8.9.1991	शारदा प्रताप रावत,	पूर्व मंत्री	गोरखपुर	भाजपा
1988	रणजीत सिंह	विधायक	देवरिया	कांग्रेस
1978	रवीन्द्र प्रताप सिंह	विधायक	गोरखपुर	जनता पार्टी

इसके अतिरिक्त जुलाई 2001 में मिर्जापुर की सांसद फुलन देवी की हत्या, जून 2005 में पूर्व सांसद लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी की हत्या, नंवबर 2010 में मेरठ में पूर्व सांसद अमरपाल सिंह की हत्या ने भी कम खौफ नहीं पैदा किया.

करोड़पति माननीयों की भी संख्या नहीं है कम

सपा सरकार में आपराधिक प्रवृति के नेताओं को जगह मिली ही हुई है. करोड़पति विधायकों की संख्या भी कम नहीं है. नेशनल इलेक्शन वॉच के अनुसार, प्रदेश सरकार के 58 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 38 मंत्री करोडपति हैं. सबसे ज्यादा अमीर मंत्री कुंवर आनंद सिंह हैं. उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र में बताया है कि उनके पास 18 करोड़ 30 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति है. कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने अपने शपथ पत्र में बताया है कि उनके पास 14 करोड़ 79 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति है. राजा भइया के पास सात करोड़, नरेंद्र सिंह यादव के पास चार करोड़ और महबूब अली के पास चार करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति है. इसी प्रकार सबसे कम चल-अचल संपत्ति एमएलसी बलराम यादव के पास कुल 16 लाख रुपये की है. ऐसा बलराम यादव ने निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र में बताया है. जंतु उद्यान मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री शिवप्रताप यादव के पास 79 लाख, अरविंद कुमार सिंह के पास 71 लाख और नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान के पास एक करोड़ 94 लाख रुपये की चल अचल-संपत्ति है.

माननीय मांगे सुरक्षा

बसपा के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या के बाद माननीयों को अपनी सुरक्षा का डर सताने लगा है. यूपी के करीब डेढ़ सौ पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा संबंधी आवेदन शासन के पास विचाराधीन हैं. सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं को तो सुरक्षा आसानी से मुहैया हो जाती है, लेकिन अन्य दलों के माननीयों को कभी अदालत की आड़ में, तो अक्सर सियासी दांव-पेंच के चलते सरकारी सुरक्षा नहीं मिल पाती है. पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय जैसे कई विधायक हैं, जो विशेष श्रेणी की सुरक्षा के लिए अदालत तक हो आए हैं. गृह विभाग में सुरक्षा के लिए माननीय चक्कर लगा रहे हैं. कई विधायक अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऊपर तक सिफारिश करने में जुटे रहते हैं. कुछ माननीय प्राइवेट सिक्योरिटी के सहारे खुद को सुरक्षित करने के प्रयास में लगे हैं.

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

ख़ूनी सियासत के मोहरे

पृष्ठ 17 का शेष

इलाहाबाद में ही बारा के पूर्व विधायक रमाकांत मिश्र की हत्या यूपी के सियासी इतिहास का काला अध्याय है. पिछली सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हुआ जानलेवा हमला भी इसी ख़ूनी जंग की कड़ी थी. अस्सी के दशक में इटावा की राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई में मुलायम सिंह यादव और बलराम सिंह यादव के बीच कई बार ख़ूनी संघर्ष हुआ. बाद में जब दोनों एक हो गए, तो दर्शन सिंह और मुलायम के बीच जंग छिड़ी, कई लोग मारे भी गए. बसपा और सपा के उभार के बाद तो माफियाओं और राजनीति का पूरी तरह से घालमेल हो गया. दस्यु ददुआ की तो चौखट पर कई नेता जीत का आशीर्वाद लेने के लिए जाते रहते थे.

राजनीति और अपराध के गठजोड़ के आंकड़े बताते हैं कि राजनीति अपराधियों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करती है. यूपी में महिला उत्पीड़न के मामले में भी हमारे माननीय पीछे नहीं हैं. चार विधायक तो ऐसे हैं, जिन पर बलात्कार जैसे घिनौने अपराध का मुकदमा चल रहा है. यह खुलासा स्वयं इन विधायकों ने चुनाव आयोग को दिए गए अपने हलफनामे में किया है. इसके अलावा यूपी की विधानसभा में 22 विधायक ऐसे हैं, जिनके खिलाफ महिलाओं के प्रति हिंसा, यौन उत्पीड़न के मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं. विधानसभा चुनाव 2012 के दौरान उत्तर प्रदेश में ऐसे दस उम्मीदवार थे, जिनके खिलाफ बलात्कार जैसे संगीन आरोप थे. यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि पूर्ववर्ती सरकारों में राज्यमंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी और आनंद सेन महिला अपहरण और उनकी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. कई पूर्व विधायकों के खिलाफ भी महिलाओं को अगवा कर उनसे बलात्कार के मामले विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं.

महिला उत्पीड़न के आरोपियों को चुनाव में उम्मीदवार बनाने में किसी दल ने कभी परहेज नहीं किया. पूर्ववर्ती सरकार में चर्चित कविता चौधरी के अपहरण और उसकी हत्या के मामले में एक कैबिनेट और एक राज्यमंत्री को अपने पद से हटना पड़ा था. विधानसभा ही नहीं, लोकसभा में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जिन पर इस तरह के संगीन मामले दर्ज हैं. बसपा सरकार में दो राज्य मंत्रियों को महिला उत्पीड़न की घटनाओं में न सिर्फ पद से हटना पड़ा, बल्कि एक को जेल भी जाना पड़ा. पद से हटाने के साथ ही, दोनों को बसपा से बाहर कर दिया गया था. अन्य अपराधों की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार के 58 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 26 मंत्री अपराधी हैं. यह बात प्रदेश सरकार के उन्हीं मंत्रियों द्वारा नामांकन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र के आधार पर कही जा रही है. प्रदेश सरकार के 58 सदस्यीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के शपथ पत्र में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य मंत्री और नगीना विधानसभा से विधायक मनोज कुमार पारस पर बलात्कार का मामला दर्ज है. उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र में यह घोषणा खुद ही की है. अमरोहा से विधायक और प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री महबूब अली के ऊपर 15 अपराधिक मामले दर्ज हैं. इस समय सभी अपराधिक मामलों में महबूब अली पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है. इन पर अपहरण, डकैती और मर्डर जैसे कुल 15 मामले दर्ज हैं. इसके अलावा निर्दलीय विधायक और कुछ समय पूर्व तक अखिलेश मंत्रिमंडल में जेल मंत्री रहे कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया के ऊपर आठ अपराधिक मामले दर्ज हैं. रामनगर से विधायक और मंत्री अरविंद कुमार सिंह पर हत्या के प्रयास सहित तीन अपराधिक मामले चल रहे हैं. गोंडा से विधायक और मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह और देवबंद से विधायक और मंत्री राजेंद्र सिंह राणा पर तीन-तीन अपराधिक मामले दर्ज हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

भगवान शिव को प्रिय है सावन

सावन सभी को प्रिय है. आसमान में गरजते बादल, बारिश की बूंदे, कौंधती बिजली यही तो पहचान है सावन का. इस महीने की ख़ूबसूरती को लेकर काफ़ी साहित्य लिखे गए है. फिल्मों में ही भी सावन के गीत और सावन की अलमस्त महीने को ख़ूबसूरती के साथ दिखाया गया है. बारिश की बूंदों की रिमझिम फ़ुहारें और ताज़े हवा के झोंकों की मदमस्त कर देने वाली सिहरन जब बदन से टकरती है, तब मन झूमने लगता है. इंसान ही नहीं कुदरत की हर कायनात सावन का तहे दिल से स्वागत करती है.

हिंदू मान्यता के अनुसार यह महाधिदेव का प्रिय माह है. इस संबंध में पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो महादेव भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योगशक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था. अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया. पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रह कर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया. सावन में सोमवार का विशेष महत्व है. सोमवार हिमांशु यानी चंद्रमा का दिन माना जाता है. चन्द्रमा की पूजा भी स्वयं भगवान शिव को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा का निवास भगवान शिव का सिर ही है. सावन के महीने में भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है. पूजा की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ की जाती है. अभिषेक में महादेव को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगाजल, गन्ना रस आदि से स्नान कराया जाता है. अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, दूब, कुशा, कमल, नीलकमल, मदार, कनेर, राई, फुल आदि से शिव की पूजा की जाती है. इसके साथ की भोग के रूप में धतूरा और भांग महादेव को चढ़ाया जाता है. इसके अलवावा, गंगाजल से शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया जाता है. सावन का महीना विलास, प्रेम और उमंग का है. इसे प्राकृतिक और अध्यात्मिक दृष्टि से भी जाना जा सकता है. शिव के प्रणव मंत्र में नमः शिवाय का योग कर देने से वह महामंत्र बन जाता है. शिव निराकार व साकार दोनों है. महादेव का अभिषेक करने के पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने के बाद जब महादेव ने इस विष का पान किया तो वह मूर्च्छित हो गए. उनकी दशा देखकर सभी देवी-देवता भयभीत हो गए, उन्हें होश में लाने के लिए पास के प्रत्येक वस्तु से उन्हें स्नान कराने लगे. इसके बाद से ही उन्हें उन सारी चीजों से अभिषेक किया जाता है. भगवान शिव को बेलपत्र और समीपत्र भी चढ़ाया जाता है. पौराणिक कथा के अनुसार जब 89 हजार ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परम पिता ब्रह्मा से पूछी तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महादेव सौ कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं, उतना ही एक नीलकमल चढ़ाने पर होते हैं. ऐसे ही एक हजार नीलकमल के बराबर एक बेलपत्र और एक हजार बेलपत्र चढ़ाने के बराबर एक समीपत्र का महत्व होता है. सावन का महीना शिवभक्तों के लिए खास होता है. शिवभक्त कांवरियों में जल लेकर शिवधाम की ओर निकल पड़ते हैं. शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए लोग बोल बम के नारे लगाते घरों से निकलते हैं. शिवभक्ती में लीन कावड़िये भगवा वस्त्र धारण कर शिवालयों में जाते हैं. शिव के प्रति कावरियों की भक्ति भावना देखते ही बनती है. इस माह में चारों ओर बोल बम की गूंज सुनाई देने लगती है. कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन शिवजी पर गंगाजल चढाने से सात जन्मों के पाप मिट जाते हैं. महाशिव रात्रि के दिन गंगाजल चढ़ाने के लिये कावड़िए एक दो दिन पहले ही गंगा जी तक पहुंच जाते है और फिर कांवर लेकर पैदल ही अपने अपने गंतव्य की ओर चल पड़ते हैं. फिर महाशिव रात्रि को शिवजी पर गंगाजल चढ़ा उन्हें प्रसन्न करते हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

अंतर्कलह से जूझ रही सपा

समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह मिशन 2014 फतह करने के लिए कमर कसे हुए हैं. उनकी मंशा है कि विधानसभा की तर्ज पर ही वह लोकसभा में चुनाव का ऐसा प्रबंधन कर दें कि दूसरे दल कुछ न कर पाएं.

अपनी महत्वाकांक्षा के तहत मुलायम सिंह बैठक दर बैठक कार्यकर्ताओं एवं उम्मीदवारों को जीत की घुट्टी पिलाते रहे हैं. पर अचानक उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार ने उनके इस किए पर पानी फेर दिया है. उनके कई विधायकों में मंत्री न बन पाने की कुंठा घर कर गई है. कुछ तो बगावत पर ही उतर आए. मंत्री न बन पाने के कारण ही देवरिया के सपा विधायक शाकिर अली बगावत पर उतर आए और पुतला जलाकर अपना रोष प्रकट किया. गाजीपुर लोकसभा प्रत्याशी बनने की चाहत रखने वाले इसी तरह हाल ही में विधानसभा विधायिका शदाब फातिमा के समर्थकों ने भी किया. उनके मंत्री न बनने के कारण समर्थकों ने सपा नेतृत्व के विरोध में नारे लगाए और पुतला फुंका.

अब समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह सतह पर आती दिखने लगी है. पूर्वांचल में प्रत्याशियों के चयन को लेकर उठापटक चल रही है. किसी को उम्मीदवार न बन पाने की पीड़ा है तो किसी को अचानक हटा दिए जाने का गुस्सा है. किसी को यह मलाल है कि उनके मनमुआफिक प्रत्याशी नहीं है. तमाम जद्दोजहद से सपा प्रमुख जूझ रहे हैं. वह सबको खुश नहीं कर पा रहे हैं. पार्टी में गुटबाजी पनप रही है. एक ओर गाजीपुर सीट के लिए विजय मिश्र दावेदार हैं, वहीं दूसरी ओर हाल ही में पार्टी में शामिल बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी को लोकसभा प्रत्याशी बनने की ललक है, क्योंकि कुशवाहा का इस क्षेत्र में जातीय दबदबा माना जाता है. यहां से पार्टी के वर्तमान सांसद राधे मोहन सिंह उम्मीदवार हैं. इसी तरह सलेमपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद स्व. हरिकेवल प्रसाद के बेटे ने दावेदारी ठोकी है, महाराजगंज लोकसभा सीट के प्रत्याशी पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह को लेकर विरोध है, क्योंकि अखिलेश के छोटे भाई मुन्ना सिंह कांग्रेस से विधायक हैं. कोठी पर कांग्रेस और सपा के झंडे लगे हैं. आजमगढ़ सीट पर प्रत्याशी को लेकर काफी उठापटक जारी है. पार्टी ने पंचायती राज मंत्री बलराम यादव को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन क्षेत्रवासियों की सपा प्रमुख के छोटे बेटे प्रतीक यादव का नाम आने से वे पीछे हट गए. पार्टी नेतृत्व ने इस बीच हवलदार यादव का नाम घोषित कर दिया है, लेकिन इस सीट के लिए ऊहापोह की स्थिति अभी भी बरकरार है कि अंतिम क्षणों में असली प्रत्याशी प्रतीक यादव या हवलदार यादव में से कौन होगा? पडरौना सीट भी गले की हड्डी बन गई है, जहां से पूर्व सांसद बालेश्वर यादव प्रत्याशी बनने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं.

बहरहाल, सपा नेतृत्व लोकसभा के चुनावी महासमर में कुदने से पहले ही अपने प्रत्याशियों को कसौटी पर पूरी तरह कस रही है, लेकिन कसौटी पर कसने के कारण ही कई प्रत्याशियों को अपनी दावेदारी से हाथ धोना पड़ रहा है. ऐसे में उनका विरोध स्वाभाविक है. अब देखना यह है कि इस विरोध को सपा नेतृत्व किस तरह संभाल पाता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

सरकारी योजनाओं का सच

ग़रीबों को कोई लाभ नहीं

शिवनाथ चतुर्वेदी

सूदखोरी पर लगाम लगाने और गरीबों को आसानी के साथ कर्ज मुहैया कराने की भारत सरकार की योजना को झटका लग रहा है. गरीबों और भूमिहीन किसानों के लिए बैंकों में संचालित जनरल क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बैंक काफी उदासीन है. इन दोनों योजनाओं में चालू वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों का आंकड़ा 1000 से भी कम है, जबकि जिले में नौ लाख से अधिक परिवार गरीब भूमिहीन हैं. गरीबों को धन के लिए सूदखोरों और महाजनों के सामने हाथ न फैलाना पड़ें, इसके लिए केंद्र सरकार ने खास तौर से भूमिहीन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य गरीबों को जनरल क्रेडिट कार्ड से कर्ज देने के लिए बैंकों ने योजनाएं चलाई, पर जिले में इन योजनाओं पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है. इससे जिले में गरीबों के लिए बैंकों से कर्ज पाना सपने की तरह है. इतना ही नही बैंकों में लोगों योजनाओं के बारे में समुचित जानकारी तक नहीं दी जाती है. यही कारण है कि गरीबों को बैंक शाखा में जाने से न केवल डर लगता, बल्कि बात तक नहीं रख पाते. बैंकों की इस कार्य शैली से सरकार और आरबीआई की मंशा को झटका लग रहा है. जिले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐक्सिस बैंक, जिला सहकारी बैंक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक आदि की शाखाएं चलती हैं. जनरल क्रेडिट कार्ड के रूप में गरीबों को स्वरोजगार के लिए 25 हजार रुपये तक का ऋण देने की व्यवस्था है. वहीं भूमिहीन किसानों को जेएलजी बनाकर किसान क्रेडिट कार्ड देने की जिम्मेदारी है, जिससे गरीब भी जीवन में आगे बढ़ सकें. लेकिन इन योजनाओं के प्रति बैंक उदासीन है. इससे गरीबों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है. इधर एलडीएम अभय कुमार सिन्हा ने माना कि कुछ बैंकों ने इन योजनाओं में काम किया है, लेकिन पूरी तरह से काम नहीं हो पा रहा है. जल्द ही इस दिशा में काम होगा और ज्यादा पात्रों को लाभान्वित किया जाएगा. ■

रमज़ान का महीना और इफ़्तार की दावतें

रमजान के पवित्र महीने में इफ्तार की दावतों की बाज़ार गर्म रहता है. सियासी जगत की बड़ी-बड़ी हस्तियों से लेकर, क्षेत्रीय स्तर के सियासी लोग इफ्तार की दावतों के बड़े-बड़े आयोजन करते हैं. इसके अलावा, कुछ नये जमाने के नये व्यवसायों से जुड़े लोग तालीम व्यवसायी बीमा संचालक से लेकर कुछ सरकारी हुक्मरान भी इन दावतों के आयोजनों में बढ़-चढ़ कर शिरकत करते हैं. इन दावतों के आयोजन में बाकायदा निमंत्रण पत्र बांटे जाते हैं और सभी वर्गों के लोगों को निमंत्रित किया जाता है. खबरनवीसों को विशेष तरजीह दी जाती है. जिस दावत का आयोजन सियासी हस्तियां कर रही हों, सियासी जमात का जमावड़ा हो और खबर न बने, तस्वीरें न छपें, यह मुमकिन नहीं. दूसरे दिन अखबार के मुख्य पृष्ठ पर सनसनी न बनें तो, पूरे आयोजन का जायका ही खराब हो जाता है. हालात तो यहीं तक हैं, पर आजकल दावतों के दौर का बाजार काफी गर्म है. ऐसा होना लाजिमी भी है, क्योंकि 2014 की सियासी जंग की रणभेरी जो बज चुकी है. ऐसे में कोई भी सियासतदार पीछे कैसे रह सकता है. अगर इन दावतों पर गौर फरमाया जाए तो नतीजा यह निकलता है कि लगभग 95 प्रतिशत ऐसे लोग इन दावतों में शरीक होते है, जो रोजा नहीं रहते. अधिकांश हजरात तो दूसरें धर्मों के होते हैं, लेकिन एक खासियत उनमें जरूर होती है, वे सियासी नजरिये से महत्वपूर्ण अवश्य होते हैं.

इस्लाम धर्म में इफ्तार की दावतों के आयोजन का मकसद कुछ और ही है, लेकिन इस सियासत ने इसका चेहरा ही बदल दिया है. रमजान का पाक महीना मुसलमानों के लिए बहुत ही खास होता है. अमीर-गरीब, छोटे-बड़े सभी की ख्वाहिश इस पाक महीने में पूरा महीना रोजा रख, परवरदीगार को अपनी श्रद्धा अर्पित करने एवं अच्छी सेहत नवाजनें के लिए इबादत करने की होती है. वह अल्लाहताला को उसके रहमो करम के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता है, लेकिन आज जो हालात है, इसमें एक माह तक बिना खाये-पिये मेहनत-मजदूरी करने के साथ रोजा रख पाना बड़ा ही कठिन होता है. इसकी कमाई से एक व्यक्ति नहीं पूरे एक कुनबे की परवरिश होती है. इसके अलावा, जो लोग खुदा न खास्ता बीमार हैं या दुर्बल हैं, उनके लिये तो रोजा खोलने तक की व्यवस्था करना असंभव है. रोजा खोलने का वक्त नीयत है जो लोग किसी कारणवश सफर पर है, यदि वे समय पर घर नहीं पहुंच पाये, तो उनको सफर में ही रोजा खोलना पड़ता है. बहुत से परिवार ऐसे भी है, जिनमें एक व्यक्ति की कमाई से पूरे कुनबे का पेट भरता है. कुछ मुसलमान भाई ऐसे पेशे से जुड़े होते है, जिन पेशों में हाड़तोड़ मेहनत पड़ती है. इफ्तार की दावतों का मकसद यही होता है कि अमीर लोग ऐसी दावतों का आयोजन करें, जिसमें आस-पास के मेहनत कश, लाचार, गरीब, दुर्बल, बेसहारा एवं दीन-हीन रोजगार भी परवरदीगार को अपनी इबादत पेश कर सकें. गरीबी-लाचारी अथवा सफर में होने की वजह मात्र से किसी रोजदार का रोजा ना खराब हो. उसे इस बात का मलाल न रह जाए कि इस पवित्र रमजान के महीने में गरीबी की वजह से उनका रोजा ख़राब न हो जाए. ज़रूरत धर्मों से ज़्यादा उनका मर्मों को समझने की है और इफ्तार की दावतों का धार्मिक मर्म यह है कि अभाव में किसी दावतें उड़ाने की जो रोजा ही नहीं है. अगर किसी क्षेत्र में किसी भी रोजादार का रोजा टूटता है तो इस क्षेत्र में कोई अमीर मुसलमान नहीं है या साधारण लोगों में आपसी प्रेम-सद्भाव नहीं है या कोई धर्म निरपेक्ष हिंदू, सिख, ईसाई नहीं है अथवा कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म तो जानता है, लेकिन धर्म का मर्म नहीं जानता. अगर इफ्तार की दावतें करनी है तो उन्हें रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, मुसाफिरों खानों, गरीबों की बस्तियों में करो, जिससे किसी गरीब, लाचार अथवा मुसाफिर का रोजा ना टूटने पाये. ■

-सुमन वी. आनंद

औद्योगिक गलियारा बनाएगा यूपी को ख़ुशहाल

दर्शन शर्मा

प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं. यूपी के बेरोजगारों के लिए खुशी की बात यह है कि अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक गलियारा यूपी से होकर गुजर रहा है, जो प्रदेश में उद्योगपतियों को आकर्षित करने वाला है. प्रदेश सरकार इसके लिए बिजली और जमीन वगैरह सहूलियतें जुटाने में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग करना चाहती है. यूपी सरकार का दावा है कि इस काम में आने वाली समस्त अड़चनों को हर हाल में दूर कर लिया जाएगा. उत्तर प्रदेश का अधिकतर भाग औद्योगिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, यहां प्रदेश सरकार छह औद्योगिक निवेश जोन बनाना चाहती है. इनमें मुख्य जिले वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, अलीगढ़ और सहारनपुर आते हैं. प्रदेश सरकार की मंशा है कि केंद्र सरकार इन परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए करों में छूट और अन्य सुविधाएं दे. इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा खाका तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया है. औद्योगिक आयुक्त आलोक रंजन का कहना है कि औद्योगिक निवेश जोन के लिए प्रदेश सरकार अब कोष जुटा रही है. प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इच्छा जाहिर की है कि वह निवेश जोन की मास्टर प्लानिंग के लिए सहायता विश्व बैंक से सस्ता कर्ज दिलाने, राष्ट्रीय निर्माण नीति के तहत सभी सुविधाएं देने, बड़े उद्यमियों को निवेश जोन में अपनी यूनिट लगाने के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराए. ■

जब राहुल प्रियंका बने परीक्षक

राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं. मिशन 2014 में जीत हासिल करने के लिए, वह इन दिनों संगठन को चुस्त-दुरूस्त करने में लगे हैं...

प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने ब्लॉक तथा नगर अध्यक्षों के चुनाव की उम्मीदवारी के लिए चयनित उम्मीदवारों की कड़ी परीक्षा ली. अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी के दो दिवसीय दौरे पर आए राहुल और प्रियंका ने अपने भ्रमण के पहले दिन अमेठी में कांग्रेस के 17 ब्लॉक अध्यक्षों तथा पांच नगर अध्यक्षों के चुनाव के लिए जारी प्रक्रिया के तहत 10 विकास खंडों के अध्यक्ष पद के कुल 40 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया. साक्षात्कार में राहुल और प्रियंका ने कांग्रेस के इतिहास, पंचायती राज, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की प्रमुख योजनाओं, मनरेगा के फायदे, संगठन के विस्तार के तरीकों के बारे में कई सवाल पूछे. संग्राम पुर ब्लॉक अध्यक्ष पद के दावेदार सभाजीत शुक्ल ने बताया कि साक्षात्कार के दौरान राहुल कम और प्रियंका ज्यादा सवाल कर रही थीं. सवालों की शुरुआत इस प्रश्न से हुई कि पिछले विधानसभा चुनाव में अमेठी में कांग्रेस क्यों हारी और क्यों कमजोर हुई. राहुल और प्रियंका ने दावेदारों से संगठन की मजबूती से जुड़े सवाल किए. प्रियंका ने पूछा कि जिस पद के लिए तुम उम्मीदवार हो, इस पर अगले छह महीनों में कितना खरा उतरोगे. प्रियंका और राहुल को मालूम है कि इस बार का लोकसभा चुनाव काफी मुश्किल है. पिछले चुनाव वर्ष 2009 में रायबरेली और अमेठी की दस विधानसभा सीटों में छह पर कांग्रेस के विधायक काबिज थे. इन दोनों क्षेत्रों से महज दो विधायक ही अपनी जीत दर्ज कर सके. जहां अमेठी राहुल के लिए अहम माना जा रहा है, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के लिए रायबरेली में विजय पताका फहराना जरूरी है. अगर इन सीटों पर कांग्रेस को कम वोट मिले, तो पूरे देश में इसका असर पड़ेगा. लिहाजा, राहुल और प्रियंका इससे बचने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं. अब देखना यह है कि राहुल और प्रियंका की तैयारियां कितनी कारगर होंगी. मालूम हो कि प्रियंका विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह दौरे करती थीं और कार्यकर्ताओं से कई बार मिली थीं. मतदाताओं से मिलने के लिए उन्होंने गांवों में अमेठी और रायबरेली के गांवों की खाक छानी थी, लेकिन दोनों क्षेत्रों से मात्र दो विधायक विजयी हुए थे. ■

बलिया विकास प्रशिष्ट प्रकाशन के शुभ अवसर पर जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

भुवाल सिंह
सहायक आबकारी आयुक्त
जनपद-बलिया

देहरादून

ठोकरें खाने को मजबूर टिहरी बांध विस्थापित

टिहरी बांध को बने एक दशक से भी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन हज़ारों विस्थापित परिवार आज भी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं. उनकी समस्या सुनने को कोई भी तैयार नहीं है. आख़िर कहां जाएं ये विस्थापित...

जबर सिंह वर्मा

तमाम विरोधों को दरकिनार कर 40 साल पहले एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध की आधारशिला रखी गई थी. आज आलम यह है कि सदियों पुराने टिहरी शहर समेत आसपास के दर्जनों गांव बांध की झील में समा चुके हैं. तमाम विरोधों के बावजूद हजारों ग्रामीणों को उनके पूर्वजों की देखी-परखी माटी से दूर कर दिया गया. समूचे देश की विद्युत जरूरतों को पूरा करने के नाम पर लाखों लोगों के गांव, खेत और खलिहान छीन लिए गए. टिहरी बांध को बने अब एक दशक से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन देश की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले हजारों विस्थापित परिवार आज भी दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं. विस्थापन का दंश झेल रहे परिवार हों या झील के आसपास बसे प्रभावित ग्रामीण, किसी की समस्या सुनने को कोई भी तैयार नहीं है.

बांध विस्थापितों को ऋषिकेश, बंजारावाला, पशुलोक, भानियावाला, डाईवाला, पथरी समेत दून और हरिद्वार से लगे दुर्गम और बिहड़ क्षेत्रों में बसाया गया था, लेकिन वहां भी नैसर्गिक अधिकार छोड़कर आए इन विस्थापितों को भूमि के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है. टिहरी में परंपरागत ढंग से पीढ़ी-दर-पीढ़ी बतौर राजस्व गांव के निवासी होने के जो अधिकार उन्हें मिल रहे थे, वह भी छूट गए. विस्थापित जगहों पर उन्हें दी गई जमीन का मालिकाना हक अब तक नहीं मिल पाया है. जो भूमि मिली, उसे भी दलालों, भू-माफियाओं, नेताओं-अफसरों ने खुर्द-बुर्द करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. विस्थापन के समय गरीबों, दलितों की तो सुनी ही नहीं गई. जिसे जहां मर्जी आई, वहां उन्हें अनुपयोगी भूमि देकर पटक दिया गया. अब उत्तराखंड सरकार भी उनके हक-हकूक दिलाने में रुचि नहीं दिखा रही, न ही कोई आवाज बांध प्रशासन के समक्ष उठाई जा रही है.

बांध निर्माण के बाद विस्थापितों और प्रभावितों को रोजगार सृजन के लिए झील क्षेत्र में नौकायन, पर्यटन, मत्स्य पालन समेत आजीविका जुटाने के कई प्रावधान रखने के सब्जबाग दिखाए गए थे, लेकिन झील बनने के 10 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ. उल्टे आसपास के क्षेत्र की दुश्वारियां और बढ़ गई हैं. विस्थापित पराश्रित बनकर रह गए हैं. पुरानी टिहरी को उजाड़कर बेढंगी और अक्सर सूनसान रहने वाली नई टिहरी मिली. हां, बांध निर्माण के चलते उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बांध प्रशासन के लिए जरूर आलीशान कालोनियां बन गई हैं. टिहरी बांध विस्थापितों के लिए लगातार कार्यरत माटू जन संगठन के समन्वयक विमल भाई का कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे एनडी जयाल और शेखर सिंह बनाम भारत सरकार व अन्य मुकदमे में बांध प्रभावितों के विषय लगातार उठाए गए हैं. आज जब कांग्रेस की सरकार राज्य और केन्द्र दोनों जगह है, तो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यह कार्य क्यों नही करवा पा रहे हैं, जबकि वह सर्वोच्च न्यायालय में प्रभावितों के मुकदमों के हर फैसले का श्रेय लेते रहे हैं. उन्होंने चुनाव से पहले हर बार विस्थापितों की समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा की. यह बात अलग है कि चल रहे मुकदमों में उन्होंने कभी मदद नहीं की.

विस्थापितों के लिए भूमि आवंटन करने में खेल शुरू से लेकर अब तक लगातार चल रहा है. पिछले कुछ महीनों में ही टिहरी बांध के 33 विस्थापित परिवारों को पुनर्वास के नाम पर सभी मानकों को ताक पर रख कर ऋषिकेश, अजबपुर और देहराखास स्थित पॉश इलाकों में सेटिंग-गेटिंग के तहत आधा-आधा एकड़ भूखंड आनन-फानन में आवंटित करवा दिए गए. यह आवंटित भूमि टीएचडीसी के अधीन थी, जो हरित पट्टी घोषित है. बावजूद इसके, नियमों के विपरीत पुनर्वास विभाग ने इसे विस्थापितों को आवंटित करवा दिया. बात यहीं नहीं रूकी. 40 से 45 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत वाली इस जमीन की रजिस्ट्री जिस दिन टिहरी विस्थापितों के नाम हुई, उसी दिन भू-माफियाओं के नाम भी ट्रांसफर हो गई. उनमें कई विस्थापित अनुसूचित जाति के भी थे, जिनकी जमीन बिना पंचायत, डीएम की अनुमति के खरीदी-बेची नहीं जा सकती. मगर सत्ता की हनक के सामने सब कुछ संभव हो गया. बानगी के तौर पर ऋषिकेश के तल्ला उप्पु के सबल सिंह-पुत्र भावों सिंह, अब्बल सिंह-पुत्र भावों सिंह को 11 फरवरी, 2013 को आधा-आधा एकड़ भूखंड आवंटित हुआ. दिलचस्प यह है कि सबल सिंह को आवंटित यह भूखंड इसी दिन जितेंद्र सिंह-पुत्र शूरवीर सिंह और केवल कृष्ण-पुत्र एचआर लांबा निवासी ऋषिकेश को 35 लाख 64 हजार और अबल सिंह का भूखंड राकेश सिंह-पुत्र धर्मसिंह निवासी ऋशिकेश और हिमांशु, निवासी टिहरी को बेच दिया गया. इन विस्थापितों को सोची-समझी रणनीति के तहत पॉश इलाके में भूमि आवंटित कराई गई. इस पूरे खेल में टिहरी से सांसद का चुनाव लड़ चुके मुख्यमंत्री के पुत्र साकेत बहुगुणा समेत कुछ कांग्रेस विधायकों और नेताओं के नाम भी खासे चर्चा में रहे. हालांकि तमाम हंगामे के बावजूद जमीन, माफिया निगल गए और विस्थापित हाथ मलते रह गए. पूरे प्रकरण में सिस्टम आज भी मजाक बनकर रह गया है. बहुगुणा राज में बेशकीमती जमीनें खुर्द-बुर्द कर करोड़ों के वारे-न्यारे करने का यह खेल लंबे समय से बेरोकटोक चला आ रहा है. ■

बांध विस्थापितों को ऋषिकेश, बंजारावाला, पशुलोक, भानियावाला, डाईवाला, पथरी समेत दून और हरिद्वार से लगे दुर्गम और बिहड़ क्षेत्रों में बसाया गया था, लेकिन वहां भी नैसर्गिक अधिकार छोड़कर आए इन विस्थापितों को भूमि के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है. टिहरी में परंपरागत ढंग से पीढ़ी-दर-पीढ़ी बतौर राजस्व गांव के निवासी होने के जो अधिकार उन्हें मिल रहे थे, वह भी छूट गए.

feedback@chauthiduniya.com

बलिया विकास प्रशिष्ट प्रकाशन के शुभ अवसर पर नगर पालिका परिषद बलिया अपने नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपेक्षा/अपील करती है कि

- यह नगर आपका है इसे स्वच्छ रखने में सहयोग करें एंव कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें
- नगर की नालियों, सड़कों पर अतिक्रमण न करें तथा नालियों में कूड़ा आदि न डालें.
- अपने परिवार में हुए जन्म-मृत्यु का पंजीयन समय से अवश्य कराएं.
- सड़े-गले (बासी) खाध पदार्थ की बिक्री न करें, न होने दें.
- नगर पालिका के समस्त करों का भुगतान सममय से करें.
- प्रदूषित जल का सेवन न करें.
- पॉलीथिन का प्रयोग वर्जित है, अतएव पॉलीथिन का प्रयोग कदापि न करें. अन्यथा दंड (जुर्माना)के भागी बन सकते हैं.
- जल ही जीवन है. जल का आवश्यकतानुसार उपयोग करें.
- अपने शहर को साफ-सुथरा, ग्रीन बलिया-क्लीन बलिया बनाने में सहयोग करें.
- बिना नक्शा पास कराए भवन का निर्माण न कराएं.

स्वच्छ - बलिया, स्वस्थ-बलिया , सुन्दर- बलिया

संतोष कुमार मिश्र
अधिशासी अधिकारी

लक्ष्मण गुप्ता
अध्यक्ष प्रतिनिधि

श्रीमती साधना गुप्ता
अध्यक्ष

समस्त सभासदगण
नगर पालिका परिषद बलिया

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

अयोध्या में वैसे तो प्रति वर्ष चौरासी कोसी, चौदह कोसी और पांच कोसी परिक्रमाएं धार्मिक रूप से होती आ रही हैं, लेकिन इस बार राम मंदिर निर्माण के लिए विहिप एक नई चौरासी कोसी और पांच कोसी परिक्रमा कराने जा रही है. इसकी राष्ट्रव्यापी तैयारियां चल रही हैं.

राम मंदिर आंदोलन

अखिलेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती

भाजपा, विहिप और आरएसएस ने राम मंदिर आंदोलन को चुनावी मुद्दा बनाने की मंशा जाहिर कर दी है. मंदिर मुद्दा उत्तर प्रदेश की सपा नेतृत्व वाली अखिलेश यादव सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है. अब देखना यह है कि सन् 1990 की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार की तर्ज पर, क्या अखिलेश सरकार बिना मुलायम सिंह की मर्जी के अयोध्या में पत्ता खड़कने का ऐलान करेगी या नहीं?

राकेश कुमार यादव

भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन को चुनावी मुद्दा बनाने की मंशा जाहिर कर दी है. राम मंदिर की नैय्या के सहारे मिशन 2014 को फतह करने का मंसूबा भाजपा और विहिप ने ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) ने भी अलापना शुरू कर दिया है. कारसेवकपुरम में इस बार राम मंदिर निर्माण को धार देने के लिए नई चौरासी कोसी परिक्रमा के नाम पर बैठकों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मुद्दे को लेकर आरएसएस भी खुलकर सामने आ गई है. एक बार फिर अयोध्या की कारसेवा की तर्ज पर पुन: देश के हिंदुओं को लामबंद कर अयोध्या लाने का प्रयास किया जा रहा है. राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश की सपा नेतृत्व वाली अखिलेश यादव सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है. अब देखना यह है कि सन् 1990 की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार की तर्ज पर क्या अखिलेश सरकार बिना उनकी मर्जी के अयोध्या में पत्ता खड़कने का ऐलान करेगी या नहीं? यह भविष्य के गर्भ में है.

अयोध्या में वैसे तो प्रति वर्ष चौरासी कोसी, चौदह कोसी और पांच कोसी परिक्रमाएं धार्मिक रूप से होती आ रही हैं, लेकिन इस बार राम मंदिर निर्माण के लिए विहिप एक नई चौरासी कोसी और पांच कोसी परिक्रमा कराने जा रही है. इसकी राष्ट्रव्यापी तैयारियां चल रही हैं. विहिप और संघ के साथ राम मंदिर मुद्दे को लेकर चौरासी कोसी परिक्रमा से शुरू हो रहे आंदोलन को लेकर राजनीतिक बैठक में भाजपा नेताओं को शामिल होने का आदेश प्रदेश नेतृत्व से मिला है. कारसेवकपुरम के वेदव्यास कथा मंडप में हुई बैठक में चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग के 6 जिलों से जुड़े कद्दावर स्थानीय नेता के अलावा विहिप संरक्षक अशोक सिंघल ने शामिल होकर राम मंदिर निर्माण की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से सहयोग मांग कर चौंकाया ही नहीं, बल्कि इस बात का संकेत भी दे दिया है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में तत्कालीन मुलायम सरकार का सहयोग था. 19 जुलाई को हुई बैठक में अशोक सिंघल ने कहा कि 25 अगस्त से 13 सितंबर तक चौरासी कोसी परिक्रमा वैसे तो विशुद्ध धार्मिक आंदोलन है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि इस आयोजन में वह साथ खड़े हों. उन्होंने सूबे की समाजवादी पार्टी सरकार से भी हर तरह के सहयोग की उम्मीद जताई है. उन्होंने कांग्रेस से भी सहयोग की उम्मीद जताई और कहा कि कांग्रेस, भाजपा की पुरानी हमसफर है. आपको बता दें कि जिस समय विवादित ढांचा ध्वस्त किया जा रहा था, उस समय दिल्ली में भाजपा के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव समेत दोनों पार्टियों के कई शीर्ष नेता चाय की चुस्कियों के साथ लाइव प्रसारण देख रहे थे. अशोक सिंघल के बयान ने पुराने दिनों की सच्चाई की भी पुष्टि कर दी है.

बताते चलें कि विश्व हिन्दू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल राम भक्तों के आक्रोश को भड़काने और उन्हें अयोध्या लाने के लिए स्वयं मैदान मे उतर गए हैं. उन्होंने अपने अयोध्या प्रवास के दौरान संत समाज से गोपनीय बैठक कर मंदिर आंदोलन की रणनीति को तय कर लिया है. उन्होंने ऐलान किया है कि 25 अगस्त से 13 सितम्बर 2013 के बीच अयोध्या की चौरासी कोसी परिक्रमा को सफल बनाने के लिए देशव्यापी जन–जागरण अभियान शुरू किया जाएगा. परिक्रमा में संत समाज के साथ चालीस प्रांतों के श्रद्धालु 150 के जत्थे में शामिल होंगे और प्रतिदिन परिक्रमार्थी 15 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे. दूसरी संतों की टोली व प्रांतो के श्रद्धालु प्रत्येक दिन हिस्सा लेंगे. 23 सितम्बर से 14 अक्टूबर के मध्य अयोध्या की अनवरत परिक्रमा भी शुरू की जाएगी और 18 अक्टूबर को सरयू तट पर संकल्प सभा कर मंदिर आन्दोलन का शंखनाद किया जाएगा. विहिप संरक्षक ने कहा है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बंगाल की जनता धर्मशील है, लेकिन वहां नेतृत्व का अभाव है. उन प्रदेशों में जागरण के लिए प्रमुख संतो की अगुवाई में कार्यक्रम तय किया जाएगा.

गौरतलब है कि श्रीराम जन्म भूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास के पट्टाभिषेक अमृत महोत्सव, जो कि 18 जून से 22 जून तक मनाया गया, में राम मंदिर निर्माण आन्दोलन की सार्वजनिक घोषणा की गई है. महोत्सव में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी मिशन 2014 की कमान संभालने वाले नरेंद्र मोदी को भी सलाह दे डाली कि अयोध्या आकर बिना रामलला के दर्शन किए चुनावी वैतरणी पार करना आसान नहीं होगा. वहीं फायर ब्रांड नेता प्रवीण भाई तोगड़िया ने यहां तक कह डाला कि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता जापान के सोलार पार्क से नहीं, बल्कि अयोध्या से होकर गुजरता है. उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि हम ऐसी सरकार बनाएं, जो 20 करोड़ की आबादी की बजाय 100 करोड़ हिन्दुओं की आबादी की चिन्ता करे. अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हिन्दू समाज का अधिकार है और इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता. 77 एकड़ के अधिग्रहित परिसर में मंदिर के अतिरिक्त कोई अन्य स्मारक किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा. उन्होंने कहा कि भाजपा ने हिन्दू समाज का विश्वास खोया है. अब इसे संसद में राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने का वचन देना होगा, तभी उन पर दोबारा विश्वास किया जाएगा.

विहिप के संरक्षक अशोक सिंघल ने मंदिर निर्माण आन्दोलन को तेज करते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के बाद रामलला की जन्मभूमि तय हो चुकी है. अब संसद को तय करना है कि रामलला को टेंट से भव्य मंदिर में कब विराजमान किया जाएगा. उन्होंने केन्द्र सरकार को चेताया कि आगामी मानसून सत्र में संसद ने राम जन्म भूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को लेकर निर्णय नहीं लिया, तो संतों के आदेश पर विश्व हिन्दू परिषद अयोध्या में बड़ा आन्दोलन शुरू करेगी. संतों द्वारा प्रस्तावित अयोध्या की चौरासी कोसी सांस्कृतिक सीमा में किसी भी तरह किसी अन्य धर्म का धार्मिक स्थल नहीं बनने दिया जाएगा. अयोध्या के वेद मंदिर में संत समिति की बैठक में समिति अध्यक्ष महंत कन्हैया दास रामायणी ने जो वक्तव्य दिया है, वह हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है. उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के लिए तिल–तिल कर मरने से अच्छा है कि मंदिर निर्माण के लिए हम अपनी बलि देकर लोक–परलोक दोनों सुधार लें. रामानन्दाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य का वक्तव्य दो कदम और आगे है. वह कहते हैं कि संसद हमारी पीड़ा को समझ ले, अन्यथा राम भक्तों का आक्रोश भड़का, तो धर्मनिरपेक्ष ताकतों की चूलें हिल जाएंगी. सिक्ख समाज के ग्रंथियों ने भी राम मंदिर आन्दोलन के सुर में सुल मिलाना शुरू कर दिया है.

गुरुद्वारा ब्रम्हकुंड के मुख्य ग्रन्थी ज्ञानी गुरुजीत सिंह ने कहा है कि सिक्ख धर्म का जन्म ही हिन्दुत्व की रक्षा में बलिदान के लिए हुआ था और हम ऐसा करना अपना सौभाग्य मानेंगे. वहीं अमृत महोत्सव के बहाने विश्व हिन्दू परिषद के अन्तर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉ. प्रवीण भाई तोगड़िया, योग गुरु बाबा रामदेव, जगत्गुरु राम भद्राचार्य, भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ, भाजपा राज्यसभा सांसद विनय कटियार सहित अनेक धर्माचार्यों ने राम मंदिर निर्माण को लेकर कई गोपनीय बैठकें कर चुके हैं. इन बैठकों के दौरान कारसेवकपुरम में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख लोगों का आना–जाना बना रहा. पांच दिनों तक वेद मंदिर, सियाराम किला, हिन्दू धाम, श्याम सदन और चन्द्रहरि मंदिर में साधु–संतो की गोपनीय बैठक कर उन्हें हिन्दू समाज को आन्दोलन के लिए तैयार करने की रणनीति समझायी गई. उक्त बैठकों के अतिरिक्त भाजपा के प्रदेश प्रभारी अमित शाह ने 6 जुलाई को कारसेवकपुरम में कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी की बैठक की. बैठक के पूर्व वह रामलला व हनुमानगढ़ी पर दर्शन करने गए, जहां पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की प्राथमिकताओं में सुशासन के साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण शामिल है. उन्होंने कहा कि पार्टी देश में सुशासन के साथ राम मंदिर निर्माण की ओर आगे बढ़ना चाहती है. यदि जनता ने हमें इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी, तो रामलला का भव्य निर्माण होने से कोई रोक नहीं पाएगा.

बहरहाल, विहिप रणनीति के मद्देनजर अयोध्या के लिए सर्वानुमति का प्रयास कर रहे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति पालोक बसु से जुड़े लोगों ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है. पालोक बसु का कहना है कि कानूनन यदि किसी मुद्दे पर इस क्षेत्र के पांच हजार लोग एक राय रखते हैं, तो कोर्ट और सरकार को सुनना पड़ता है, इसीलिए वह हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं. हमारी मंशा है कि मंदिर गर्भगृह स्थल पर ही भव्य तरीके से बने. मुसलमान पास की जमीन का अपना दावा छोड़ेंगे, मगर उन्हें अधिग्रहित 77 एकड़ भूमि में ही पश्चिमी छोर पर सटे भूमि के पास कोर्ट की अनुमति से मस्जिद का निर्माण कराने दिया जाए.

लब्बोलुबाब यह है कि एक बार फिर कारसेवा आन्दोलन की तर्ज पर हिन्दू धर्माचार्य और नेता अयोध्या में ज्वालामुखी की स्थिति खड़ा करना चाह रहे हैं. अगस्त माह में देश भर के लाखों हिन्दुओं का रुख अयोध्या की ओर मोड़कर भाजपा के मिशन 2014 को सफल बना दिल्ली की सत्ता पर पुन: कब्जा करने की मंशा है. मिशन सफल हो या न हो, लेकिन यह तय है कि एक बार फिर अयोध्या और उसके आसपास के बाशिंदों को भय और असुरक्षा के साये से गुजरना पड़ेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120–6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627366